



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण,
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. ७२]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल १५, १९७८/चैत्र २५, १९००

No. 72]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1978/CHAITRA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न वी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक सम्परण और सहकारिता मन्त्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(आयात व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, १५ अप्रैल, १९७८

सार्वजनिक सूचना

सं. २५-आई०टी०सी० (भी०एन०) /७८/ निसिल सं. आई०पी०सी०/३९/१३/
७६—१९७७-७८ के लिए उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत
वित्तयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों को जारी करने के सबध में लागू होने वाले नियम तथा शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट १ तथा २ में वी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचिस की जाती है।

सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट I

उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के अन्तर्गत निजी क्षेत्र अयातों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए शर्तें

खण्ड 1— सामान्य

नीवरलैंड्स इवेस्टीरिंग्स वीक थीर आटिकलिंग्स लैन्डन एन० वी० द्वारा प्रवान किए गए १९७७-७८ के लिए उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट को विकासशील वेशों के लिए खोल दिया गया है। तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन वित्तयुक्त किए जाने वाले माल एवं पर्याप्त वस्तुएं एवं इससे सबध

आनुषंगिक सेवाएं नीवरलैंड्स से आयात की जा सकती हैं और परिशिष्ट 'क' के रूप में "नीवरलैंड द्वारा द्विपक्षी विकास अध्ययन के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिकारिता के लिए मार्गदर्शन"। सूची में सन्मिलित सभी देश (प्रत्यक्ष-१) इस क्रेडिट के अन्तर्गत "पात्र स्रोत देश" होंगे। दोहरी साक्ष करारों अर्थात् जी एक एल १ २० मिलियन और जी एक एल ५४ मिलियन में प्रतिपूर्ति की अंतिम तिथि ३१-१२-१९८० होगी।

2 किन्तु पात्र से इतर स्रोत वेशों से रसायन के सबध में 10% की सीमा तक और अन्य आयातों के सबध में 20% की सीमा तक के सबधको को इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है। यदि कोई हो तो इस सबध में विशिष्ट आवेदन सविदा पूर्ण होने से पूर्व ही वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) का किए जाने चाहिए।

3 इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए पात्र स्रोत वेशों से उपर्युक्त खड़ १ (२) में सकेति सीमा से अधिक सम्परण को भयानक बनाने के लिए पात्र से चिन्ह स्रोत वेशों से माल और सेवाओं के सीमित सम्परणों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए नीवरलैंड की सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

खण्ड 2—आयात लाइसेंस जारी करना

2(1) आयात लाइसेंस १२ माल की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए लागत बीमा भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा। वैध अवधि में दूसरी के लिए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे वैध अवधि के भीतर ही

संबंध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करे जो इस मामले में ग्राहिक कार्य विभाग से परामर्श लेगा।

2(2) पक्के आवेदन नीदरलैंड में समुद्रपार संभरकों को या अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों को लागत कि बीमा भाषा/लागत तथा भाड़ा के अधार पर अवश्य दिए जाने चाहिए और आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 4 मास के भीतर ही आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। यदि पक्के आवेदन देने का निर्णय निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेंस धारी को चाहिए कि वह जैसा भी मामला हो मुख्य नियंत्रक आयात नियति को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि क्यों नहीं प्रारम्भिक वैध अवधि के भीतर ही आवेदन देने का काम पूरा हो सका और इसके ग्राहित एवं आव्याय के साथ आवेदन देने की अवधि में बृद्धि की मांग करने के लिए प्रस्ताव रखे। आवेदन देने की ऐसी अवधि में बृद्धि के लिए आवेदन पर विचार प्रत्येक मामले में पात्रता के अधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और चार मास की अवधि बृद्धि के सकते हैं। लेकिन यदि आयात जारी होने की तारीख से 8 मास से अधिक की बृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपावाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अर्थ कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) वित्त भंतालय को भेजे जाने चाहिए।

2(3) लाइसेंस पर 'उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट' अंकित होगा और यह उस सार्वजनिक सूचना की सं० का संकेत करेगा जिसके अन्तर्गत यह लाइसेंस शर्तें जारी की जाती है। प्रथम तथा द्वितीय प्रथम के लिए लाइसेंस कोड 'एम'/'एन एन' होंगे। इस लाइसेंस कोड का उल्लेख सभी पोतलवान प्रेसेंट्रों में होना चाहिए और साथ ही साथ रुपया जमा करने समय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र 'एस' में भी इसका उल्लेख होना चाहिए।

2(4) जैसे ही आयातक आयात लाइसेंस प्राप्त करता है उसे चाहिए कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ वित्त भंतालय, ग्राहिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को एक रिपोर्ट भेजें:—

- (1) आयात लाइसेंस की संख्या और निनाक
- (2) मूल्य
- (3) यदि कोई हो तो आयात लाइसेंस में संकेतित मुश्त्रा विनियम वर
- (4) वह तारीख जिस तक ग्राहिक कार्य विभाग को संविदा की प्रतियां भेजने की सम्भावना है।

खण्ड 3—क्रेडिट को पूर्ण करना

3(1) इस क्रेडिट के अन्तर्गत विस्तार के लिए पात्र संविदा का व्यूनतम मूल्य डी एफ एल-25,000/- होगा।

3(2) आयात लाइसेंस के महे केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा करने के लिए अनुमति दी जाएगी जिसके लिए आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख के तुरंत बाद ही वित्त भंतालय, ग्राहिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

3(3) माल के आयात के लिए संविदा और नीदरलैंड से सेवाओं और पात्र स्त्रोत देशों का निश्चय अनुबंध-1 में यथा उल्लिखित माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

3(4) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाएं ग्रोप-आर्टिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी:—

(क) जहां नीदरलैंड आयातों के लिए परम्परागत या केवल एक मात्र स्रोत है, या

(ख) जहां आयातों का मूल्य डी एफ एल 1.25 मिलियन से कम का है, या

(ग) जहां ऐसी कियाविधि लागू नहीं है या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच करार किसी और अधिक उचित कियाविधि के आधार पर सम्भरण के लिए संविदा पूर्ण हो जाने से पूर्व ही निपिचर रूप से तय हो जाना चाहिए।

3(5) निम्नलिखित मामलों में ग्रोपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय बोली का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं होगा:—

(क) जहां क्रेता के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मानकीकरण को बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त कारण है।

(ख) उन मामलों में जहां विषयात्रीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण सीमा संभरकों की संख्या सीमित है और क्रेता की माकिट जानकारी ऐसी है कि उससे यह आशा की जा सकती है कि वह योग्य संभरकों को जानता है।

(ग) जहां भारतीय आयातकों और विवेशी संभरकों के बीच चल रहे वर्तमान संबंध और नीदरलैंड और/या विकासीय देशों में उपलब्ध और समरूप संभरकों के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कर्जदार यह समझता है कि आयात केवल नीदरलैंड से ही प्राप्ती होने चाहिए। ऐसे मामलों में माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन (अनुबंध 1) की कंडिका 31 से 30 में निहित अधिप्राप्ति का नियम अपनाया जाना चाहिए।

3(6) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में क्रेता किसी भी एकमात्र संभरक से सीधे ही माल खरीद सकता है:—

(1) वाणिज्यक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में पजीकृत ब्रांड नाम की वह पर्यवस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुक़ बेचने के लिए है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमतः प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक है या विनिर्माणकर्ता है।

(2) वाणिज्यक आयातक द्वारा अधिप्राप्ति में वह पर्यवस्तु शामिल होती है जो विनिर्माण संसाधन या अन्तिम उत्पाद के सज्जीकरण और पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमतः प्राधिकृत वितरक है या व्यापारी है और जिसके लिए संभरक विनिर्माणकर्ता है।

(3) विषेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पुजों की अदाना बदली का सुनिश्चय करने द्वारा अधिप्राप्ति के द्वारा एक स्रोत से की जा सकती है।

(4) आयातक एक ऐसा विनिर्माणकर्ता है जिसके उपकरण और कच्चे माल का फार्मूला ऐसे कच्चे माल की विषेष किस्म के साथ अधिक से अधिक उपयोग के लिए बनाए गए हैं जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं।

(5) आयातक ग्रोपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत मूल रूप से की गई अधिप्राप्ति की बढ़ाना चाहता है या फिरसे उसे प्राप्त करना चाहता है बशतँ कि मूल अधिप्राप्ति की तुलना में अनुसूरक अधिप्राप्ति कम है और कुछ अवधार पर ही की जाती है और जब मूल अधिप्राप्ति के संबंध में नियम कार्य अभी चल रहा है या मूल अधिप्राप्ति के तुरंत बाद ही की जाती है।

(6) सौदे का मूल्य डी एफ एल 1 25 मिलियन से कम है।

(7) परामर्शदाता फर्मों के चुनाव के लिए श्रीपत्रारिक प्रतियोगी भौली कियाविधि की आयातका नहीं है। लेकिन भारतीय फर्मों द्वारा परामर्शदाता फर्मों को सुझायो के लिए नियन्त्रण भेजने से पूर्व ही ऐसी भावी पर्मों की एक सूची विन मन्त्रालय, आधिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए, इसके बाद सूची नीदरलैंड की सरकार को भेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दें सकती है या परामर्शदाता की पसन्द को रख कर सकती है और नीदरलैंड में परामर्शदायी क्षेत्र की जानकारी के अधार पर इस सूची को बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकती है।

(8) जहां श्रीपत्रारिक युली अन्तर्राष्ट्रीय बाली के अधार पर माल की अधिप्राप्ति के लिए प्रत्यन्त जिए जाने हैं तो आयातक को चाहिए कि वह जैसे ही नियिदा नाटिस भारतीय आयात की आनंदीय नियाति बुनेटिन में विवापत के लिए भेजे जाएं उसी समय इनकी नीन प्रतियो का विन मन्त्रालय, आधिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) नई दिल्ली का प्रवगत करते हुए भरत में नीदरलैंड के राजदतावास को भेज दे।

(9) खण्ड 2(2) में उल्लिखित “पुरिट आदेश” शर्त का अर्थ है भारतीय लाइसेंसरी द्वारा विदेशी सभरको को दिया गया वह आदेश जो बाद बाले के पुष्टिकरण आवेदन द्वारा विधिवत् समर्थित हो या व्य सविवा जो भारतीय आयातक और विदेशी सभरको दोनों द्वारा विधिवत् समर्थित हो या क्य सविवा जो भारतीय आयातक और विदेशी सभरको दोनों द्वारा विधिवत् स्वताक्षरित हो। विदेशी सभरको के भारतीय अभिकर्ताओं के पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

(10) यदि सविवा इच सभरक के साथ की गई तो सविवा के लागत-बीमा-भाड़ा/लागत एवं भाड़ा मूल्य को, इच गिल्डर में अप्स करना चाहिए और यदि सविवा पात्र स्रोत देशों के सभरको वे गाथ की गई हो तो उनकी मुद्रा में घटक करना चाहिए।

(11) सविवा में भुगतान की व्यवस्था नक्कद उत्तर पर होनी चाहिए प्रथम पातसदान दस्तावेजों को प्रत्यन्त करने पर। विदेशी सभरको भारतीय आयातको की किसी भी प्रकार की गाथ सुविधा उपसंधि करने की स्वीकृति नहीं देंगे।

(12) सविवा के मूल्य में सभिमित भारतीय अभिकर्ता वे कमीशन की धनराशि वो विशेष रूप से अर्थित किया जाना चाहिए। इस सभिधि में किसी प्रशार भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रूपए में किया जाना चाहिए। इस प्रयत्न जन के लिए विदेशी मुद्रा में प्रेप्त व्यवस्था नहीं होगा। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग के रूप में शोरे और इलिंग लाइसेंस के लिए बूक बिन जाएगी।

(13) क्य आदेश और सभरक के पुष्टिकरण अंतर्गत अप्रेज के होने चाहिए।

(14) सविवा में निम्नलिखित व्यवधानों को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए—

(1) सविवा भारत सरकार के अनुनादन के अधीन है (यदि सविवा का मूल्य डब गिल्डर में 50,000 या इनस कम हो) और यह भारत सरकार तथा नीदरलैंड सरकार दोनों के अनुमोदन के अधीन है (यदि सविवा का मूल्य डब गिल्डर 50,000 में अधिक हो जाता है)।

(2) यह सविवा डब सामान्य प्रयाजन एंट्रिट के लिए लाइसेंस शर्तों के अन्तर्गत दी गई भुगतान विधानाध द्वारा सचालित होगी और इस सभिधि में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही यह प्रभावी होगी।

(3) “माल डब मूल्य/विनिर्माण के हैं” (नीदरलैंड में सभरको के मामले में)

या

“माल मूल्य/विनिर्माण के हैं” (पात्र स्रोत देशों के सभरको के मामले में)

(4) नीदरलैंड से आयात लिए जाने वाले माल के लिए सभरको का नीदरलैंड पूजी निवेशक बैंक को उग जिसे व नीदरलैंड विनिय गडल द्वारा जिसमें सभरक स्थापित है जारी किया गया/प्रमाणित किया हुआ इस बार में एक प्रमाण पत्र वा प्रतियों से देना पड़ेगा कि माल नीदरलैंड मूल्य है। यह प्रमाण गणतान्त्र अनुबन्ध 5 में दिया गया है। प्रमाण पत्र का एक नमूना अनुबन्ध 5 में दिया गया है।

पात्र स्रोत देशों के सभरको के मामले में सभरको को “माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सार्वदायिन (अनुबन्ध-1)” में दिए गए उद्देश्य नियमों के अनुसार एग० आई० आ० का माल के उद्देश्य का प्रमाण देना पड़ेगा।

(15) जहां प्रशासन नियापावन गार्टी अपेक्षित हो तब सभरको से बैक ग रटा/ वारेटी क, प्रस्तुत वर्ते क लिए कानूना चाहिए।

खण्ड 4—भारत सरकार नीदरलैंड पूजी निवेशक बैंक द्वारा सविवा का अनुमोदन

(1) (क) सविवा पूर्ण होने के सुरक्ष बाद वी आयातको को आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति के साथ/सविवा/सभरण आदेश की 5 फोटो या प्रमाणित प्रतियों विनिय गवालय, आधिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) का भेजनी चाहिए। पात्र स्रोत देशों के सभरको के साथ पूर्ण की गई सविवाओं के मामले भ उमकी 8 प्रतियो भेजी जानी चाहिए। इसके अनियित आयातक के लिए अनुबन्ध-2 में उल्लिखित सूचना भी भेजना आवश्यक है।

(ब) इन सभरको के साथ पूर्ण की गई सविवाओं के मामले में आयातको का स्टाम्प समाहर्ता द्वारा विनिय न्याय निर्णय निर्धारित प्रति में अनुबन्ध 4 अनुमोदित अनुसूचित बैंक से एक बैंक गार्टी भेजनी चाहिए। बैंक गार्टी सविवा की धनराशि के समतुल्य रूपए का दर्शन हुए व्याज और अन्य प्रशारा महित उस धनराशि के लिए हानी चाहिए जिसके लिए प्राधिकार पत्र माना जाए है परिवर्तन की दर आपात साइमेंस की जारी होने की तियों को प्रतिलिपि राजस्व और बैंकिंग विभाग द्वारा अधिगूचित विनिय दर हानी।

(2) जब सभरको के नाम जिसमें नियिदा सूचना विज्ञप्ति की गई थी।

(3) उन पार्टियों के नाम जिन्होंने नियिदा पूछताछ के मद्दे दाम बनाए हैं।

(4) विशिष्ट प्रस्ताव का नुनने के लिए वारेटी सही सही पात्र यह भी बताया जाए कि यह न्यूनतम तरीका उपयुक्त बोला गया।

(5) यदि सविवा दस्तावेज, प्राधिकारिक युली अन्तर्राष्ट्रीय बाली या श्रीपत्रारिक चुनिद्वा अन्तर्राष्ट्रीय बाली पर आपागित हो तब निम्नलिखित सूचनाएँ भी प्रस्तुत की जानी चाहिए—

4(4) 50,000—उच्च गिल्डर या इससे कम मूल्य की सविदाओं के समय में उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय आयातक के उत्तरी सविदा/मन्त्रण आवेदन को प्रतिया उच्च प्राधिकारियों को भेजते समय बता दिया जाएगा। 50,000 उच्च गिल्डर से अधिक की सविदाओं के लिए, जैसे ही उच्च क्रेडिट के अन्तर्गत उच्च प्राधिकारियों द्वारा सविदा के वित्तदान के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है जैसे ही आयातक को यह सूचित कर दिया जाएगा कि उनकी सविदा प्रभावी हो गई है।

खण्ड 5-संभरकों को भुगतान

(क) नीदरलैंड के संभरकों को भुगतान

5(1) विकासणील देशों के लिए नीदरलैंड पूँजीनिवेशक बैंक विदेश को एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध 5 के रूप में) हेतु में भारत के राज-दूतावास के माध्यम से पोतलदान दस्तावेज के मद्दे संभरकों के लिए भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और सविदा आदि की प्रतियों के साथ उसे उच्च प्राधिकारियों को प्रयोगित किया जाएगा।

5(2) प्राधिकार पत्र की वैधता को सुनिश्चय संविदा में निर्विष्ट वितरण अनुसूची को व्यापार में रखते हुए किया जाएगा। किसी भी मामले में प्राधिकार पत्र, आयात लाइसेंस भी वैधता के बाद वैध नहीं होगा।

5(3) बूँकि क्रेडिट के अन्तर्गत सामान्यतः उच्च बैंक द्वारा संभरकों को भुगतान पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के मद्दे ही किए जाते हैं अतः इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए गए आयातों के लिए रियायती प्रबंध की सुविधा लागू नहीं होगी।

5(4) संभरकों को पोतलदान/भुगतान प्राधिकार पत्र की वैधता प्रबंध के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में, आयातक को वित्त भवालय, प्रार्थक कार्य विभाग (उम्ल्यू ई-3 अनुभाग) के साथ प्राधिकार पत्र की समाप्ति प्रबंध से बहुत पहले ही प्राधिकार पत्र में उपर्युक्त बृद्धि के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। यदि मानी गई बृद्धि प्रबंध मूल आयात लाइसेंस की वैधता से प्रधिक हो तो पुनर्वैध मूल आयात लाइसेंस की फोटो प्रति और बैंक से वह पत्र जिसमें बैंक गारंटी की वैधता प्रबंध बड़ा दी गई है, आवेदन पत्र के साथ भेजी जानी चाहिए।

5(5) यदि प्राधिकार पत्र की वैधता प्रबंध में बृद्धि के लिए आवेदन, प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 महीने की प्रबंध के भीतर प्राप्त नहीं हो जाती तो प्राधिकार पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी गई समझी जाएगी और प्राधिकार पत्र अपने आप खत्म हो गया समझा जाएगा।

5(6) मूल परकार्य पोतलदान दस्तावेज निरपवाद रूप से नीदरलैंड पूँजी निवेशक बैंक द्वारा भारत में सवित आयातक के बैंक को भेजे जाएंगे जिसे वह सुनिश्चित करने के बाद ही सर्वान्वित आयातकों के परकार्य दास्तावेज रिहा करने चाहिए कि आयातक ने निम्नलिखित को जमा कर दिया है:—

(1) सार्वजनिक सूचना सं० 8-प्राईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17 जनवरी, 1976 में यथा निर्धारित और मुख्य वित्तनक, आयात-नियात की सार्वजनिक सूचनाओं में समय समय पर यथा प्रधिसूचित या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुद्रा वित्तमय नियन्त्रण प्रबंधकाओं के माध्यम से गणना की जाने वाली प्रचलित वर पर उच्च गिल्डर में संभरकों को भुगतान के समतुल्य रूप:

(2) विकासणील देशों के लिए नीदरलैंड पूँजीगत निवेश बैंक एन बी, विदेश द्वारा संभरकों को वास्तविक भुगतान की तारीख से आयातक द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया हीस हजारी, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रूप के वास्तविक निवेश की तिथि तक निश्चित जमा की जाने वाली प्रतिक्रिया धनराशि के लिए वेष्ट उपर्युक्त (1) सार्वजनिक सूचना

सं० 46 प्राईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार प्रथम 30 दिनों के लिए 9% प्रार्थक वर और 30 दिनों की प्रबंध से प्रधिकारियों के लिए 15% प्रार्थक वर के द्विरात्रि से ब्याज।

5(7) यह सुनिश्चय करने की जिम्मेदारी संबंधित भारतीय बैंक की होगी कि आयातक को आयात दस्तावेज सौपने से पूर्व ही देय धनराशि सरकार के लेखे में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है। लाइसेंसधारी को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि बैंकों से दस्तावेजों की सुरक्षांगी लेने से पूर्व ही देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखे में जमा कर दी जाती है।

5(8) आयातकों को प्रतिक्रिया रूपान्तर विवेशी मुद्रा वित्तमय के प्राधिकृत आपारियों के माध्यम से करना चाहिए और सार्वजनिक सूचना सं० 184-प्राईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में यथा प्रतिक्रिया लाइसेंस की मुद्रा वित्तमय नियन्त्रण प्रति भी उनके द्वारा पूँजीकरण करवा लेनी चाहिए। प्रतिक्रिया प्रपत्र 'एस' संबंधित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेज दिया जाएगा।

5(9) खण्ड 5(6) में उल्लिखित धनराशि को स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाला, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली के पास केन्द्रीय सरकार के लेखे में निवेश के लिए निम्नलिखित लेखा एनी के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए:—

"केन्डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेज डिपोजिट नाट वियरिंग इन्स्टेंट-843-सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परवेजिस एप्लस्ट्रा एब्रोड-परवेजिस एप्लस्ट्रा अन्डर उच्च जनरल परवज ब्रेडिट 1977-78"

5(10) उपर्युक्त उल्लिखित रूपए निवेश की सूचना वित्त मंत्रालय, प्रार्थक कार्य विभाग, यू०सी०ब्रो० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ सार्वजनिक सूचना सं० 74-प्राईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31 मई, 1974 और 103 प्राईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 12-10-1976 में निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल जगताना आलान को भी भेजना चाहिए। प्राधिकार पत्र सं० के संबंध में सूचना विवेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके लिए रूपान्तर विवेश किया गया है, उच्च संभरकों को भुगतान की तिथि, ब्याज की धनराशि और वह प्रबंध जिसके लिए इसकी गणना की गई है, निरपवाद रूप से राजकोष चालान में सकेतित की जानी चाहिए।

प्रतिपूर्ति विवादित

5(11) उन आयातक लाइसेंसों के मामले में जहाँ उनका मूल्य 1 लाख रुपाएं से कम है, आयातक, को प्रतिपूर्ति किया विधि को चुनने की छूट होगी वशर्ते कि निष्पादन आदि के लिए कोई भी भुगतान रोका जाना जारी नहीं है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आयातकों को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनकी मन्त्रिवाद में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि भुगतान की विधि प्रतिपूर्ति प्रणाली द्वारा होगी। आयातकों को एक साथ पत्र भारत सरकार द्वारा उनके संविधान के अनुमोदन प्राप्त होने पर खोलना होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातक द्वारा यथा निर्दिष्ट नीदरलैंड में संभरकों के बैंक के लिए साथ पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करने हुए आयातक के बैंक को एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध 6) वित्त मंत्रालय, प्रार्थक कार्य विभाग (उम्ल्यू ई-3 अनुभाग) द्वारा जारी किया जाएगा, आयातक द्वारा साथ पत्र के मद्दे भुगतान आयात लाइसेंस की मुद्रा वित्तमय नियन्त्रण प्रति के आधार पर किया जाएगा। सामान्यतः संभरकों को सभी पोतलदान/भुगतान उपर्युक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 महीनों के भीतर पूरा कर दिए जाने चाहिए। संभरकों को पोतलदान/भुगतान वीस महीने की प्रबंध के भीतर पूरा न किए जाने के मामले में आयातक को जारी किया जाएगा कि वह निरपवाद रूप से संभरकों को पोतलदान/भुगतान को पूरा करने के लिए, समय सीमा की बृद्धि के लिए, इस निर्धारित प्रबंध के समाप्त होने से कम से कम एक महीना पूर्व ही वित्त मंत्रालय, प्रार्थक कार्य

विभाग इन्हीं 3 अनुभाग से सम्पर्क स्थापित करें। यह आवेदन, मार्गी गई प्रवधि बुद्धि को शामिल करते हुए पुनर्निर्धित आयात लाइसेंस की फोटो प्रति द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि ऐसा आवेदन निर्धारित प्रवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो उनकी संविदा में अप्रयुक्त शेष धनराशि आपिस कर दी गई समझी जाएगी। आयातक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, पालियार्मेट स्ट्रीट, नई विल्ली-१ को प्राप्त के पोतलवान के 15 दिनों के भीतर ही संभरक को किए गए भुगतान के संबंध में अपने बैंक से एक प्रमाण पत्र और डच संभरक से हस बारे में एक प्रमाण पत्र के साथ बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि “उसमें.....डच गिलडर की धनराशि जो बीजक मूल्य या माल के पोतलवान के 100% के बराबर है” उसे प्राप्त कर लिया है। वह यह भी सुनिश्चय करेगा कि संभरक द्वारा खंड 3(14) (4) में उल्लिखित माल के उद्गम के बारे में प्रमाण पत्र की दो प्रतियां सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक के माल के पोतलवान के 15 दिनों की निर्धारित प्रवधि के भीतर भेज दी जाती है। आयातकों की और से आर्थिक कार्य विभाग को जल्दी से प्रतिपूर्ति दस्तावेजों को भेजने से सम्बद्ध किसी भी लापरवाही पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्धारित को आयातक के नाम में सभी आयात लाइसेंस नियंत्रित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक गल्ली करता रहे तो ऐसी हालत में उसके मामले को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्धारित की काली सूची में रखने के लिए सिफारिश की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आयातक को आयात नियंत्रण आदि को शासित करने वाले अधिनियम के अन्तर्गत जुमर्ना/सजरा किया जा सकता है। आयातक द्वारा प्रतिपूर्ति क्रियाविधि का विकल्प लेने के मामले में उसे संविदा की 8 फोटो प्रतियों वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी संविदा के लिए अनुमोदन प्राप्त करते समय भेजनी चाहिए।

(ख) पात्र स्वोत देशों में संभरकों को भुगतान

5(12) आयातक द्वारा उसके आवेदन पत्र में यथा संकेतित संभरक के नाम में पात्र स्वोत देश में संभरक के बैंक के लिए साथ पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध-६ के रूप में) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (इन्हीं 3 अनुभाग) द्वारा खोला जाएगा। उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के साथ संविदा की प्रतियां भी हेंग में भारत के राजदूतावास द्वारा डच प्राधिकारियों को प्रेषित की जाएंगी।

5(13) पूर्व की कठिकारों में उल्लिखित प्राधिकार पत्र की पावरी के बाद आयातक का बैंक उसके प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर और वैध आयात लाइसेंस के महे अपने बैंकर के माध्यम से संभरक के नाम में एक साथ पत्र भोलेगा। इस संबंध में सूचना सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, पू०सी०ओ० बैंक विल्हेम, पालियार्मेट स्ट्रीट, नई विल्ली को भेजी जाएगी।

5(14) संभरक को भुगतान किए जाने के बाद संभरक का बैंक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, पू०सी०ओ० बैंक विल्हेम, पालियार्मेट स्ट्रीट, नई विल्ली को संभरक द्वारा विधिवत् पृष्ठांकित प्रमाणपत्र के साथ हस संबंध में पोतलवान दस्तावेज के अपरकार्य सेट और बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि बाद वाले से भुगतान प्राप्त हो गए हैं।

5(15) संभरक का बैंक संभरक से माल के उद्गम देण के संबंध में एक प्रमाण पत्र या एक प्रमाण (दो प्रतियों में) इस संबंध में प्राप्त करेगा कि वह माल और सेवाओं की अधिकारित के लिए मार्गदर्शन के स्तिंशुलग्न उद्गम देण के नियमों के अनुसार है और उसे सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, पू०सी०ओ० बैंक विल्हेम, पालियार्मेट स्ट्रीट, नई विल्ली को भेजेगा।

5(16) आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के लदान के महे उसके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग पू०सी०ओ० बैंक विल्हेम, पालियार्मेट स्ट्रीट, नई विल्ली को भेजे।

आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर बीजक/माल के लदान के महे उसके द्वारा संभरक को किए गए प्रेषण के एक प्रमाण पत्र को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, पू०सी०ओ० बैंक विल्हेम, पालियार्मेट स्ट्रीट, नई विल्ली को भेजे। आयातक को यह भी सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि लदान दस्तावेज का एक प्रकार्य सेट और बीजक की दो पंसितियों के साथ संभरक द्वारा भुगतान की पावरी के संघर्ष में विधिवृत् पृष्ठांकित प्रमाण पत्र और खंड 5(14) और 5(15) में उल्लिखित उचाम प्रमाणपत्र माल के लदान से 15 दिनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दिए जाएंगे।

5(17) आयातक द्वारा साथ पत्र के महे भुगतान आयात लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के आधार पर किए जाएंगे।

5(18) सामान्यतः सभी लदान/संभरकों के लिए भुगतान उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकार पत्र के जारी होने से 20 मास की प्रवधि के भीतर पूर्ण कर दिए जाने चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ लदान/संभरकों के लिए भुगतानों को 20 मास की प्रवधि के भीतर पूर्ण करने की संभासना नहीं होती तो आयातक को चाहिए कि वह निराशावाद रूप से लदान/संभरकों के लिए भुगतान को पूरा करने के लिए उपर्युक्त प्रवधि सीमा की समाप्ति से कम से कम एक मास पूर्व ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (इन्हीं 3 अनुभाग) से सम्पर्क स्थापित करें। इस प्रकार के आवेदन के साथ पुनर्वैष्ठ आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें मार्गी गई प्रवधि बुद्धि भी शामिल हो। यदि इस प्रकार का आवेदन निर्धारित प्रवधि से पूर्ण ही प्राप्त नहीं होता है, सो संविदा के अप्रयुक्त शेष को अस्पापित किया गया समझा जाएगा।

5(19) आयातक को और से आर्थिक कार्य विभाग को शीघ्र ही प्रतिपूर्ति वस्तावेज भेजने में किसी भी लुटी पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्धारित को आयातक के नाम में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को स्थित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक खुक करता रहे तो उसका मामला मुहूर्य नियंत्रक, आयात-निर्धारित की कालीसूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है।

5(20) प्रतिपूर्ति दस्तावेज की पावरी के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय नीवर लैड पूजीगत बैंक को पात्र लौत देशों से संभरकों को भुगतान की गई धनराशि को प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेगा। नीवरलैड पूजीगत बैंक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीवरलैड में प्रज्ञापित मुद्रा दर पर नीवरलैड गिलडर में समतुल्य धनराशि को प्रतिपूर्ति करेगा।

चंद 6 विविध

6(1) आयातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग की स्थिति को यथाति दृष्टि अनुबंध-7 के रूप में एक त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (इन्हीं 3 अनुभाग) को भेजे।

6(2) इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसारी और संभरक के बीच यदि कोई लगड़ा उठता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। संभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके द्वारा पूर्व की जाने वाली शर्तें आयातक द्वारा साफ रूप से अनुबंध-2 में बता दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो लगड़े के निपटान से संबंधित एक व्यवस्था भी संविदा में शामिल की जाए।

6(3) लाइसेंसारी आयात लाइसेंस या इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा मामात्य प्रयोजन केंटिंग के अन्तर्गत सभी प्रकार के आवारों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुवेशों और आवेशों का तुरन्त पालन करेगा।

6(4) उपर्युक्त कठिका में दी गई शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्धारित (नियंत्रण) प्रधिनियम के अधीन उचित कार्यवाई की जाएगी।

प्रतिबध-1

नीदरलैंड द्वारा द्विपक्षीय विकास ऋण के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन

क. सामान्य

1. ये मार्ग-दर्शन द्विपक्षीय ऋण के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को शामिल करते हैं जो (क) शासकीय नीदरलैंड प्रकाश सहायता कार्यक्रम का एक भाग है। ये ऋण विकासशील देशों के लिए उपलब्ध है। पात्र स्रोत देशों का सूची परिषिक्षण 'क' के रूप में सलग्न है। इस सूची में प्राप्तकर्ता देश इसमें शामिल है। नीदरलैंड को सरकार पात्र स्रोत देशों से सभरण की कमी को पूरा करने के लिए पात्र स्रोत से इतर स्रोत देशों से शाहन और बीमा कीमतों सहित माल और सेवाओं के सीमित संभरण के लिए व्यक्तिगत आधार पर सहमत हो सकती है।

2. नीदरलैंड की सरकार को इनके लिए अवधि है। सतुष्ट हो जाना चाहिए कि ऋण से प्राप्त सामग्री का उपयोग, अर्थ व्यवस्था, कार्य-क्रमता, अतराष्ट्रीय प्राप्तियां तथा में निपटता और पात्र स्रोत देशों के बीच बिना किसी देश-भाव की छद्मे में रखते हुए और इन मार्ग-दर्शनों में बताई गई अधिप्राप्ति कियाविधियों के अनुसार किया जाना है।

3. कार्डिका 16 और 17 में उल्लिखित मामलों का छोड़कर ऐसी कोई भी प्रशिया नहीं अपनाई जानी चाहिए जिससे यह पता चलता हो या यह परिणाम निकलता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष सभरक को या सभरको का पक्ष लिया जा रहा है।

4. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए ऋणी द्वारा अपनाए जाने वाले उद्देश के नियम और नियन्त्रण इन मार्ग-दर्शनों के साथ परिषिक्षण 'ख' के रूप में सलग्न कर दिए गए हैं।

5. ऐसे मामले में जहां ऋणी पर, अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता तो वह ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिससे यह सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक है कि खरोदवार इन मार्ग-दर्शनों का अनुपालन करता है।

6. (1) ऋणी निम्नलिखित मामलों की छोड़कर अधिकारिक उर्द्दी अतराष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और सेवाएं प्राप्त करेगा—

(क) जहां नीदरलैंड परम्परागत या आयातों के लिए केवल एक माल स्रोत है।

(ख) जहां आयातों का मूल्य ऐसे एक एवं 1.25 मिलियन से कम है।

(ग) जहां इस प्रकार की कियाविधि लागू नहीं होती या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंड राजकार और ऋणी देश के बीच करार किसी अन्य उभित कियाविधि से सभरको को उनकी ओलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमदाति करने से पूर्ण ही पूरा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का करार राजकीय नीदरलैंड राजदूतावास के माध्यम से ऋणी द्वारा दी जाने वाली सभी संबद्ध जानकारी के आधार पर किया जाना है।

6. (2) जहां भारतीय आयातों और विदेशों सभरको के बीच कायम वर्तमान सबध और नीदरलैंड और या विकासशील देशों में उपलब्ध, और व्यभिजात संभरणों के अवसर के प्रकाश में ऋणी राम्रता है कि आयात केवल नीदरलैंड से ही प्रभावी किए जाने चाहिए तो खरोदवार, केवल नीदरलैंड से के लिए बोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैंड से और साथ ही साथ पात्र स्रोत देशों से ओलिया प्राप्त करने के लिए विकल्प रखेगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31-33 के साथ मार्ग-दर्शन का अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34-38 के साथ अनुच्छेद 30 लागू है।

7. ये मार्ग-दर्शन और साथ ही साथ उद्देश के नियम और पात्र स्रोत देशों की सूची नीदरलैंड को सरकार के संशोधनाधीन है।

ब. अधिकारिक खुली अतराष्ट्रीय बोली के लिए कियाविधि

(४) बोली के लिए आमदान जारी करने समय (या ऋणी की ओर से खरोदवार) निम्नलिखित दो शकाशनों में से कम से कम एक में बोली का विज्ञापन देगा।—

भारतीय व्यापार परिक्रा

भारतीय नियंत्रित सेवा बुलेटिन

आयातक भारतीय अन्याय परिक्रा या भारतीय सेवा बुलेटिन से उथा विज्ञापित नियंत्रित नंबिटम की तीन प्रतिक्रा भारत मिथ्यत नीदरलैंड के राजदूतावास को भेजेगा।

५. प्रतिवेशिता को व्यातक प्रात्साहन देने के लिए ऐसी अलग-अलग सविदाएं जिनके लिए जब कभी सभव हो बोलिया आमदाति की जाती है तब इनमें अड़ी होनी चाहिए कि अन राष्ट्रीय आधार पर बोलिया का आक्षित वर सके। दूसरी तरफ यह हि यदि तकनीकी और प्रणाली ऐक दृष्टि से एक पर्यायजनका का विशेष प्रकार की सविदाओं में विभाजित करना सभव हो और इस प्रकार के विभाजनों ऋणी को लाभ हो ग्रो/या इससे अतराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली और भी विशाल बन जाए तो परियोजना विभाजित की जानी चाहिए। अभियांत्रिक, उपकरण और नियमण कार्य (सामान्यतः "टर्न की कान्टेक्ट") के स्वरूप में जाने जाते हैं) के लिए एकल सविदाओं की आदा की जाना सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक सविदाओं के भीतर ऋणी देश के लिए सपूर्ण लाभ अपेक्षा करती है।

१०. विशेष रूप से सविल कायदे का सविदाओं के लिए अधिकारिक पूर्व योग्यता को बोला की जानी सकती है। यदि पूर्व-योग्यता को बाला की जाती है तो वह इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः संतोषजनक निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। (१) ऐसी प्रकार के कार्य में कार्य का पूर्व अनुभव (२) कार्मिक, उपकरण एवं संयंत्र के संबध में इसकी क्षमता और (३) इसकी आर्थिक स्थिति और सबलता। पूर्व-योग्यता क्रियाविधि का विज्ञापन किया जाएगा। पूर्व-योग्यता के लिए विचार किए जाने वाले हजारों के लिए संक्षिप्त विशिष्टकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जब पूर्व-योग्यता लागू हो जाती है तो वे सभी कार्य जो पूर्व-योग्यता की शर्तों को पूरा करती है बोली के लिए अनुमत होंगी।

११. बोली के दस्तावेज उन भाषाओं में से किसी एक भाषा में तैयार किए जाएंगे जो अतराष्ट्रीय पत्र-व्यवहार में साधारणतः प्रयोग को जाती है और जब वह कानूनी तीर भर रोक नहीं लगा दिया जाता इस बात का उल्लेख करेंगी उक्त भाषा दस्तावेज के मूल पाठ में लागू रहेगी।

१२. विशिष्टकरण में किए जाने वाले कार्य सभरण किए जाने वाले माल और सेवाओं तथा सुपुर्दीय या सरथापन की जगह के लिए जहां तक सभव हो साक और सुस्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इंहें विशिष्टकरण के विषय के प्रत्युक्त होगी, जहां वे अनुकूल नहीं होगी तो उसका मूल पाठ लागू होगा। विशिष्टकरण में मूल्यांकन के सिद्धांत और ओलियों की तुलना का उल्लेख करेंगा जो तब सेवे में दिए जाएंगे जब मूल्यांकन किए जाते हैं। और ओलियों की तुलना की जाती है। विशिष्टकरण में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, जिससे कि स्वतंत्र और संपूर्ण अतराष्ट्रीय प्रतिवेशिता को स्वीकृति एवं प्रोत्साहन मिल सके।

किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी स्पष्टीकरण गलतियों में सुधार और विशिष्टकरणों से परिवर्तन तथा बोली के लिए आमंत्रण से उनको योग्य ही अवगत करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया था।

१३. यदि इस प्रकार के राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल होने आवश्यक हों तो विशिष्टकरण में यह बताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अतराष्ट्रीय स्वीकृत मानकों को पूरा करते हैं जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उसके बराबर या अलगी किसी की मात्र की गई हो तो वे भी स्वीकृत किए जाएंगे।

14. यदि विशेष फालतू पुर्जी की प्रपेक्षा की जारी है या यह निश्चय किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणकता को बनाए रखने के लिए एक विशेष माला के मानकीकरण की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन और क्षमता पर आधारित होने और उनमें केवल तभी पजीकृत मार्क नाम सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पाद निर्धारित होने चाहिए। अन्तिम मामले में विशिष्टिकरण में विकल्प की उत्तमान के प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दी जाएगी जिसमें मिलती-जुलती विशिष्टिताएँ हैं जिनका निष्पादन और क्षालिटी कम से कम उन विशिष्टिकृत स्तर के बराबर है।

15. बोली के लिए निमंत्रण में पात्र स्त्री वेशों का उल्लेख किया जाएगा और उद्योग के लागू नियमों को बनाया जाएगा।

16. बोटेशन की जात्याकृति पात्र स्त्री वेशों के संभरणों के बीच पूर्णत बराबरी की जाती है कि आधार पर की जाएगी (इसमें माल और उपकरण के लिए सीमा-गुलक टैरिफ और अन्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी करों की नियमिती पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल हैं) लेकिन और्जी वेश माल और सेवाओं के संभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमतें शामिल नहीं हैं स्थानीय माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र स्त्री वेशों के उत्पादों के लिए वरीयता की गुणावश्वता के लिए जो गटू है या जो इस प्रकार के वर्ग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए अन्य पात्र स्त्री वेशों में उत्पन्न होने वाले माल और सेवाओं के लिए आधिकृत है। वरीयता की यह गुणावश्वता न्यूनतम मूल्यांकित विदेशी बोली के लागत बीमा भाड़ा पर 15 प्रतिशत या बोलीकार के वेश में सीमा-गुलक करों के बीचीय अधिक वर्ग जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

17. विशेष मामलों में और्जी नीदरलैंड सरकार और और्जी देश के बीच आपसी परामर्श करके कठिका। 16 में उल्लिखित वरीयता की गुणावश्वत के प्रतिरक्षित गटू के अनुकूल स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माणकर्ताओं के लिए वरीयता की सीमित गुणावश्वत को प्रदान कर मरकता है। वरीयता के स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय दर्जा या क्षेत्रीय स्वार्थ और प्रबंध और और्जी वेश के पंजीकरण या इन विनिर्माणकर्ता कर्मों के क्षेत्रीय आर्थिक वर्ग जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

18. बोली दस्तावेज में कोई भी सहमत वरीयताएँ प्रवर्शित की जाएंगी और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें लागू किया जाएगा उन्हें भी बनाया जाएगा।

19. बोलीकारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसमें वे अपनी बोलियों प्रस्तुत करेंगे।

20. बोलियों को प्राप्त करने और बोली को खोलने के लिए अन्तिम तारीख समय और स्थान बोली के लिए नियमणों में घोषित किया जाएगा और सभी बोलियों निर्धारित समय पर जनता के सामने खोली जाएगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को बिना खोले ही लौटा दिया जाएगा। बोलीकार का नाम प्रत्येक बोली या आवेदित या स्वीकृत यवि कोई विफली बोली हो तो उसका कुल मूल्य उंची आवाज में पढ़ा जाएगा और उनका रिकार्ड रख दिया जाएगा।

21. किसी बोलीकार को बोलिया खुलने के बाद अपनी बोली में परिवर्तन करने की स्थीकृति नहीं दी जाएगी। केवल बोली के मूल में परिवर्तन से भिन्न स्पष्टीकरण स्थीकार किए जा सकते हैं। और्जी किसी भी बोलीकार या अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है किन्तु किसी भी बोलीकार की बोली के मूल में या अपनी बोली के मूल में परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा।

22. कनून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर जांच से सम्बद्ध कोई भी मूलना स्पष्टीकरण और बोली के मूल्यांकन तथा परिनिर्णय से संबद्ध

सिफारिश बोलियों के सार्वजनिक रूप से खुलने के बाद मफल बोलीकार के लिए संविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी उस व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो और्जी की ओर से या नीदरलैंड की सरकार की ओर से इन वियाविधियों से आगामी रूप से सबद्ध नहीं है;

23. बोलियों के खुलने के बाद खरीदार उस बात का सुनिश्चय करने के लिए बोलियों की जात्र करेगा कि क्या बोलियों के परिफलन में महत्वपूर्ण गलियां की गई हैं क्या बोलिया/बोली दस्तावेज की आवश्यकताओं के पूर्णत अनुकूल तो है क्या अपेक्षित गारन्टीयों और जमानतों की अवस्था की गई है क्या दस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए गए हैं और क्या दस्तावेज अन्यथा रूप से वास्तव में बोली दस्तावेज के अनुकूल नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। तब आर्थिक वृद्धि से विस्तृत निर्धारण के साथ तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा जिससे प्रत्येक अनुकूल बोली का मूल्यांकन किया जा सके और बोलियों को मिलान के लिए समर्थ बनाया जा सके।

24. बोली के लिए निमंत्रण में बताया जाए कि खरीदार को ऐसी सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार है जब कोई बोली विशिष्टिकरण के प्रयोजन के अनुकूल नहीं है और जब प्रतियोगिता के अभाव का प्रमाण मिलता है या निष्ठ बोलिया उस पूर्व अनुमानित धनराश की कीमत से अधिक होती है जो इस तरह की कारंदारी वो उचित बताने के लिए पर्याप्त है। यदि रासी बोलियां रद्द कर दी जाती हैं तो और्जी नीदरलैंड उस सरकार के साथ परामर्श करने के बाबत ऐसी स्थितियों के कारणों को और निम्न बोली और अनुमानित कीमत में अन्तर के कारणों को जानने के लिए एक या एक से भिन्न स्तरम बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है विशिष्टिकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तथा की गई वो संविदाएँ जिसमें परियोजना की मनुमानित धनराश की कीमत से उन्हें स्वीकार किया जा सकता है वशर्ते कि परिवर्तन परियोजना के स्वरूप को वास्तविक रूप से नहीं बदलते। जहां परिवर्तन वास्तविक है वहां पुनः बोली उचित हो सकती है। इसे हर बार नीदरलैंड्स की सरकार द्वारा अनुमोदित कराना होगा।

25. बोलियों के मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में बताए गए नियम और जाती के अनुसार और बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से पूर्व इससे सम्बद्ध किसी भी आशोधन के अनुसार होने जाहिए। न्यूनतम मूल्यांकित बोली की स्पष्टी करने के प्रयोजनार्थ कीमत से भिन्न तथ्यों जैसे निर्माण कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता, इसकी सुरुदंगी को समय और सेवा और फालतू पुर्जी की उपलब्धता की भी ध्यान में लिया जाएगा और जहां तक संभव ही राकेता मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिसमें बोली कीमत को भुगतान किया जाएगा उनका मूल्यांकन बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा भी दरों के आधार पर और बोली की अन्तिम तारीख को इस प्रकार के सौबों के लिए लागू रखेंगे।

26. संविदा का परिनिर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा जिसकी बोली पूर्व की कंडिकामों में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्यांकित बोली निश्चय की गई हो।

27. अनुरोध करने पर नीदरलैंड्स की सरकार को अधिप्राप्ति के सभी पहलुओं पर अपनी टिप्पणी और सिफारिश प्रदान करने के लिए उचित प्रवत्तर दिया जाएगा। संविदा का परिनिर्णय होने के बाद नीदरलैंड्स की सरकार को विधि के उपयोग के मूल्यांकन के लिए सभी सम्बद्ध वस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी (उनकी प्रत्येक सहित) प्रदान की जाएगी।

(ग) श्रीपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली से भिन्न अधिप्राप्ति की क्रियाविधि :

23. कंडिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कंडिका 31—39 में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कंडिका 6 के अनुमार लागू हो सकते हैं।

29. मानकीकरण :

जहाँ खरीददार के पास अपने उपकरण के उचित मानकीकरण को बनाए रखने के लिए विश्वमनीय कारण हैं।

30. योग्य संभरकों की सीमित संख्या :

उन मामलों में जहाँ विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रकृति के कारण योग्य संभरकों की संख्या सीमित है और खरीददार को मार्किट जानकारी ऐसी है कि उससे आवा को जा सकती है कि योग्य संभरकों के बारे में जाने।

31. श्रीपचारिक चुनिदा अन्तर्राष्ट्रीय बोली :

सामान्य चुनिदा अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत खरीददार उन सीमित संख्या के (पूर्व) योग्य संभरकों से बोलिया आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत हैं जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाते हैं।

ऐसे मामले में शृंणी को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि किसी भी सम्भावित योग्य संभरक को छोड़ नहीं दिया गया है। जब और जैसे ही वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार, से पात्र स्रोत, वेशों के सम्मानित संभरकों के बारे में जानकारी मार्गी जाएँगी सभी आवश्यक जानकारी प्रयान की जाएँगी जिससे कि वे उचित आधार पर आग लेने में समर्थ हो सकें।

32. संभरकों का चुनाव केवल उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाना है और जहाँ तक संभव हो वे नीदरलैंड्स सहित अनेक पात्र स्रोत वेशों से चुने जाते हैं।

33. कंडिका 8 में उल्लिखित से भिन्न श्रीपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू की जाती हैं।

34. श्रीपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति :

यदि श्रीपचारिक प्रतियोगिता बोली की क्रियाविधियों के माध्यम से अधिप्राप्ति नहीं होती है तो वह संतोषजनक वाणिज्यिक नीति के अनुसार और पात्र स्रोत वेशों के बोच बिना किसी भेद-भाव के प्राप्त करनी चाहिए।

35. आयातक को श्रीपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति के इच्छित उपयोग का विस्तृत और समयोजित प्रचार करना चाहिए। पात्र स्रोत वेशों के संभरक जब भी ऐसी सूचना मार्गेंगे, तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार उनको व्यायोचित आधार पर भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सभी आवश्यक सूचना देंगी।

36. वर्तों और प्रस्तावों की तैयारी के लिए अनुमति समय शामिल की गई संविवाहों के स्वरूप द्वारा तियोजित किया जाएगा। साधारण सम्प्रत्यंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए समय और वितरण दोनों की अनुसूचियां पर्याप्त लम्बी होंगी।

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैंड्स सरकार मूल्यमान के प्राप्त किए गए थे इसके पूर्ण व्योरे सहित विक्रय किए गए माल, शामिल किए गए संभरकों और प्राप्त मूल्य वर्तों के सम्बन्ध में वित्तीयों से सूचना मार्ग सकती है।

38. श्रीपचारिक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण संभव सीमा वर्त व्योचित मार्ग-दर्शन लागू होना चाहिए।

39. एक मात्र संभरक :

निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केता का किसी एकमात्र संभरक से सीधे ही क्रय करने की अनुमति दी जाती है—

(1) एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पूजीकृत व्यापार चिरंकृत नाम आवा पृथक्स्तु शामिल है होती है जो आयातक द्वारा पुनः विकी के लिए हो, जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित प्राधिकृत वितरक व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक व्यापारी हो ;

(2) एक वाणिज्यिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पृथक्स्तु शामिल है जो विनिर्माण संस्थान या संयोजन और उस प्रतिम उत्पाद से पुनः विक्रय के लिए अधिप्राप्ति की जाती है जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित रूप से प्राधिकृत वितरक व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक विनिर्माण हो ;

(3) पुजों की विनिमयशीलता का सुनिश्चय करने के लिए या विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण अधिप्राप्ति केवल एक ही व्यापार से पूर्ण की जा सकती है ;

(4) केता वह विनिर्माण हो जिसका साज-सामान और कच्ची सामग्री का फारूला कच्ची सामग्री की उस विशेष किसी के जिस सर्वोत्तम उत्पाद के लिए बनाया गया हो जो केवल एक ही व्यापार से प्राप्त की जा सकती हो ;

(5) यदि संभरक श्रीपचारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अधीन मूल रूप से प्राप्त की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना या बढ़ाना चाहिए हो व्यापर्ति के सम्पूरक अधिप्राप्ति मूल अधिप्राप्ति के मुकाबले में छोटी हो, केवल कुछ ही अवसरों पर पूर्ण की जाती हो और जब मूल अधिप्राप्ति से संबंधित निर्माण कार्य उस समय भी चल रहा हो या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण करने के पाइँही समय वाले पूर्ण की जाती हो ।

(6) यदि सौदे का मूल्य डी०एफ० एल० 1.25 मिलियन से कम हो ।

घ. परामर्शकों के उपयोग के लिए मार्ग-दर्शन ।

40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाएं इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि उनका परामर्श डिजाइन, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के वस्त्रावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक या श्रीपचारिक पश्चात से मृक्त हो और वे प्रतियोगिता के आधार का अनुपालन कर सकती हों। स्थानीय परामर्शदाती संस्थाओं पर विचार करते समय राष्ट्रीय स्वामित्व का स्तर प्रबंध और कामिक तथा पंजीकरण जैसी बातें पर उचित ध्यान देना चाहिए ।

41. परामर्शदाती संस्थाओं के चयन के लिए श्रीपचारिक प्रतियोगिता बोली क्रियाविधियों की आवश्यकता नहीं है। सेक्रेन, चदन की प्रक्रिया में शृंणी को उन प्रस्तावित संस्थाओं की योग्यात्मित संदेश पर विचार करना चाहिए जिनमें कई पात्र स्रोत वेशों में समर्थ और स्वतंत्र सेवाएं प्रपत्त करने की श्रापा की जा सकती हो ।

यह शृंणी निम्नलिखित बातों की ध्यान में रखते हुए पूर्वनुणों पर आधारित होणी:—

(1) कार्य की समान किसी में संस्था का पहला अनुभव ;

(2) कमंचारियों, साज-सामान और संयंत्र के संबंध में इस संस्था की क्षमता; और

(3) इसकी वित्तीय स्थिति और स्वतंत्रता ।

यह बालनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण भेजने से पहले अपनी प्रत्याशित सम्मानियों को सूची नीदरलैंड्स सरकार को प्रस्तुत करे। नीदरलैंड्स सरकार का परामर्शी के चयन को अस्वीकार करने का प्रधिकार है, इसके अनियन्त्रित वह नीदरलैंड्स में परामर्शदात्री भेज से अपनी जानकारी के आधार पर यह सुकाव दे सकती है कि इस सूची में दृढ़ि की जाती है।

इ. शिकायतें :

42. खरीदार बोली के संबंध में बोलियो को प्रस्तुत करने और मंत्रिवादी के प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को मुनने और उनकी जांच करने की व्यवस्था करेगा।

43. श्रीपद्मार्थिक बोली कियाविधि के अंतर्गत की गई खरीद के मामले में बोली समाप्त होने की नियम से पूर्व किए गए प्रतिबंध पर्यवर्त्तन विभिन्नकरण या आभद्रण की प्रतिबंध प्रवधि के संबंध में विषयवस्तु की किसी भी शिकायत का समाधान बोलियो के खलने से पूर्व ही किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही उचित प्रवधि के लिए बोली के लिए अनियम तिथि स्थगित की जाए।

44. जब शिकायत मंदद संभरकों में से किसी एक के द्वारा की गई है तो शिकायत के विषय से संबंधित और इस पर की गई कार्रवाई से मबद्दित दस्तावेज नीदरलैंड्स सरकार द्वारा और अपनी दावा जांच के लिए उपलब्ध होगे।

परिशिष्ट "क"

विकामर्शील देशों की संयुक्त द्विपक्षीय अहं के लिए पात्र छोते देशों की सूची

(क) नीदरलैंड्स

(ख) अफ्रीका

उत्तरी साहारा,

अर्लंजीनिया

लीबिया अरब गणराज्य

मोरक्को

तूनीसिया

मिश्र

विभिन्नी साहारा :

मोटस्थाना

बुर्किना

केपोहन

केप वर्दी द्वीप समूह

मध्य अफ्रीका गणराज्य

चाद

कोमोरो द्वीप

कानो (जनशादी गणराज्य)

जैरी गणराज्य

दहोमी

इथोपिया

गिर्किन

गिर्मिया

धाना

गिनी

गिनी चिसाऊ

ग्राइंडरी कोस्ट

कीनिया

लिबोयो

लाइबेरिया

मालायासी गणराज्य

मलावी

माली

मरिलेनिया

मारिशस

नाइजर

नाइजेरिया

रियूनियन

स्प्रान्डा

सैनेगाल

सेच्चलेज

सिवरा लैजोन

सोमालिया

टरफार और इसास

सेट हैलेन और डेपेंडेन्सिस

सूडान

स्वातालीसिंड

तन्जानिया

टोगो

उगान्डा

अपर बोल्टा

जाम्बिया

जमेरिका उत्तरी एवं मध्य :

बहामास

बारबेडोस

बरमदा

कोस्टा रिका

क्यूबा

डोमीनिकन गणराज्य

ई-1 सल्वादोर

गुडैलीप

गुस्तावाला

हैती

होनुराज (ज)

होन्डरस (ब्र)

जमेका

माटिनिक

मैक्सिको

नीदरलैंड्स अम्फ्लीज

निकारागुआ

पनामा

सेट वेरी मिक्युलोन

विनी दाव टोबागो

वेस्ट इन्डीज (ब्र)

विजिए :

अर्जेन्टीना

बोलीविया

ब्राजील

चिली

कोलम्बिया

इक्वादोर

फाफलैंड द्वीप समूह

गुयाना

मिनी (फ)

पराग्वे

पीर

सुरीनाम
युश्क्वे
वीनेज्युले
एशिया मध्य पूर्वी
ईहरीन
हराम
इराक
हजाराइन
जोहैन
कुवैत
लेबनान
झोमन
फलार
सऊदी अरब
यमन (जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य)
सीरिया (अरब गणराज्य)
यमन (अरब गणराज्य)

विभिन्न एशिया
अफगानिस्तान
बगदा देश
भूटान
बर्मा
भारत
मालदिव
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका
सुदूर पूर्व
बूनी
सेमर गणराज्य
हांगकांग
इन्डोनेशिया
कोरिया (गणराज्य)
कोरिया (जनवादी प्रजातन्त्र गणराज्य)
लाओस
मेको
मालेशिया
फिलीपिन्स
सिंगापुर
थाईलैण्ड
तिमोर
वियतनाम (गणराज्य)
वियतनाम (प्रजातन्त्र गणराज्य)
लामुक्किक
फिझी
गिलबर्ट एवं एलिस द्वीप समूह
फिन्च पोलिनेशिया
न्यू कॉलोनिया
न्यू ईवराइंडज (ब्रॅथेंफ)
ऐसिफिक द्वीप समूह (यू० एस०)
पैपीन्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह
टोंगा
वालिज और कुतुमा

पश्चिमी सामोगा
यूरोप
टर्की
पुर्तगाल
परिशिष्ट "क"

उद्गम के नियम

1. उद्गम के इन नियमों की विषयाधीन मर्दे पात्र और देशों में उत्पादित भाल और सेवाएं होगी।
2. माल के मामले में नीदरलैण्डस से उद्गम का नियरिण इस क्षेत्र में उस विधान के अधीन होगा जो कि यूरोपीय समुदाय में लागू है।
3. पैरा 2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीदरलैण्डस के वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा।
4. माल के मामले में विकासशील देशों के उद्गम का नियरिण उस उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली की रूपरेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हो।
5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों के प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपत्र 'ए' (जो अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है)। उद्गम में प्रमाण पत्र द्वारा भेजा जाएगा।
6. सेवाओं के मामले में (प्रथम भार्ग व्रश्न का पैरा 1) उद्गम का नियरिण नीदरलैण्ड सरकार और झृण लेने वाले देशों के वीच आपसी परामर्श से तदर्थं आधार पर किया जाएगा।
7. ऐसे मामलों में जहां उद्गम के नियमों से वास्तव में कोई समर्था पैदा हो जाती है या झृण लेने वाले देश को गम्भीर प्राथिक आठा हो जाता है (उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावी सम्भरणों पर जबर्दस्त प्रातबन्ध) तो इन नियमों से सुदृकरण पाने की स्वीकृति वी जाती सकती है किस्त वह केवल नीदरलैण्ड सरकार एवं झृण लेने वाले देश के बीच प्राप्ती परामर्श के बाद दी जा सकती है।

अनुबन्ध 2

- (ए) भारतीय आयातक का नाम और पता और/या जहां आवश्यक हो परियोजना अधिकारी का नाम व पता।
- (बी) संभरक का नाम और पता। यदि संभरक पात्र स्वीकृत देश के हैं तो उस मामले में विस्तृलिखित सूचनाएं भी भेजी जानी चाहिए:—
 - (1) राष्ट्रिकता।
 - (2) पात्र स्वीकृत देशों के द्वारा रखे गए शेयरों का प्रतिशत।
- (सी) (1) आयात साइरेस की संख्या और दिनांक।
 - (2) मूल्य।
- (डी) (1) नीदरलैण्डस/पात्र स्वीकृत देश में संभरक के बैंक का नाम और पता
 - (2) भारत में आयात का बैंक (यह वह बैंक होगा जिसने बैंक गारंटी दी है)।
- ** (3) भारत में आयातक का बैंक जो कि आयातक के लिए पोतलबान वस्त्रावेष रिहा करने से पहले भारत के लेख में रखा जाना फरमे के लिए उत्तरदायी होगा।

*निजी क्षेत्र के लिए।

**सार्वजनिक क्षेत्र के लिए।

(इ) उच्च गिल्डरस में या पाल स्नोत वेश की मुद्रा में संविदा भावेत का मूल्य ।

(एफ) भ्रष्टाचारित की विधि, क्या यह सीधे खरीद पर आवश्यक है या भ्रष्टाचारिक खुले ग्रंथालैट्रीय बोली पर या चयन फार्मूला ग्रन्ट-रिट्रीय बोली के आधार पर, जिस माम्रमें यह संकेत किया जाना चाहिये कि क्या संविदा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ न्यूनतम तकनीकी उपर्युक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है ।

(जी) आयात किये जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ।

(एच) माल का उद्गम—यदि कोई हो तो गैर पाल स्नोत वेशों से आयातित संबंधितों का प्रतिशत ।

(झाई) सुपुर्वगी को पूरा करने की संभावित तिथि ।

(जे) भुगतान की शर्त और संभावित वह तिथि जिस दिन इस संविदा के ग्रन्तर्यात भुगतान के लिए पड़ेगी ।

(के) पोतक्षयान बस्तावेजों की विस्तृत सूची जैसे अवतरण विल, बीजक, उद्यम प्रमाण पत्र आदि जिसे विकासशील वेशों के लिये नीवरलैन्ड पंजीय विवेश बैंक या पाल स्नोत देश में संभरकों के बैंक को चाहिये कि संभरकों को भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रस्ताव दस्तावेज की प्रतियों के साथ मांग करे ।

(एल) यदि संविदा में शामिल है तो भारतीय एजेन्ट का वह कमीशन (ठीक-ठीक धनराशि संकेतित की जानी है) जिसे प्राधिकार पत्र जारी करते समय संविदा के मूल्य में से घटाना पड़ेगा, इस प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेन्टों को रपये में आयातकों द्वारा सीधे ही किया जायेगा ।

(एम) वह मूल्य जिसके लिये प्राधिकार पत्र अपेक्षित है ।

(एन) बैंक गारम्टी की संख्या, दिनांक और मूल्य इसमें उस अवधि का भी संकेत हो जिस तक यह वैध है ।

(ओ) यदि कोई हो, तो विशेष मनुष्येश ।

अनुबन्ध 3

उच्चक्रेडिट

संविदा प्रमाणपत्र

संविदा के ब्यौरे

भारतीय आयात साइटेस की संख्या ।

- संविदा की संख्या एवं दिनांक ।
- खरीदार को संभरित किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के ब्यौरे । (यदि बहुत सी मदों का संभरण किया जाना है तो प्रमाणपत्र में विस्तृत सूची लगाई जानी चाहिए ।)
- खरीदार को चुकाई जाने योग्य कुल संविदा कीमत (लागत-बीम, भाड़ा, लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए) डी० एफ० आई० । यदि माल का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्डों की पूर्ति प्रवर्णय की जानी चाहिए ।
- नीवरलैन्डस बाणिजिक मंडल की जारी किया गया लाइसेंस स० । को जागत एवं भारत के लिये उपर्युक्त नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रसिद्धि किए हुए वह उस माल की खरीद

संभरक द्वारा सीधे ही विदेशों से की गई है अर्थात् विनिर्भास में प्रयुक्त आक्षयित सामग्री या संबंधितों का प्रतिशत ।

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य ।

(छ) मदों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण ।

5. यदि सेवाओं का वंभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खण्ड भी भी पूर्ति की जानी चाहिए ।

6. किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या

(क) आपकी कंपनी (साइट इन्जीनियर ब्राह्मण आदि) ।

(छ) स्थानीय संभरक ।

द्वारा खरीदार के वेश में निष्पादित की गई सेवा का उल्लेख कीजिए ।

7. उपर्युक्त कंपिका 4 और 5 के सम्बन्ध में यथा आवश्यक अर्थक विप्रयोग ।

8. मैं शोध्याम करता हूं कि मैं संभरक द्वारा या नीवे उल्लिखित द्वारा नीवरलैन्डस में नियुक्त किया गया हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे प्रधिकार है । एतद्वारा बचत देता हूं कि उपर्युक्त कंपिका 4 और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से भिन्न और किसी भी ऐसे माल या सेवा का इस संविदा के निष्पादन में संभरक द्वारा संभरण नहीं किया जाएगा जो नीवरलैन्डस मूल के नहो है ।

हस्ताक्षरित ।

ओहृदा ।

संभरक का नाम और पता ।

विवाक ।

नीवरलैन्डस बाणिजिक मंडल ।

प्रमाणित

अनुबन्ध 4

गारंटी बांड

(इस सामान्य प्रभेक्षण क्रेडिट के ग्रन्तर्यात माल के आयात संस्कृति व्रक्रिया के ग्रन्तर्यात बैंकों द्वारा भेजा जाना है)

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले (इसके बाद इसे 'भरकार' कहा गया) इच्छा सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के ग्रन्तर्यात जारी की गई शर्तों के अनुसार तथा ऊपर उल्लिखित करार के मुद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण में दिनांक की जारी किया गया लाइसेंस स० । को जागत एवं भारत में उपर्युक्त नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रसिद्धि किए हुए वह उस माल की खरीद के आयात के लिए इच्छा गिल्डर में भुगतान के लिए राजी

होते हुए आयातक के अनुरोध पर हम (ईक) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जिहे द्वारा भुगतान की गई धनराशी को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू परिवर्तित दर पर जा इस मञ्चन्द्र में समय-ममत्य पर सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, इच सभरको को किए गए भुगतान की नारीब को सरकारी लेख में क्रेडिट के लिए समतुल्य पये के भुगतान की तारीब तक पहुँचे 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर पर [जैसा कि सार्वजनिक सूचना 46-माइटोसी (पीएन)/76 दिनोंक 16-6-76 में निर्धारित है] गणना किए गए ब्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावसी की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार को क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के ग्रन्तीयत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा नेत्रा शीर्ष के विपरीत सकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं, विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हेंग द्वारा प्राप्त आयात नशा का प्रकार्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जब कि उक्त के अधिकत जमा दृष्टे पूरे कर लिए गए हों।

2 हम दि । . . (बैक) सरकार जहा और जैसा भी, सभ्य समय पर निवेश के, आयातक द्वारा सभ्य समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य या उस पर कोई भी भ्रष्ट जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमे उच सभरको को भुगतान करने की तारीख से पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर (येक्से पूर्वान्त सार्वजनिक सूचना) गणना किया हुआ व्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो १० से अधिक नहीं है, आयातको द्वारा भुगतान करने में देर होगी, तो उसकी भी क्षति से सरकार को दूर रखें और उसकी क्षतिपूर्ति करें। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अधिकार उसकी और से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के सबध्न में जो राशि हमारे (बैक) द्वारा दी जाती है, उस सबध्न में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर (बैक), अधिकतम और अनिवार्य होगा।

3 हम (बैक) भागे हस बात पर सहमत है कि सविका के अन्तर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर प्रायात के मूल्य में बढ़ि होने से या अधूरे भाल छुड़ाने की स्थिति में उसके मूल्य में बढ़ि होने की स्थिति में जैसा कि उपर्युक्त कहिका I में बताया गया है, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के प्रनुपात में बैक गारटी बाड़ की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम (बैक) आगे इस बात पर सहमत है कि इस गार्टी में जो कुछ दिया गया है, वे उत्तिकृत करार/सविका के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगा और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गार्टी में प्राने बाला सारा बकाया पूर्ण रूपेण चुकाता कर दिया गया हो और इसकी सारी मांगे पूरी न हो गई हो या उनमें न हो गई हो ।

5 इसमें उल्लिखित गारटी पर आयातक या दि... (बैक) के सविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारटी को प्रमाणित किए बिना आयातक और दि... (बैक) पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित करे। उपर्युक्त भासले के सदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो, इस गारटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए

नियम या सरकार की ओर से दी गई, कृष्ट या मायातक पर किए गए किसी तरह का अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात चाहे जो भी हो, जो जमानतों से सबधित हो, (बैक) पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पहुँचा।

6 अन्त में हम (बैक) यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित रूप में परामर्श पाए जिना भुद्वाकाल में इसकी गारटी को रद्द नहीं करेंगे।

7. हम (बैंक) सार्वजनिक सूचना स० 15-प्राईटी सी (पी एन)/72, दिनांक 28-1-1972 तथा सार्वजनिक सूचना स० 108 प्राईटी सी (पी एन)/72, दिनांक 21 जूलाई, 1972 तथा इसके बाद समय समय पर जारी की जाने वाली ऐसी ही सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार भवित्वित निष्क्रिय करने का भी अवन देते हैं।

8 इस गारटी के अन्तर्गत रुपए (इसमें व्याज तथा अन्य प्रभार भी शामिल है, इसे गारटी की धनराशि के 1% से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हमारी जिम्मेदारी है और यह गारटी दिन* मास 19 तक लागू रखी जाएगी। जब तक इस गारटी के अन्तर्गत 6 मास के भीतर लिखित रूप से मांगे पूरी नहीं कर सकते जाते, और जब तक उसके बाद तक दूसरे 6 मास के भीतर जो तक होती और उनकी मात्रा के लिए मुकवामा या कार्यवाही लागू न हो जाए, इस गारटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे और हम लोग इसके प्रत्यन्त निहित सारी जिम्मेवालियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे।

विन का दिनांक,
वास्ते (वैक)
श्री (नाम और घोहवा) के द्वारा
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी प्रांत से स्वीकृत
इस्ताक्षर

*यह तारीख उस तारीख में एक मास और जोड़ कर गिनी जाएगी जिस तारीख तक सभरको को सभी भुगतान पूरे कर देने की समाप्ति है। इण्णणी —स्टाम्प पेपर का भूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलाकार के द्वारा न्याय निर्णित किया जाना है।

भाग्यवत्— 5

सख्त्या—एफ 14()उख्त्य फ-3/7

भारत सरकार

विसं मंसालय

भाष्यिक शार्य विभाग

नई दिल्ली, विनाक

सेवा में

विकासशील देशों के लिए दि नीदरलैण्डस इन्वेस्टमेंट बैंक,

दिल्ली

नीदरलैंड्स

... लाख नीवरलैस्म गिलदर्स के ज्ञान के लिए समझोता
प्रिय महोदय गण,

प्राधिकार प्रस्तुति

મારુદ એ મારુ

सर्वश्री और हालैड के
सर्वश्री के बीच
चित्त यूक किए जाने वाले सीधे के सबै में अपने आज के आवेदनपत्र
के प्रसग में हम एकद्वारा निवेदन करते हैं कि और उपर्युक्त सविदा की
शर्तों के अनुसार
एन० एफ० एल० माल की धनराशि हालैड में सभरक को चुकाने के लिये
आपको बिना शर्स और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते हैं। यह निवेदन
किया जाता है कि उच सभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, पोतलदान
और अन्य वस्तवेज को
(आयातक के बैक)

सीधे भेज दिये जाए।

संभरकों को विकासशील दरों के लिए नीदरलैंड पूजी निवेद बैक
को उस जिले के जिसमें निर्यातिक स्थित है, नीदरलैंड व्यापार मण्डल
द्वारा जारी किए गए/प्रमाणित किए गए प्रमाण-पत्र की इस सबै में
दो प्रतियों प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत आने
वाले माल नीदरलैंड मूल के हैं।

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, वित मकालय, आर्थिक
कार्य विभाग (आर्थिक सहायता लेखा शाखा) जीवन दीप बिल्डिंग, पालिया-
मेंट स्ट्रीट, नई विल्ली को प्रभासारित करें। यह प्राधिकार पत्र
..... तक बैंध रहेगा।

कृत भारत का राजपत्रि

(

प्रतिलिपि
(आयातक के बैक को)

आयातक को मूल दस्तावेज रिहा करने से पहले उन्हे यह सुनिश्चय
कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 8 आईटीसी (पी एन) /76
दिनांक 17-1-1976 और ऐसे ही सार्वजनिक सूचनाएं जो समय समय
पर जारी की जाएं उनमें निर्धारित तरीके में मुद्रा विनियम की मिथित
दर पर गणना किए जाने वाले समतुल्य रूपए और उम पर संभरकों को
भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में धनराशि जमा करने की तिथि
तक सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आईटीसी/पी एन/76 दिनांक 16-6-76
में निर्धारित दरों पर व्याज जमा कूरा दिया गया है।

अनुबन्ध 6

भारत सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय
संख्या एफ-4()इन्स्ट्रू ई-3/
आर्थिक कार्य विभाग
नई विल्ली
विषय.—सामान्य प्रयोजन डच क्रेडिट के अन्तर्गत की गई सविदा प्रतिपूर्ति
प्रिय महादेव,
सर्वश्री
(भारतीय आयातक)
रूपए ()
..... (रूपए) के मूल्य के लिए गामान्य प्रयोजन डच
क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस में
दिनांक के मद्दे नागर बीमा-भाण्डा/

लागत एवं भाड़े की
() धनराशि के
लिए
के सभरण के लिए सर्वश्री

(विवेशी सम्भरक)
के साथ सविदा की है। सविदा की एक प्रति संलग्न है।

2. ऊपर के रूपए की धनराशि में से
भारतीय एजेट के कमीशन के रूप में
धनराशि भारतीय मुद्रा में भवा की जानी है। विवेशी मुद्रा में संभरण
को अदा की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विवेशी मुद्रा लोतो में से
अर्धयुक्त की जाएगी जिसकी आद में
धनराशि तक उच सामान्य प्रयोजन क्रेडिट में से प्रतिपूर्ति की जानी है।

3. आपको उनके बैकरों प्रधार्ति सर्वश्री
के माल्यम से सर्वश्री
के नाम में इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर
और बैंध आयात लाइसेंस के मद्दे, सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक
यू० सी ओ० बैक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई विल्ली को सूचना देते
हुए एक साथ पत्र लोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

4. मुद्रा विनियम नियंत्रक मैनुअल के खण्ड 7 पैरा 10 के अनुसार,
आपको यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि साथ पत्र की समाप्ति तिथि
संबंधित आयात लाइसेंस में वथा उल्लिखित पोतलदान के लिए अनिम्न
तिथि के पैतालीस (45) दिनों से ज्यादा नहीं है।

5. साथ पत्र में यह भी प्रावधान होगा कि सर्वश्री
(विवेशी सम्भरक)

अपरकाभ्य पोतलदान वस्तावेजों का एक सेट और बीजक की ओ प्रतियो
जो उच सम्भरक द्वारा इस प्रमाण पत्र द्वारा पूर्णकृत हो कि भुगतान
उनके द्वारा प्राप्त हो गया है, सीधे ही सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक,
कित मकालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैक बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली को भेजेगा।

जिस जिला में निवारित है उम जिले के नीदरलैंडस आपार मण्डल
से साथ पत्र के अन्तर्गत आने वाले माल के नीदरलैंड मूल के होने के
सबै में जारी किए गए/प्रमाणित किए गए/इस साथ पत्र के अन्तर्गत
आने वाले माल उद्यगम के सबै में उचित समर्थ प्राधिकारी द्वारा जारी
किए गए प्रमाण-पत्र की ओ प्रतियो भी वे प्राप्त करेंगे और नियंत्रक
सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेंगे।

6. आप को, यदि कोई हो तो बैक लबों को छोड़कर बीजक/माल
के पौतलदान के मद्दे आपके, द्वारा सर्वश्री
को किए गए¹ प्रेषण का एक प्रमाण पत्र भी सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, वित
मकालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैक बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली को भेजना होगा।

7. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीप

()

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

तथिका की प्रति के साथ प्रति इनको प्रेषित :—

1. भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा विनियम नियन्त्रण विभाग, वर्षाई-1

2. प्रति निम्ननिष्ठित को भी भूचनार्थ प्रेषित :—

(1)
(भारतीय आयातक)

यह सुमिष्टय कर लिया जाए कि मर्वंथी
(विवेशी बैंकर)

ने नियन्त्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय, अधिक कार्य विभाग यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भुगतान बीजक सहित पोतमदान और अन्य दस्तावेजों (अप्रकाश्य) का एक सेट, बीजक की दो प्रतियां जिस पर संभरक द्वारा यह प्रमाण-पत्र विधिवत पूळांकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां भेज दी गई हैं।

(2) मर्वंथी
(विवेशी बैंक)

आप से यह भनुरोध है कि प्रत्येक आदायकी पर भुगतान बीजक सहित पोतमदान और अन्य दस्तावेजों (अप्रकाश्य) का एक सेट बीजक की दो प्रतियां जिस पर संभरक द्वारा यह प्रबाण पत्र विधिवत पूळांकित हो कि उसके द्वारा भुगतान प्राप्त हो गया है और माल के उद्गम के बारे में प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां नियन्त्रक सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय, अधिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेज दी जाए।

(3) नियन्त्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा वित्त मंत्रालय, अधिक कार्य विभाग यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

मनुष्यान्थ 7

उच्च (सामान्य उद्देश्य) ब्रेडिट के प्रत्यर्गत उपयोग के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट को प्रदर्शित करने आला विवरण

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की संख्या संथा दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. लिए गए आवेदों का मूल्य
5. प्राधिकार-पत्र की संख्या और दिनांक
6. प्राधिकार-पत्र की धनराशि
7. प्राधिकार-पत्र की वैधता की तारीख
8. त्रैमासिक के द्वारा उपयोग की गई धनराशि उच्च गिल्डर
9. उपयोग की गई कुल धनराशि उच्च गिल्डर
10. मरकारी द्वारा में जमा की गई कुल धनराशि रुपये
11. आगामी त्रैमासिकों के द्वारा किया जाने वाला भुगतान
12. अवधिकार, यदि कोई हो

उच्च सामान्य प्रयोजन ब्रेडिट के प्रत्यर्गत सार्वजनिक धन आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए गते

खण्ड 1, सामान्य

1 (1) नीदरलैंडस इन्वेस्टरिंग्स बैंक वीर आंटविकलिंग्स संस्करण १० बी० द्वारा प्रदाने के लिए इच सामान्य प्रयोजन ब्रेडिट को विकासील देशों के लिए खोल दिया गया है। तदनुसार इस ब्रेडिट के प्रधीन वित्तयुक्त किए जाने वाले माल एवं पण्ड-वस्तुएं एवं इससे संबंध भानुष्ठानिक सेवाएं नीदरलैंडस से आयात की जा सकती हैं और परिषिष्ट 'क' के रूप में "नीदरलैंड द्वारा दिए विकास क्षण के प्रत्यर्गत माल और सेवाओं की प्रयोगप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन" सूची में सम्मिलित सभी देश (अनुबन्ध-1) इस ब्रेडिट के प्रत्यर्गत "पात्र लोग" देश होंगे। दोनों साथ करारों अर्थात् भी एक एल १.२० मिलियन और भी एक एल ५.४ मिलियन प्रतिपूर्वि की अंतिम तिथि ३१-१२-१९८० होगी।

1 (2) किन्तु पात्र के इतर स्रोत देशों से रसायन के संबंध में 10% की सीमा तक और अन्य आयातों के संबंध में 20% की सीमा तक के संघटकों को इस ब्रेडिट के प्रत्यर्गत वित्तवान किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है। यदि कोई ही तो इस संबंध में ब्रेडिट ग्रावेदत संविदा पूर्ण होने से पूर्व ही वित्तमन्नालय (अधिक कार्य विभाग) को किए जाने चाहिए।

1 (3) इस ब्रेडिट के प्रत्यर्गत वित्त वान के लिए पात्र स्रोत देशों से उपयुक्त खंड 1(2) में सकेति सीमा से अधिक संभरण को संपूर्ण बनाने के लिए पात्र से भिन्न देशों से माल और सेवाओं के सीमित सम्भरणों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए नीदरलैंडस की सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

खण्ड 2—आयात लाइसेंस जारी करना

2 (1) आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए सागत भीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा। वैध अवधि में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह वैध अवधि के भीतर ही सबद्ध लाइसेंसधारी से सम्पर्क स्थापित करे जो इस मासले में आधिक-कार्य-विभाग से परामर्श लेगा।

2 (2) प्रके प्रावेश नीदरलैंडस में समुद्रार संभरकों को या अनु-खंड 1 में उल्लिखित देशों को सागत भीमा भाड़ा/भागत तथा भाड़ा के आधार पर ग्रवश्य दिए जाने चाहिएं और आयात साइसेम के जारी होने की तारीख से 4 मास के भीतर ही अधिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-३ अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिएं। यदि प्रके प्रावेश देने का निर्णय निर्धारित चार मास की अवधि के भीतर नहीं हो पाता है तो लाइसेंसधारी को जाहिए कि वह जैसा भी मामला हो, मुख्य नियन्त्रक, आयात नियोत को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारियों को इसका कारण बताते हुए कि क्यों नहीं प्रारम्भिक वैध अवधि के भीतर ही आवेश देने का काम पूरा हो सका, इसके औचित्य एवं आवाया के साथ आदेश देने की अवधि में वृद्धि की मांग करने के लिए प्रस्ताव रखें। प्रावेश देने की ऐसी अवधि में वृद्धि के लिए आवेश पर विचार प्रत्येक मासले में पात्रता के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो और आर मास की अवधि की वृद्धि दे सकते हैं। लेकिन, यदि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 8 मास से अधिक की वृद्धि की मांग की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरावाद स्पष्ट से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा अर्थ कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-३ अनुभाग) वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए।

2 (3) लाइसेंस पर (उच्च सामान्य प्रयोजन ब्रेडिट) अंकित होगा और यह उस सार्वजनिक मूच्छों की मध्या का सकेत जारी किये जाने अनुरूप यह लाइसेंस शर्तें जारी की जाती हैं। प्रथम तथा द्वितीय प्रत्यय के लिए

लाइसेन्स कोड 'एम'/'एन' होंगे। इस लाइसेन्स कोड का उल्लेख सभी प्रतिवादी में होना चाहिए और साथ ही साथ भवया जमा करने समय रिजिस्ट्रेशन को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित प्रपत्र 'एम' में इसका उल्लेख होना चाहिए।

2(4) जैसे ही आयातक आयात लाइसेन्स प्राप्त करता है उसे चाहिए कि वह इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी के साथ विसंगतालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को एक रिपोर्ट भेजें:—

- (i) आयात लाइसेन्स की मंज्या और दिनांक
- (ii) मूल्य
- (iii) परिकोई हो तो आयात लाइसेन्स में संकेतित मुद्रा विनियम दर
- (iv) वह तारीख जिस तक आर्थिक कार्य विभाग को मंजिश की प्रतियोगी भेजने की संभावना है।

बंड 3—क्रेडिट को पूर्ण करना

3(1) इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तवान के लिए पाल संविदा का मूल्यम शूल्य ही एक एल—25,000 होगा।

3(2) आयात लाइसेन्स के मुहे एक संविदा की जाती चाहिए। विशेष मामलों में एक से प्रधिक संविदा करने के लिए अनुमति वी जाएगी जिसके लिए आयात लाइसेन्स जारी करने की तारीख के तुरन्त बाद ही विसंगतालय, आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

3(3) माल के आयात के लिए संविदा और नीदरलैंड से सेवाओं और पाल स्रोत देशों का निश्चय अनुबंध में यथा उल्लिखित माल और सेवाओं की प्रधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

3(4) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर माल और सेवाएं शौधारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी:—

- (क) जहां नीदरलैंड आयातों के लिए परस्परागत या केवल एक-माल स्रोत है; या
- (ख) जहां आयातों वा मूल्य ही एक एल 1.25 मिलियन से कम का है; या
- (ग) जहां ऐसी किया-विधि लागू नहीं है या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच करार किसी भी प्रधिक उचित किया-विधि के आधार पर संधरण के लिए संविधायूर्ण हो जाने के पूर्व ही निश्चित रूप से तय हो जाना चाहिए।

3(5) निम्नलिखित मामलों में शौधारिक बूली अंतर्राष्ट्रीय बोली का अनुराग लेना भी आवश्यक नहीं होगा:—

- (क) जहां क्रेता के पास अपने उपकरण के पर्याप्त मालकीकरण को बनाए रखने के लिए मुक्तियुक्त कारण है।
- (ख) उन मामलों में जहां विषयाधीन प्रधिप्राप्ति की प्रक्रिया के कारण योग्य संभरकों की सम्या सीमित है और क्रेता की मार्किट जानकारी ऐसी है कि उससे यह भावा की जा सकती है कि वह योग्य संभरकों को जानता हो।
- (ग) जहां भारतीय आयातकों और विवेशी संभरकों के बीच चल रहे वर्तमान सम्बन्ध और नीदरलैंड और/या विकासकील देशों में उपलब्ध और समरूप संभरकों के बीच को ध्यान में रखते

हुए कर्जवार यह समझता है कि आयात केवल मीदरलैंड से ही प्राप्ती होने चाहिए। ऐसे मामलों में माल और सेवाओं की प्रधिप्राप्ति के लिए यांग दशन (अनुबंध 1) की कठिका 31 से 39 में निहित प्रधिप्राप्ति का नियम प्रयोग जाना चाहिए।

3(6) निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मालमें में क्रेता किसी भी एकमात्र संभरक से सीधे ही माल छारी बना सकता है:—

- (i) वाणिज्यिक आयातक द्वारा प्रधिप्राप्ति में पंजीकृत ब्राइड नाम की वह पर्यवर्ती विभाग होती है जो आयातक द्वारा पुनः बेचने के लिए है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमन: प्राप्तिकृत वितरक है या आपारी है और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक है या विनियमित कर्ता है;
- (ii) वाणिज्यिक आयातक द्वारा प्रधिप्राप्ति में वह पर्यवर्ती विभाग होती है जो विनियमित प्रक्रियागत करने या अंतिम उत्पाद के सउजीकरण और पुनः बिक्री के लिए प्राप्ति की जाती है और जिसके लिए आयातक संभरक का नियमन प्राप्तिकृत वितरक है या आपारी है और जिसके लिए संभरक विनियमित कर्ता है;
- (iii) विशेष डिजाइन या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पुर्जे की अवलो-बदली का सुनिश्चय करने हेतु प्रधिप्राप्ति केवल एक व्योंत तक की जा सकती है।
- (iv) आयातक एक ऐसा विनियमित कर्ता है जिसके उपकरण और कच्चे माल का फार्मुला ऐसे कच्चे माल की, विशेष किस्म के साथ प्रधिक से प्रधिक उपयोग के लिए बनाए गए हैं जो केवल एक ही लोट से प्राप्त किए जा सकते हैं;
- (v) आयातक शौधारिक अंतर्राष्ट्रीय बोली के अंतर्गत मूल रूप से की गई प्रधिप्राप्ति को बढ़ावा द्याता है या फिर से उसे प्राप्त करना चाहता है वशर्त कि मूल प्रधिप्राप्ति की तुलना में अनुपूरक प्रधिप्राप्ति कम है, और कुछ प्रवासी पर ही की जाती है और जब मूल प्रधिप्राप्ति के संबंध में नियमित कार्य प्रभी चल रहा है या मूल प्रधिप्राप्ति के सुरक्षत बाद ही की जाती है;
- (vi) लोट का मूल्य ही एक एल 1.25 मिलियन से कम है।

3(7) परामर्शदाता कर्मी के चुनाव के लिए शौधारिक प्रतियोगी बोली किया विधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, भारतीय कर्मी द्वारा परामर्शदाता कर्मी को सुसाइटों के लिए नियंत्रण भेजने से पूर्व ही ऐसी भावी कर्मी की एक सूची विसंगतालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग) को भेजी जाती चाहिए। इसके बाद तूली नीदरलैंड की सरकार की भेजी जाएगी जो इसे स्वीकृति दे सकती है या परामर्शदाता की पसंद को रद्द कर सकती है। और नीदरलैंड में परामर्शदाता की क्षेत्र की जानकारी के आधार पर इस शूली को बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकती है।

3(8) जहां शौधारिक बूली अंतर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर माल की प्रधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव किए जाते हैं तो आयातक को चाहिए कि वह जैसे ही नियमित नोटिस भारतीय आपार प्रतिका या भारतीय नियम बुलेटिन में विज्ञापन के लिए भेजे जाएं उसी समय इसकी तीन प्रतियोगी को विसंगतालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई-3 अनुभाग), नई दिल्ली को प्रवेगत कराते हाएं भारत में नीदरलैंड के राज्यवाचास को भेज दें।

3(9) बंड 2(2) में उल्लिखित "पुष्टि आवेदन" शर्त का अर्थ है भारतीय लाइसेन्सधारी द्वारा विवेशी संभरकों को दिया गया वह प्रावेश या बाद वाले के पुष्टिकारण भावेव द्वारा विधिवत समर्पित हो या एक संविदा

जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकारियों पर आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकारियों के पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

3(10) यदि संविदा उच्च संभरक के माथ की गई तो संविदा के लागत बीमा भाइ/लागत एवं भाइ मूल्य को, उच्च गिल्डर में व्यक्त करना चाहिए और यदि संविदा पात्र लोत देशों के संभरकों के माथ की गई हो तो उसको भुगतान में व्यक्त करना चाहिए।

3(11) संविदा में भुगतान की व्यवस्था नकद आधार पर होनी चाहिए अथवा पोत-लदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर विदेशी संभरकों भारतीय आयातकों को किसी भी प्रकार की साक्ष-सुविधा उपलब्ध करने की स्वीकृति नहीं देंगे।

3(12) संविदा के मूल्य में सम्मिलित भारतीय अधिकारियों के कमीशन की धरमराशि को विशेष रूप से अंकित किया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान भारतीय अधिकारियों को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विदेशी मदा में प्रेषण स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के भाग के रूप में होंगे और इसलिए लाइसेंस के लिए बसूल किए जाएंगे।

3(13) कम आदेश और संभरक के पुष्टिकरण आदेश केवल प्राप्तेजी में ही होने चाहिए।

3(14) संविदा में निम्नलिखित व्यवस्थाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए:—

(i) संविदा भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। यदि संविदा का मूल्य उच्च गिल्डर में 50,000 या इससे कम हो (और यह भारत सरकार तथा नीदरलैंड सरकार दोनों के अनुमोदन के अधीन है यदि संविदा का मूल्य उच्च गिल्डर 50,000 से अधिक हो जाता है)

(ii) यह संविदा उच्च सामान्य प्रयोजन क्रेडिट के लिए लाइसेंस शर्तों के अंतर्गत दी गई भुगतान क्रिया-विधि द्वारा संचालित होगी और इस संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाव ही यह प्रभावी होगी।

(iii) “माल उच्च मूल्य/विनिर्माण के हैं” (नीदरलैंड में संभरकों के मामले में)

या

“माल मूल्य/विनिर्माण के हैं” (पात्र लोत देशों के संभरकों के मामले में)

(iv) नीदरलैंड से आयात किए जाने वाले माल के लिए संभरकों को नीदरलैंड जी निवेशक बैंक को उस जिले से नीदरलैंड आणिय भंडल द्वारा जिसमें संभरक स्थापित है जारी किया गया/प्रमाणित किया तुम्हा इस बारे में एक प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में देना पड़ेगा कि माल नीदरलैंड मूल का है। यह प्रमाण-पत्र भुगतान प्राप्ति करते समय अन्य पोत-लदान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रमाण-पत्र का एक नमूना अनुबंध-3 में दिया गया है।

पात्र लोत देशों के संभरकों के मामले में संभरकों को “माल और सेवाओं” की अधिप्राप्ति के लिए सार्व-दर्शन (अनुबंध-1) में दिए गए उद्गम में दिए गए उद्गम नियमों के अनुसार एन० प्राई० ओ० को माल के उद्गम का प्रमाण देना पड़ेगा।

3(15) जहां प्रथागत निष्पादन गारंटी के अपेक्षित हो वहां संभरकों से बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए।

बंड-4 भारत सरकार/नीदरलैंड पूंजी निवेशक बैंक द्वारा संविदा का अनुमोदन

4(1) संविदा पूर्ण होने के तुरंत बाद ही आयातकों को आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति के साथ संविदा/संभरक आवेदन की 5 फोटोया प्रमाणित प्रतिया आणिय मंद्रालय, आधिक कार्य विभाग (उच्चम् ई-3 अनुभाग) को भेजनी चाहिए। पात्र लोत देशों के संभरकों के साथ पूर्ण की गई संविदाओं के मामले में उसकी 8 प्रतियां भेजी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयातक के लिए अनुबंध-2 में उल्लिखित सूचना भी भेजना आवश्यक है।

4(2) यदि संभरक संविदा ग्रीष्मकारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली या ग्रीष्मकारिक चुनिन्वा अंतर्राष्ट्रीय बोली पर आधारित हो तब निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत की जानी चाहिए:—

(i) उम प्रकाशन का नाम जिसमें निविदा सूचना विवरित की गई थी।

(ii) उन पार्टियों के नाम जिन्होंने निविदा पूछताछ के मद्दे वाम बताए हैं।

(iii) विशिष्ट प्रस्ताव को चुनते के लिए नारण और यह भी बताया जाए कि यह संविदा न्यूनतम तकनीकी उपयुक्त बोली थी।

4(3) यह संविदा दस्तावेज, प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन, आयात लाइसेंस और बैंक गारंटी सही पाए जाते हैं तो वित्त मंद्रालय आधिक कार्य विभाग संविदा की प्रतियों को हेंग में भारत के राजदूतावास के माध्यम से उच्च प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजेगा।

4(4) (क) 50,000 उच्च गिल्डर या इससे कम मूल्य की संविदाओं के संबंध में उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के अनुमोदन के बारे में भारतीय आयातकों को उनकी संविदा संभरण आदेश की प्रतियों उच्च प्राधिकारियों को भेजते समय बता विद्या जाएगा।

4(4) (ख) 50,000 उच्च गिल्डर से अधिक संविदाओं के लिए जैसे ही उच्च क्रेडिट के अंतर्गत उच्च प्राधिकारियों द्वारा संविदा के वित्तदान के लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, आयातकों को यह सूचित कर विद्या जाएगा कि उनकी संविदा प्रभावी हो गई है।

बंड-5 संभरकों को भुगतान

(क) नीदरलैंड के संभरकों को भुगतान

5(1) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूंजी निवेशक बैंक द्विहेंग की एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध-7 के रूप में) हेंग में भारत के राजदूतावास के माध्यम से पोत-लदान दस्तावेज के मद्दे संभरकों के लिए भुगतान को प्राधिकृत करते हुए जारी किया जाएगा और संविदा आविकी की प्रतियों के साथ उसे उच्च प्राधिकारियों का अप्रत्रिपत्ति किया जाएगा।

5(2) प्राधिकार पत्र की बैधता का मुनिश्वय संविदा में विशिष्ट वित्तरण अमुसूखी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। किसी भी मामले में प्राधिकार पत्र आयात लाइसेंस की बैधता के बाव बैंक भेजी होगा।

5(3) चूंकि क्रेडिट के अंतर्गत सामान्यतः उच्च बैंक द्वारा संभरकों को भुगतान पोत-लदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के मद्दे दिए जाते हैं अतः इस क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान किए गए आयातों के लिए रियायती अवधि की सुविधा लागू नहीं होगी।

5(4) संभरकों को पोतलदान/भुगतान प्राधिकार पत्र की बैधता अवधि के भीतर पूरा न किया जाने के मामले में आयातकों की वित्त मंद्रालय, प्राधिक कार्य विभाग (उच्चम् ई-3 अनुभाग) के साथ प्राधिकार पत्र में अपूरुक वृद्धि के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। यदि मार्गी

गई वृद्धि भ्रात्यात् मूल आयात साइर्सेम की वैधता से अधिक हो तो पुनर्वैध मूल आयात लाइसेस की फोटो प्रति और बैंक से वह पत्र जिसमें बैंक गारन्टी की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है, आवेदन पत्र के माध्य में जी जानी चाहिए।

5(5) यदि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन प्राधिकार पत्र की वैधता तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो जाती तो प्राधिकार पत्र में अप्रयुक्त शेष धनराशि वापिस कर दी जाएगी और प्राधिकार पत्र भ्रात्यात् आप खत्म हो गया समझा जाएगा।

5(6) मूल परामर्श बोत-लदान दस्तावेज निरपवाद रूप से नीदरलैंड पूजी निवेशक बैंक द्वारा भारत में गवाहित आयातक के बैंक को भेजे जाएंगे। वह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक बैंक की शाखा होगी जिसे यह सुनिश्चय करने के बाद ही सबधित आयातक को परामर्श दस्तावेज रिहा करने चाहिए कि आयातक से निम्नलिखित को जमा कर दिया है—

(1) सार्वजनिक सूचना सं० ८-भाई० टी० सी० (पी० एन०)/७६ दिनांक १७ जनवरी, १९७६ में यथा निर्धारित और मूल्य नियमक, आयात-नियाति की सार्वजनिक सूचनाओं से समय-समय पर यथा अधिसूचित या रिजर्व बैंक आफ इडिया के मुद्रा विनियम नियमण परियों के माध्यम से गणना की जाने वाली प्रक्रियत दर पर इच्छा गिल्डर में सभरकों की भुगतान के समतुल्य रूप।

(2) विकासशील देशों के लिए नीदरलैंड पूजीगत निवेश बैंक एन बी द्विंदे देश द्वारा सभरकों को वास्तविक भुगतान की तारीख से आपातक द्वारा स्टेट बैंक आफ इडिया, टीस हजारी, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रूपये के वास्तविक निषेप की तिथि तक निश्चित जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि के लिए देखें उपर्युक्त (1) सार्वजनिक सूचना सं० ४८-भाई० टी० सी० (पी० एन०)/७६ दिनांक १६ जून, १९७६ के अनुसार प्रथम ३० दिनों के लिए ९% वार्षिक दर और ३० दिनों की अवधि से अधिक के लिए १५% वार्षिक दर के हिसाब से व्याज।

5(7) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित भारतीय बैंक की होगी कि आयातक को आयात दस्तावेज सीपने से पूर्व ही देय धनराशि सरकार के लेखों में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है। लाइसेस धारी को यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि बैंकों से दस्तावेजों की मुद्राओं को लेने से पूर्व ही देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखों में जमा करा दी जाती है।

5(8) सार्वजनिक क्षेत्र के आयातिकों को अपेक्षित रूपया निषेप केवल ब्रिटेनी मुद्रा विनियम के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से करता चाहिए और सार्वजनिक सूचना सं० १४४-भाई० टी० (पी० एन०)/६८, दिनांक ३० अगस्त, १९६८ में यथा अपेक्षित लाइसेम की मुद्रा विनियम नियमण प्रति भी उनके द्वारा पृष्ठाक्रिय करवा देनी चाहिए। अपेक्षित प्रपत्र “एस” सम्बन्धित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इडिया, बम्बई को भेज दिया जाएगा।

5(9) अब 5(6) में उल्लिखित धनराशि को स्टेट बैंक आफ इडिया, टीस हजारी शाखा, दिल्ली या रिजर्व बैंक आफ इडिया, नई दिल्ली के पास केंद्रीय सरकार के लेखों में निषेप के लिए निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा की जानी चाहिए—

“के—डिपोजिट एड एडवानसेज डिपोजिट नाट बियरिंग इन्ट्रेस्ट—
४४—सिविल डिपोजिट-स्टेट-डिपोजिट्स फॉर परवेजिस एसेस्ट
एड्स—परवेजिस एसेस्ट अडर इच जनरल परपज ट्रेडिट
१९७७-७८”

5(10) उपर्युक्त उल्लिखित रूपए निषेप की सूचना विस्त भ्रात्यारण, वार्षिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक ब्रिटिश, पार्लियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ सार्वजनिक सूचना सं० ७४-भाई० टी० सी० (पी० एन०)/७४, दिनांक ३१ मई, १९७४ और

सं० १०३-भाई० टी० सी० (पी० एन०)/७६, दिनांक १२-१० ७६ में निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किए गए मूल खाजाना चालान को भी भेजना चाहिए। प्राधिकार पत्र सं० के सबन्ध में सूचना, विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके लिए रूपया निषेप किया गया है, इच संभरक को भुगतान की तिथि, व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए इसकी गणना की गई है, निरपवाद रूप से राजकोष चालान में सकेतिक की जानी चाहिए।

(अ) पात्र स्रोत देशों को भुगतान

5(11) आयातक द्वारा उसके आवेदन-पत्र में यथा सकेतिक सभरक के नाम में पात्र स्रोत देश में सभरक के बैंक के लिए साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध १-८ के रूप में) विस्त भ्रात्यारण, वार्षिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई ३ अनुभाग) द्वारा खोला जाएगा। उपर्युक्त प्राधिकार पत्र की प्रति के साथ संदिवा की प्रतियां भी हेग में भारत के राजदूतावास द्वारा इच प्राधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।

5(12) पूर्व की कंडिकाप्रो में उल्लिखित प्राधिकार पत्र की पात्री के बावजूद आयातक का बैंक उक्त प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से ३० दिनों के भीतर और वधु आयात लाइसेस के मध्ये प्रपत्रे भैंकर के माध्यम से संभरक के नाम में एक साख पत्र खोलेगा। इस सम्बन्ध में सूचना सहायता देखा एवं विद्या परीक्षा नियमक, य०० सी० ओ० बैंक ब्रिटिश, पार्लियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

5(13) सभरक को भुगतान किए जाने के बाद सभरक का बैंक सहायता देखा एवं लेखा परीक्षा नियमक, विस्त भ्रात्यारण, वार्षिक कार्य विभाग, य०० सी० ओ० बैंक ब्रिटिश, पार्लियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को संभरक द्वारा विधिवत् पृष्ठाक्रिय प्रमाण-पत्र के साथ इस सम्बन्ध में पोलवान दस्तावेज के अपरकाम्य सेट और बीजक की दो प्रतियों को भेजेगा कि बावजूद से भुगतान प्राप्त हो गए हैं।

5(14) सभरको का बैंक संभरक के मालक के उदगम देश के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र या एक प्रमाण (दो प्रतियों में) इस सबन्ध में प्राप्त करेगा कि वह माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शने के लिए सलग उद्गम देश के नियमों के अनुसार है और उसे सहायता देखा एवं लेखा परीक्षा नियमक, विस्त भ्रात्यारण वार्षिक कार्य विभाग, य०० सी० ओ० बैंक ब्रिटिश, पार्लियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी।

5(15) आयातक को चाहिए कि वह यदि कोई हो तो बैंक प्रभारों को छोड़कर शीजक/माल के लदान के मध्य उनके द्वारा सभरक को किए गए ब्रेष्ट के एक प्रमाण-पत्र को सहायता देखा एवं लेखा परीक्षा नियमक, विस्त भ्रात्यारण, वार्षिक कार्य विभाग, य०० सी० ओ० बैंक ब्रिटिश, पार्लियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे। आयातक को यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि लदान दस्तावेज का एक परकाम्य सेट और बीजक की दो प्रतियों के साथ सभरक द्वारा भुगतान की पात्री के सम्बन्ध में विधिवत् पृष्ठाक्रिय प्रमाण-पत्र और अब ५(13) और ५(14) में उल्लिखित उद्गम प्रमाण-पत्र माल के लदान के सदान से १५ दिनों के भीतर विस्त भ्रात्यारण, वार्षिक कार्य विभाग, सहायता देखा परीक्षा नियमक, को भेज दिए जाते हैं।

5(16) आयातक द्वारा साख पत्र के मध्ये भुगतान आयात लाइसेस की मुद्रा विनियम नियमण प्रति के आधार पर किए जायेगे।

5(17) सामान्यत सभी लदान/सभरको के लिए भुगतान उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकार पत्र के जारी होने से २० मास की प्रतिधि के भीतर पूर्ण कर दिए जाने चाहिए। ऐसे मासों में जहां लदान/सभरको के लिए भुगतानों को २० मास की प्रतिधि के भीतर पूर्ण करने की सभावना न हो तो आयातक को चाहिए कि वह निरपवाद रूप से लदान/सभरको के

निए भुगतान को पूरा करने के लिए उपर्युक्त अवधि भीमा की समाप्ति से कम से कम एक मास पूर्व ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू.ई-3 अनुभाग) से मंपर्क स्थापित करे। इस प्रकार के आवेदन के साथ पुनर्वेद्ध आयात लाइसेंस की एक कोटी प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें मार्गी गई अवधि बृद्धि भी शामिल हो। यदि इस प्रकार का आवेदन निर्धारित अवधि से पूर्व ही प्राप्त नहीं होता है तो संविदा के प्रत्यक्षत रूप को अस्पष्टिकरण किया गया भवित्वा जाएगा।

5(18) आयातक की ओर से आर्थिक कार्य विभाग को शीघ्र ही प्रतिपूर्ति दस्तावेज भेजने में किसी भी ब्रूटि पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा और सुध्य नियन्त्रक, आयात-नियंत्रित को आयातक के नाम में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि आयातक बूक करता रहे तो उसका मामला मुख्य नियन्त्रक, आयात-नियंत्रित को काली सूची में लिखने के लिए भेजा जा सकता है।

5(19) प्रतिपूर्ति वस्तावेज की पावती के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक, वित्त मंत्रालय, नीदरलैंड पूर्जीगत बैंक को पाल भोत देशों से संभरकों को भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेगा। नीदरलैंड पूर्जीगत बैंक प्रतिपूर्ति की तारीख को नीदरलैंड में प्रदत्तिलाई मुद्रा दर पर नीदरलैंड गिल्डर में समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

खंड 6—विविध

6(1) आयातक को चाहिए कि वह लाइसेंस के उपयोग को दर्शाने हए अनुबंध 9 के रूप में लैमारिक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-3 अनुभाग) को भेजे।

6(2) इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई समझा उठता है तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होती। संभरक को भुगतान प्रभावी किए जाने से पूर्व ही उसके द्वारा पूर्ण भी जाने वाली भारत आयातक द्वारा साफ रूप से अनुबंध-2 में बता दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो झगड़े के निपटान से संबंधित एक व्यवस्था भी संविदा में शामिल की जाए।

6(3) लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस या इससे मंबन्धित किसी एक या सभी मामलों पर तथा इच्छा सामान्य प्रयोजन केंटिक के अंतर्गत सभी प्रकार के प्राभावों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियंत्रण, अनुबंधों और आदेशों का तुरन्त पालन करेगा।

6(4) उपर्युक्त केंटिक से दी गई शर्तों का उल्लंघन या प्रतिक्रिया करने पर आयात तथा नियंत्रण (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

खुलून्य-1

नीदरलैंड द्वारा द्विपक्षीय विकास व्यवस्था के अन्तर्गत माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्गवर्णन

क. सामान्य

1. ये मार्गवर्णन द्विपक्षीय अनु द्वारा को शासित करते हैं जो कि द्विपक्षीय नीदरलैंड विकास सहायता कार्यक्रम का एक भाग है। ये अनु विकासशील देशों के लिए उपलब्ध है। पाव स्वीकृत देशों की सूची परिणिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है। इस सूची में प्राप्तकर्ता देश इसमें शामिल है। नीदरलैंड की सरकार पाव स्वीकृत देशों से संभरण की कमी को पूरा करने के लिए पाव स्वीकृत देशों से इतर स्वीकृत देशों से वाहन और दीमा कीमों महिल माल और सेवाओं के सीमित संभरण के लिए व्यक्तिगत आधार पर सहमत हो सकती है।

2. नीदरलैंड की सरकार को इसके लिए अवश्य ही संतुष्ट हो जाना चाहिए कि अनु से प्राप्त लाभ का उपयोग, प्रथम व्यवस्था, वार्यक्षमता, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निषेधाता और पाव स्वीकृत देशों के बीच बिना किसी भेद-भाव को ध्यान में रखते हुए और इन मार्गवर्णनों में बताई गई अधिप्राप्ति कियाविधियों के अनुमार किया जाना है।

3. केंटिक 16 और 17 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं प्रयोगी जानी चाहिए जिससे यह पता चलता हो या यह परिणाम निकालता हो कि किसी एक विशेष देश के एक विशेष संभरक को या संभरकों का पक्ष लिया जा रहा है।

4. माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए अणी द्वारा अपनाए जाने वाले उद्यम के नियम और नियंत्रण इन मार्गवर्णनों के साथ परिणिष्ट 'ब' के रूप में संलग्न कर लिए गए हैं।

5. ऐसे मामले में जहां अणी पर अधिप्राप्ति का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह ऐसे अवस्थाएं करेगा जिसे यह मुनिष्कत करने के लिए आवश्यक है कि खरीददार इन मार्गवर्णनों का अनुपालन करता है।

6(1) अणी निम्नलिखित मामलों को छोड़कर औपचारिक खुलून्य अन्तर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से माल और सेवाएं प्राप्त करेगा:—

(क) जहां नीदरलैंड स परम्परागत या आयातों के लिए केवल एक-मात्र स्वीकृत है,

(ख) जहां आयातों का मूल्य ई०.५८०.१.२५ मिलियन से कम है,

(ग) जहां इस प्रकार की कियाविधि लागू नहीं होती या उपयुक्त नहीं है। इस मामले में नीदरलैंड सरकार और अणी देश के बीच करार किसी अन्य उचित कियाविधि से संभरकों को उनकी बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आवंतित करने से पूर्व ही पूरा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का करार राजकीय नीदरलैंड राजदूतावास के माध्यम से अणी द्वारा दी जाने वाली सभी सम्बद्ध जातकारी के आधार पर किया जाना है।

6(2) जहां भारतीय आयातों और विदेशी संभरकों के बीच कायम वर्तमान संबंध और नीदरलैंड द्वारा विकासशील देशों में उपलब्ध और अधिकार अन्तर्गत संभरणों के अवसर के प्रकार में अणी समझता है कि आयात केवल नीदरलैंड से ही प्रभावी किए जाने चाहिए तो खरीदार, केवल नीदरलैंड के लिए बोली को सीमित रखने के लिए या नीदरलैंड और साथ ही साथ पाव स्वीकृत देशों से शोलियां प्राप्त करने के लिए विकल्प रखेगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 31-33 के साथ मार्गवर्णन का अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 34-38 के साथ अनुच्छेद 30 लागू है।

7. ये मार्गवर्णन और साथ ही साथ उद्यम के नियम और पाव स्वीकृत देशों की सूची नीदरलैंड की सरकार के संशोधनाधीन हैं।

(ख) औपचारिक खुलून्य अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए किया विधि

8. बोली के लिए आमतंत्र जारी करते समय अणी (या अणी की ओर से खरीदार) निम्नलिखित दो प्रकाशनों में से कम से कम एक में शीली का विज्ञापन देगा:—

भारतीय आयात परिक्रमा

भारतीय नियंत्रित सेवा दुर्बिन

आयातक भारतीय आयात परिक्रमा या भारतीय सेवा ब्लेटिन में पथा विज्ञापित निविदा नोटिस की तीन प्रतियां भारत स्थित नीदरलैंड के राजदूतावास की भेजेगा।

9 प्रतियोगिता को व्यापक प्राप्तसाहन देने के लिए ऐसी अलग-अलग संविधाएँ जिनके लिए जब कभी सभव हो बोलिया आमतित की जाती है वह इतनी छोटी होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलिया को आवश्यित बन मजे। इसी तरफ यह कि यदि तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से एक परियोजना को विशेष प्रकार की संविधाओं में विभाजित करना सभव हो और इस प्रवार के विभाजन से अट्टी को लाभ हो और/या इससे प्रत्यर्षाष्ट्रीय प्रतियोगी बोली और भी विशाल बन जाए तो परियोजना विभाजित की जानी चाहिए। अभियानिक उपकरण और निर्माण कार्य (सामान्यतः 'टर्न की काल्ट्रेक्ट' के रूप में जाने जाने हैं) के लिए एक संविधाओं की बात की जा सकती है यदि वे उपलब्ध तकनीकी एवं आर्थिक सुविधाओं के भीतर अट्टी देश के लिए सम्पूर्ण लाभ प्राप्त करती हैं।

10 विशेषरूप से भिन्न कार्यों की संविधाओं के लिए औपचारिक पूर्व योग्यता की बात की जा सकती है। यदि पूर्वयोग्यता की बातों की जाती है तो वह इन बातों को ध्यान में रखत हुए पूर्णतः संतोष-जनक निष्पादन की क्षमता पर आधारित होनी चाहिए (1) इसी प्रकार के कार्य में फार्म का पूर्व अनुभव (2) कार्मिक, उपचरण एवं संयत क संबंध में इसकी क्षमता और (3) इसकी आर्थिक स्थिति और सम्भवता। पूर्वयोग्यता क्रियाविविध का विज्ञापन कड़िका 8 में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा। पूर्वयोग्यता के लिए विचार किए जाने वाले इच्छुक टेक्नोलॉजी के लिए संक्षिप्त विशिष्टकरण उपलब्ध कराए जाएं। जब पूर्वयोग्यता लागू हो जाती है तो वे सभी फर्म जो पूर्वयोग्यता की गतीयों को पूरा करती हैं बोली के लिए अनुमत होंगी।

11 बोली के दस्तावेज उन भाषाओं में से किसी एक भाषा में तैयार किए जाएंगे जो प्रत्यर्षाष्ट्रीय पत्र-व्यवहार में साधारणत प्रयोग की जाती है और जब तक धानूनी तौर पर रोक नहीं लगा दिया जाता इस बात का उल्लेख करेंगे उक्त भाषा दस्तावेज के मूल पाठ में लागू रहेगी।

12 विशिष्टकरण में किए जाने वाले कार्य, संभरण किए जाने वाले माल और सेवाओं तथा सुपुर्दिग्नी या संस्थापन की जगह के लिए जहाँ सक सभव हो साफ और मुस्लिम स्वप से बताया जाएगा। इस विशिष्टकरण के विषय के अनुकूल होनी, जहाँ वे अनुकूल नहीं होगी तो उसका मूल पाठ लागू होगा। विशिष्टकरण में मूल्यांकन के मिद्दात और बोलियों की तुलना में का उल्लेख करेंगे जो द्रव नेत्रों में लिए जाएंगे जब मूल्यांकन किए जाते हैं और बोलियों की तुलना की जाती है। विशिष्टकरण में इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए जिससे कि स्वतन्त्र और सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की स्वीकृति एवं प्रोत्साहन मिल सके।

किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी स्पष्टीकरण या गलतियों में सुधार और विशिष्टकरणों में परिवर्तन तथा बोली के लिए आमतंत्र से उनको योग्य ही अवश्यक करा दिया जाएगा जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया था।

13 यदि इस प्रकार के राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुमार ही उपकरण या माल होने आवश्यक हों, तो विशिष्टकरण में यह बताया जाएगा कि वे माल जो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानकों का प्रति करते हैं जिनमें उल्लिखित मानकों के अलावा उसके बराबर या अच्छी किसी की माग की गई शू सी वे भी स्वीकार किए जाएंगे।

14 यदि विशेष फालतू पूजी की अपेक्षा की जाती है या यह निष्पत्य किया जाता है कि कुछ अनिवार्य गुणकर्ता को बनाए रखने के लिए एक विशेष मालों के मानकीकरण की आवश्यकता है तो

विशिष्टकरण निष्पादन और क्षमता पर आधारित होगे और उनमें केवल तभी पजीकृत मार्क नाम, सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पाद निर्धारित होने चाहिए। अन्तिम मामले में विशिष्टकरण में विकल्प की उन मामलों के प्रस्तावों की लिए स्वीकृति वी जाएगी जिसमें मिलती जूलनी विशिष्टताएँ हैं और जिनका निष्पादन और बोलिटी कम से कम उन विशिष्टकृत स्तर के बराबर है।

15 बोली के लिए निमंत्रण में पात्र स्रोत देशों का उल्लेख किया जाएगा और उनमें उद्घम के लागू नियमों की बताया जाएगा।

16 कोटेशन की जाव पात्र स्रोत देशों के सभरको के बीच पूर्णत बराबरी की गतीयों के आधार पर की जाएगी (इसमें माल और उपकरण के लिए सीमा शुल्क टैरिफ और भ्रम्य करों और इसी प्रकार के प्रभावी करों की नियुल्क कीमतों पर कोटेशन के मूल्यांकन भी शामिल है) लेकिन, अट्टी देश माल और सेवाओं के सभरण के लिए बोली के मूल्यांकन और मिलान करने के लिए जिसमें परिवहन कीमतें शामिल नहीं हैं, स्थानीय माल और सेवाओं के लिए और उन अन्य पात्र स्रोत देशों के उत्पादों के लिए वरीयता की गुजाइश देने के लिए जो गट्ट में है या जो इस प्रकार के अंग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए, अन्य पात्र स्रोत देशों में उत्पन्न होने वाले माल और सेवाओं के लिए प्राधिकृत है। वरीयता की यह गुजाइश/मूलतम मूल्यांकित विदेशी बोली के लागत बीमा भाड़ा पर 15 प्रतिशत या बोलीकार के देश में सीमा-शुल्क करों के बरंमान स्तर, इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

17 विशेष मामलों में, अट्टी, नीदरलैंड्स सरकार और अट्टी देश के बीच आपसी परामर्श करके, कड़िका 16 में उल्लिखित वरीयता की गुजाइश के अतिरिक्त गट्ट के अनुकूल स्थानीय और भेदीय विनिर्माण-कर्ताओं के लिए वरीयता की सीमित गुजाइश को प्रदान कर सकता है। वरीयता की स्तर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय दर्जा या भेदीय स्थाप्य और प्रबंध तथा अट्टी देश के पजीकरण या इन विनिर्माणकर्ता कर्मों के भेदीय आर्थिक वर्ग जैसे तर्बो पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

18 बोली दस्तावेज में कोई भी सहमत वरीयताएँ प्रदर्शित की जाएंगी और बोली के मूल्यांकन और तुलना में जिस तरीके से उन्हें लागू किया जाएगा उसे भी बताया जाएगा।

19. बोलीकारों को पर्याप्त मम्य दिया जाएगा जिसमें वे अपनी बोलियों प्रस्तुत करेंगे।

20. बोलियों को प्राप्त करने और बोली को खोलने के लिए अन्तिम तारीख, मम्य और स्थान बोली के लिए नियमों में धोषित किया जाएगा और मभी बोलियों निर्धारित समय पर जनका के मामने खोली जाएंगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को बिना खोले ही लौटा दिया जाएगा। बोलीकार का नाम, प्रत्येक बोली या आवेदित या स्वीकूल यदि कोई विकल्पी बोली हो तो उसका कुल मूल्य ऊची आवाज में पढ़ा जाएगा और उनका रिकार्ड रख दिया जाएगा।

21 किसी बोलीकार को आलिया खुलने के बाद आगामी बोली में परिवर्तन करने के लिए स्वीकृत नहीं वी जाएगी। केवल बोली के मूल में परिवर्तन से भिन्न स्पष्टीकरण स्वीकार किए जा सकते हैं। अट्टी किसी भी बोलीकार को अपनी बोली में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। किन्तु किसी भी बोलीकार को बोली के मूल में या अपनी बोली के मूल्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

22 कानून द्वारा मध्य आरेक्षित को छोड़कर जाव से मन्दव और भी स्थान स्पष्टीकरण और बोली के मूल्यांकन सथा परिनिर्णय से सम्बद्ध मिकारिश, बोलियों के सार्थनिक रूप से खुलने के बाद सकत बोलीकार

के लिए संविदा के परिनिर्णय को घोषित करने से पूर्व किसी भी उस व्यक्ति को नहीं भेजी जाएगी जो श्रीगी की ओर से या नोवरलैंड्स की सरकार की ओर से इन कियाविधियों से श्रीपचारिक रूप से सम्बद्ध नहीं है।

23. बोलियों के खुलने के बाद खरीदार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या बोलियों के परिकलन में महत्वपूर्ण गलतियाँ की गई हैं, क्या बोलियों बोली वस्तावेज की आवश्यकताओं के पूर्णतया अनुकूल तो हैं, क्या अपेक्षित गारंटीयों और जमानतों वी व्यवस्था की गई है, क्या वस्तावेज सही रूप से हस्ताक्षरित कर दिए गए हैं और क्या वस्तावेज अन्यथा रूप से सही है, यदि कोई बोली वास्तविक रूप से विशिष्टीकरण के अनुकूल नहीं होती है या उसमें अस्वीकृत भावों हैं या अन्यथा रूप से वास्तव में बोली वस्तावेज के अनुकूल नहीं होती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

तब आधिक दृष्टि से विस्तृत निर्वारण के साथ तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा जिस से प्रत्येक अनुकूल बोली का मूल्यांकन किया जा सके और बोलियों को मिलाने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

24. बोली के लिए निम्नलिखित में बताया जाए कि खरीदार को ऐसी सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार है जब कई बोली विशिष्टीकरण के प्रयोजन के अनुकूल नहीं हैं और जब प्रतियोगिता के अन्वाव का प्रमाण मिलता है या निम्न बोलियों उम पूर्व अनुमानित अन्वारण की कीमत से अधिक होती है जो इस तरह की कारंवाई को उचित बनाने के लिए पर्याप्त है। यदि सभी बोलियों रद्द कर दी जाती हैं तो श्रीगी नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ऐसी स्थितियों के कारणों को और निम्न बोली और अनुमानित कीमत में अन्तर के कारणों को जानने के लिए एक या एक से अधिक न्यूनतम बोलीकारों के साथ सीधा कर सकता है विशिष्टीकरण में परिवर्तन को परावर्तित करने वाली तय की गई या सविदाएं जिन से परियोजना की अनुमानित कीमत में कमी हो सकती है उन्हें स्वीकार किया जा सकता है बनार्ते कि परिवर्तन परियोजना के स्वरूप को वास्तविक रूप से नहीं बदलते। जहां परिवर्तन वास्तविक है वहां पुनः बोली उचित हो सकती है। इसे हर बार बोलर-लैंड्स की सरकार द्वारा अनुमोदित करना होगा।

25. बोलियों के मूल्यांकन बोली वस्तावेजों में बताए गए नियम और यहाँ के अनुसार और बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से पूर्व हस्त से सम्बद्ध किसी भी आशोधन के अनुमान होने चाहिए। न्यूनतम मूल्यांकित बोली की स्पष्टी करने के प्रयोजनार्थ कीमत से निम्न तथ्यों जैसे नियम कार्य या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय उपकरण की कार्य क्षमता और विश्वसनीयता, हस्त की सुपुर्दी की समय और सेवा और कालजु पुर्जों की उपलब्धता को भी ध्यान में लिया जाएगा और जहां तक सम्भव हो सेवा मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा वे मुद्रा जिन में बोली कीमत का सुगतान किया जाएगा उन का मूल्यांकन केवल बोली के मिलान के प्रयोजनार्थ सरकारी साधन द्वारा प्रकाशित मुद्रा की दरों के आधार पर और बोली की अन्तिम तारीख को इस प्रकार के सौदे के लिए लागू दरों के आधार पर किया जाएगा।

26. संविदा का परिनिर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाएगा जिस की बोली पूर्व की कडिकारों में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्यांकित बोली नियित की गई हो।

27. अनुरोध करने पर नीदरलैंड्स की सरकार को अधिप्राप्ति के सभी पहलुओं पर अपनी टिप्पणी और सिफारिश प्रदान करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। संविदा का परिनिर्णय होने के बाद नीदरलैंड्स की सरकार को शृण के उपयोग के मूल्यांकन के लिए सभी सम्बद्ध वस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी (उनकी प्रतियोगी सहित) प्रदान की जाएगी।

(ग) श्रीपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय बोली से निम्न अधिप्राप्ति की किया विधि

28. कडिका 29 और 30 में उल्लिखित मामलों में कडिका 31-39 में उल्लिखित अधिप्राप्ति के नियम कंडिका 6 के अनुसार लागू ही सकते हैं।

मानकीकरण

29. जहां खरीदार के पास प्रपत्ते उपकरण के उचित मानकीकरण को बनाए रखने के लिए विवरणीय कारण हैं।

मोबाइलरकों की सीमित संख्या

30. उन मामलों में जहां विषयाधीन अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के कारण योग्य समरकों की संख्या सीमित है और खरीदार की मार्किट जानकारी ऐसी है कि उम से आमा को जा सकती है कि योग्य समरकों के बारे में जाने।

31. श्रीपचारिक खुलिया अन्तर्राष्ट्रीय बोली

सामान्य खुलिया अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्वर्गत खरीदार उन सीमित संख्या के (पूर्व) योग्य समरकों से बोलियों आमत्रित करने के लिए प्राप्तिहृत है जो विषयाधीन अधिप्राप्ति की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य समझे जाने हैं।

ऐसे मामलों में श्रीगी को यह सुनिश्चित कर लेगा चाहिए कि किसी भी समानित योग्य समरक को छोड़ ही दिया गया है। अब और ऐसे वे विलं यंत्रालय (आधिकारिक आर्थ विभाग) भारत सरकार, से पात्र स्रोत देशों के समानित संभरकों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी जिस से कि वे उचित आधार पर भाग लेने में समर्थ हो सके।

32. संभरको का चुनाव केवल उन की योग्यताओं के आधार पर किया जाना है और जहां तक समर्थ हो वे नीदरलैंड्स सहित अनेक पात्र स्रोत देशों से चुने जाने हैं।

33. कडिका 8 में उल्लिखित से भिन्न श्रीपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से साधू की जानी हैं।

34. श्रीपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति

यदि श्रीपचारिक प्रतियोगिता बोलों की कियाविधियों के माध्यम से अधिप्राप्ति नहीं होती है तो यह संतोषजनक वाणिज्यिक नीति के अनुमान और पात्र स्रोत देशों के बीच विना फिरो के भेदभाव के प्राप्त करनी चाहिए।

35. आयानक को अनोन्चारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति के हिच्छित उत्तरोग का विस्तृत और समयोदित प्रवार करना चाहिए। पात्र स्रोत देशों के समरक जब भी ऐसे सूचना मार्गें तो वे वित मत्रालय (आधिकारिक कार्य विभाग), भारत सरकार उन को न्यायोचित आधार पर भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए मध्ये अधारश्वर के अनुमति देने के लिए अधिकारी देनी होंगी।

36. दो और प्रस्तावों की तैयारी के लिए अनुमित समय शामिल की गई संविदाओं के स्वरूप द्वारा नियमित किया जाएगा। साधारण सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अनुमति देने के लिए समय और वितरण दोनों की अनुसूचियों पर्याप्त लम्बी होगी।

37. कुछ विशेष मामलों में नीदरलैंड्स सरकार भूलभाव के प्राप्त किए गए ये इस के पूर्ण और सहित विक्रय किए गए मात्र, शामिल किए गए संभरकों और प्राप्त मूल्य दरों के सबध में विकेनाओं से सूचना मात्र सकती है।

38. श्रीपचारिक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए पूर्ण संभव सीमा तक योग्यता भारी दर्दन लाभ होना चाहिए।

39. एक मात्र संभरक

निम्नलिखित मामलों में से किसी एक मामले में केता को किसी एकमात्र संभरक से सीधे ही काय करने की अनुमति दी जाती है :

- (1) एक वाणिजिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पंजीकृत आगार विक्रित नाम वाली पूर्णवस्तु शामिल होती है जो आयातक द्वारा पुन विक्री के लिए हो, जिस के लिए आयातक संभरक का नियमित प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक एकमात्र वितरक या विनिर्माता हो।
- (2) एक वाणिजिक आयातक द्वारा वह अधिप्राप्ति जिसमें वह पूर्णवस्तु शामिल है जो विनिर्माण समाधान या सरोजन और उन अन्तिम उत्पाद के पुनः विक्रय के लिए अधिप्राप्ति को जाती है जिसके लिए आयातक संभरक का नियमित रूप से प्राधिकृत वितरक या व्यापारी हो और जिसके लिए संभरक विनिर्माता हो।
- (3) पुर्जे की विनियमणीजनन का मुनिशय करने के लिए या विशेष डिजाइन या सकनीकी आवश्यकताओं के कारण अधिप्राप्ति के विल एक ही स्रोत से पूर्ण को जा सकती है।
- (4) केता वह विनिर्माता हो जिसका माज मामान और कच्ची सामग्री का कार्मुला कच्ची सामग्री की उप विशेष किलम के जिस सर्वोत्तम उपयोग के लिए बनाया गया हो जो केवल एक ही स्रोत से प्राप्त की जा सकती है।
- (5) यदि संभरक ग्रोपचारिक ग्रन्टरिट्रीय बोली के अधीन मूल स्पष्ट में प्राप्त की गई अधिप्राप्ति को बढ़ाना या दुहराना चाहता हो तब उसके के संभरक अधिप्राप्ति मूल अधिप्राप्ति के मुकाबले में छोटी हो, केवल कुछ ही अवसरों पर पूर्ण की जाती हो और जब मूल अधिप्राप्ति से सर्वंधित निर्माण कार्य उस समय भी चल रहा हो या मूल अधिप्राप्ति पूर्ण करने के थोड़े समय बाद पूर्ण की जाती हो।
- (6) यदि सौदे का मूल्य डॉ० एफ० एल० 1.25 मिलियन से कम हो।

(घ) परामर्शकों के उपयोग के लिए नार्मदार्शन

40. परामर्श देने वाली नियोजित संस्थाएँ इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए कि उन का परामर्श डिजाइन, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा तैयार किए गए बोली के दस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिजिक या ग्रोपचारिक पक्षपात से मुक्त हों और वे प्रतियोगिता के आधार का अनुपातन कर सकती हो। स्थानीय परामर्शदाती संस्थाओं पर विचार करते समय राष्ट्रीय स्थानिय का स्तर प्रबंध और कामिक तथा पंजीकरण जैसी आत्मा पर उचित ध्यान देना चाहिए।

41. परामर्शदाती संस्थाओं के चयन के लिए ग्रोपचारिक प्रतियोगिता बोली कियाविधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन की प्रक्रिया में अर्णी को उन प्रत्याशित संस्थाओं का यथोचित संख्या पर विचार करना चाहिए जिनसे कई पात्र स्रोत देशों से समर्थ और स्वतंत्र सेवाएँ प्राप्ति करने की आगा की जा सकती हो। यह सूची निम्नलिखित बोली को ध्यान में रखते हुए पूर्व गुणों पर ध्यानित होगी।—

- (1) कार्य की समान किस्मों में संस्था का पहला अनुभव।
- (2) कर्मचारियों, साज-सामान और संयंक के संबंध में इस संस्था की क्षमता।
- (3) इसकी वित्तीय स्थिति और सबस्क्राप्ट।

यह बांधनीय है कि प्रस्तावों के लिए निमंदण भेजने से पहले अर्णी प्रत्याशित संस्थाओं की सूची नीदरलैंड्स सरकार को प्रस्तुत करे। नीदरलैंड्स सरकार को परामर्शी के चयन को अस्वीकार करने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त वह नीदरलैंड्स में परामर्शदाती थेट्र में अपनी जानकारी के आधार पर यह सुझाव दे सकती है कि इस सूची में बुँदि की जाती है।

(घ) शिकायतें

42. खरीदार बोली के संबंध में बोलियों को प्रस्तुत करने और संविदाओं के प्रदान करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सुनने और उनकी जाच करने की व्यवस्था करेगा।

43. ग्रोपचारिक बोली कियाविधि के अन्तर्गत की गई खरीद के मामले में बोली समाप्त होने की निधि से पूर्व किए गए प्रतिबन्ध एवं वस्तु विशिष्टिकरण या आमत्रण की प्रतिबन्ध अवधि के सम्बन्ध में विषयवस्तु की किसी भी शिकायत का समाधान बोलियों के खुलने से पूर्व ही किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो नीदरलैंड्स सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही उचित अवधि के लिए बोली के लिए अन्तिम तिथि स्थगित की जाए।

44. जब शिकायत संबद्ध संभरकों में से किसी एक के द्वारा की गई है तो शिकायत के विषय से मंबंधित और इस पर की गई कारंबाई से संबंधित वस्तावेज नीदरलैंड्स सरकार द्वारा और अर्णी द्वारा जाच के लिए उपलब्ध होगे।

परिशिष्ट 'क'

विकासशील वेसों को संयुक्त द्विपक्षीय श्रण के लिए पात्र स्रोत वेसों की सुवो

क. नीदरलैंड्स

ख. अर्णीका

उत्तरी सहारा

अर्जीरिया

लीबिया अरब गणराज्य

मोरक्को

तूनीसिया

मिस्र

विक्टोरी सहारा

ओटस्काना

बुरुण्डि

कैमोरून

केप वर्दी बीप समूह

मध्य अफ्रीका गणराज्य

चाव

कोमोरो द्वीप समूह

कांगो (जनवादी गणतंत्र)

जैरी गणराज्य

द्वीपी

इथोपिया

गेंदोन

जम्बिया

घाना

गिनी

गिनी बिसांड

आइबोरी कास्ट

कीनिया

सिशेथो

लाइबीरिया

मालागसी गणराज्य

मलायी

मार्सी

मार्टिनिया

मारिशस	पश्चिमा
नाइजीर	मध्य-पूर्वी
नाइजेरिया	बहरीन
रियूनियन	ईरान
स्थान्ता	ईराक
सेनेगल	इजराइल
सैचेन्ज	जोर्डन
सिवरा लेप्रोन	कूवैत
सोमालिया	लेबनान
टर, कार और इमास	ओमन
सैट हैलेन और हेन्डेमिज	वल्लार
सूडान	सऊदी अरब
स्वाजीलैंड	यमन (जनवादी प्रजातंत्र गणराज्य)
तन्जानिया	सीरिया (प्रखण्ड गणराज्य)
टोगो	यमन (अरब गणराज्य)
उगान्डा	इकिरी
अवर बोल्टा	अफगानिस्तान
जाम्बिया	बागला देश
अमेरिका	भूटान
उत्तरी एवं मध्य	बर्मा
बहमास	भारत
बारबेडोम	मालदिव
बरमूदा	नेपाल
कोस्टा रिका	श्री लंका
ब्यूटा	पाकिस्तान
डौमिनिकन (गणराज्य)	सुहूर पूर्व
ई। सैलवाडोर	ब्रूनी
गुडलोप	ईमर गणराज्य
गुआडालाका	हांग-कांग
हेटी	इंडोनेशिया
होन्दुराज (ब्र)	कोरिया (गणराज्य)
होन्डरस (बी० आर०)	कोरिया (जनवादी प्रजातंत्र गणराज्य)
जार्मन्का	लाओस
मार्टिनिक	मैको
मैकिस्को	मलेशिया
नीदरलैंडस अन्टीलीज	फ़िलीपिन्स
निकारागुआ	सिगापुर
पनामा	थाईलैंड
सैट पैरी/एट मिल्युलोन	सिमोर
एट टोबागो	वियनताम (गणराज्य)
बेस्ट हंडीज (बी० आर०)	वियनताम (प्रजातंत्र गणराज्य)
इकिरा	सामूहिक
अजेंटोना	फ़िजी
क्लीनीडाड हट टोबागो	मिलबर्स्ट एवं एलिस वीपसमूह
बोलीविया	फ़ैज़ पोलिनेशिया
ब्राजील	क्यू ईसेंडोनिया
चिली	न्यू हेबराइज़ (बी० आर० एण्ड एफ० आर०)
कोलम्बिया	पेसेकिक वीपसमूह (यू० एस०)
इक्साडैर	पैपो न्यू शिनी
काकलैंड द्वीप समूह	सोलोमन द्वीप समूह
गुयाना	टोगा
गिनी (एफ० आर०)	वालिज औ फ़तुना
पारागुये	पश्चिमी सामोआ
पीरु	यूरोप
सूरीनाम	टर्की
युक्रेन	पुर्तगाल
बीनेजयुला	

परिशिष्ट 'ए'

उद्गम के नियम

1. उद्गम के हन नियमों की विवराधीन मर्दे स्रोत देशों में उत्पादित माल और सेवाएं होगी ।
2. माल के मामले में नीवरलैंड्स के उद्गम का निर्धारण इस भेद में उम विधान के अधीन होगा जोकि यूरोपीय भूमुदाय में लागू है ।
3. पैरा 2 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण नीवरलैंड्स के वर्णित अंडल द्वारा जारी किए गए उद्गम के प्रमाण-पत्र के माध्यमें जाएगा ।
4. माल के मामले में, विकासशील देशों के उद्गम का निर्धारण उस उद्गम नियम के अधीन होगा जो अधिमान्यता सामान्य प्रणाली की रूप-रेखा में यूरोपीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई हो ।
5. पैरा 4 में उल्लिखित माल के उद्गम का प्रमाण विकासशील देशों के प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रपत्र 'ए' (जो अधिमान्यता की सामान्य प्रणाली के उपयोग में लाया जाता है) उद्गम के प्रमाण-पत्र द्वारा भेजेगा ।
6. सेवाओं के मामले में (अवर्त भावन-वर्तन का पैरा 1) उद्गम का निर्धारण नीवरलैंड्स सरकार और जहू लेने वाले देशों के बीच आपसी परामर्श के तहत आधार पर किया जाएगा ।
7. ऐसे मामलों में जहां उद्गम के नियमों से वास्तव में कोई समस्या पैदा हो जाती है या जहू लेने वाले देश को गम्भीर आर्थिक घाटा हो जाता है (उदाहरणार्थ बहुत से सम्भावी संभरणों पर जबरदस्त प्रतिबन्ध) तो हन नियमों से छुटकारा पाने को स्वीकृति दी जा सकती है किन्तु यह केवल नीवरलैंड्स सरकार एवं जहू लेने वाले देश के बीच आपसी परामर्श के बाव दी जा सकती है ।

अनुबन्ध-II

(ए) भारतीय आयातक का नाम और पता और/या जहां आवश्यक हो परियोजना अधिकारी का नाम और पता

(बो) संभरक का नाम और पता । यदि संभरक पाव स्रोत देश के हैं तो उस मामले में निम्नलिखित सूचनाएं भी जेजी जानी चाहिए:—

- (i) राष्ट्रिकरण
- (ii) पाव स्रोत देशों के द्वारा रखे गए शेयरों का प्रतिशत

(सी) (i) आयात लाईसेंस की संख्या और दिनांक

(ii) मूल्य

(डी) (i) नीवरलैंड्स/पाव स्रोत देश में संभरक के बैंक का नाम और पता

* (ii) भारत में आयातक का बैंक (वह यह बैंक होगा जिसने बैंक ग्राहकी दी है)

** (iii) भारत में आयातक का बैंक जो कि आयातक के लिए पोतलदान वस्तावेज दिला करते से पहले भारत के लिए रुपया जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(ई) डब गिल्डरस में या पाव स्रोत देश की मुद्रा में संविदा प्रादेश का मूल्य

(एफ) अधिप्राप्ति की विधि, क्या यह सीधे खरीद पर आधारित है या ग्रोप्पारिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय बोली पर या चयन कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय

*निजी क्षेत्र के लिए ।

**सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ।

बोनी के आधार पर जिस मामले में यह संकेत किया जाना चाहिए कि क्या संविदा यदि कोई हो तो उन कारणों के साथ अनुत्तम तकनीकी उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई है ।

(जी) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(एच) माल का उद्गम—यदि कोई हो तो गैर-पाव स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत

(आई) सुपुर्वी को पूरा करने की संभावित सिधि

(जे) भुगतान की शर्त और भवावित वह तिथि जिस विन इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़ेगी

(के) पोष-लद्धान वस्तावेजों की विस्तृत सूची, जैसे अवतरण बिल, बीजक, उद्गम प्रमाण-पत्र आदि जिसे विकासशील देशों के लिए नीवरलैंड्स पूंजी निवेश बैंक या पाव स्रोत देश में संभरकों के बैंक को चाहिए कि संभरकों को भुगतान करने से पहले अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज की प्रसिद्धि के साथ माग करें

(एल) यह संविदा में शामिल है तो भारतीय एजेंट का वह कमीशन (ठीक-ठीक धन-राशि संकेत की जाना है) जिसे प्राधिकार-पत्र जारी करने समय संविदा के मूल्य में से घटाना पड़ेगा, इस प्रकार का कमीशन का भुगतान भारतीय एजेंटों को रुपये में आयातकों द्वारा सीधे ही किया जाएगा ।

(एम) वह मूल्य जिसके लिए प्राधिकार-पत्र अपैक्षित है

(एन) वह मूल्य जिसके लिए विवरण अपैक्षित है

(ओ) यदि कोई हो, तो विशेष अनुदेश ।

अनुबन्ध-III

इच्छेविट

संविदा प्रमाण-पत्र

संविदा के अधीने

भारतीय आयात लाईसेंस की सं०

1. संविदा की संख्या एवं दिनांक
2. खरीदार को संभरित किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के अधीने
3. खरीदार को चुकाई जाने योग्य कुल संविदा कीमत (लागत बीमा भाड़ा लागत एवं भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का संकेत कीजिए) दी एफ़०माई०
4. नीवरलैंड्स में उत्पन्न नहीं किए गए माल का जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत किन्तु यह उस माल की खरीद संभरक द्वारा सीधे ही विदेशों से की गई है अर्थात् विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित या संघटकों का प्रतिशत
- (क) प्रतिशत जहाज वर निःशुल्क मूल्य
- (ब्र) मर्दों का विवरण एवं संक्षिप्त विशिष्टिकरण

5. यदि सेवाओं का संभरण किया जाना है तो निम्नलिखित खंड की भी पूर्ति की जानी चाहिए।—
6 किए जाने वाले किसी काम का अनुमानित मूल्य या (क) आपकी फर्म (साइट हंजीनियर प्रभाग आदि)
(ख) स्थानीय संभरक द्वारा खरोदार के देश में निष्पादित की गई सेवा का उल्लेख कीजिए।
7. उपर्युक्त कांडिका 4 और 5 के संबंध में यथा आवश्यक अर्हक टिप्पणियाः
8. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं संभरक द्वारा या नीचे उल्लिखित द्वारा नीदरलैंड्स में नियुक्त किया गया हूँ और इस प्रमाण-पत्र पर हस्तांकर करने का मुझे अधिकार है। एतद्वारा वचन देता हूँ कि उपर्युक्त कांडिका 4 और 5 में उल्लिखित माल एवं सेवाओं से भिन्न और किसी भी ऐसे माल या सेवा का इन सरियाँ के निष्पादन में संभरक द्वारा संभरण नहीं किया जाएगा जो नीदरलैंड्स मूल के नहीं है।
हस्ताक्षरित
ओहदा
संभरक का नाम और पता
दिनांक
नीदरलैंड्स वाणिज्यिक मंडल

सेवा में

शिकासशील देशों के लिए दि नोदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट बैंक, दि हैग,

नीदरलैंडस

लाभ नीदरैंडम गिल्डसे के अहन के लिए समझौता

प्राधिकार-पत्र संख्या
भारत को आपके बैंक द्वारा दिए गए अरुण में से भारत के सर्वश्री
..... और हालैंड के सर्वश्री
..... के बीच वित्त युक्त किए जाने वाले सीधे के सम्बन्ध में अपने आज के प्राक्षेदनपत्र के प्रसंग में हम एतद्वारा निवेदन करते हैं और उपर्युक्त संविदा की शर्तों के अनुसार
..... एन० एफ० एल०
मात्र की धनराशि हालैंड में संभरक को चुकाने के लिए आपको बिना शर्तें और बिना परिवर्तन के प्राधिकृत करते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि इच संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, पोतलदान और अन्य वस्त्रावेज को सीधे भेज दिए जाएं।

(आयातक के बैंक)

संभरकों को विकासशील बैणों के लिए नीदरलैंड्स पूजी निवेश बैंक को उस जिले के जिसमें निर्यातिक स्थित हैं, नीदरलैंड व्यापार मंडल द्वारा ~~प्रयोगिक~~ गण/प्रमाणित किए गए प्रमाण-पत्र की इस सम्बन्ध में दो प्रतियोगी प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्राधिकार-पत्र के अन्तर्गत आवे वाले माल नीदरलैंड्स मल के हैं।

कृपया नामे डालने की सूचना भारत सरकार, विस मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आर्थिक सहायता देखा शाखा) जीवन द्वीप बिल्डिंग, पार्लियमेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को प्रगतास्ति करे। यह, प्राधिकारा-पत्र
..... तक वैध रहेगा।

हुते भारत का राष्ट्रपति

()

प्रतिलिपि

(आधातक के बैक को)

आधातक घो मूल वस्तावेज रिहा करने से पहले उन्हे यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 8 प्राई०टी०सी० (पी०एन०) / 76, दिनांक 17-1-1976 और ऐसी ही सार्वजनिक सूचनाएं जो समय-समय पर जारी री जाएं उनमें निर्धारित तरीके में मुद्रा विनियम की भिन्नत दर पर गणना किए जाने वाले समतुल्य रूपए और उस पर संभरकों को भुगतान की तिथि से सरकारी लेख में घनराशि जमा करने की तिथि तक सार्वजनिक सूचना स० 46-प्राई०टी०सी० (पी०एन०) / 76, दिनांक 16-6-76 में निर्धारित दरों पर ब्याज जमा कर दिया गया है।

संस्कृत → V

संख्या एफ-4 () संख्या ई-3/.

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

(प्राचिन कार्य विस्तार)

विषय:—सामान्य प्रयोजन उच्च क्रेडिट के अन्तर्गत की गई संविदा—प्रतिपूलि
प्रिय महोवय,

सर्वश्री द्वे

(સાધીન પ્રદાન)

विजय शर्मा (१९८८)

रुपए) के मूल्य के लिए सामान्य प्रयोजन उच्च फ्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए साइर्सेस संस्था
दिनाक के मद्दे लागत बीमा भाड़ा/
लागत एवं भाड़े को
(.....) धनराश के लिए

के सम्भरण के लिए सर्वाधीन (विवेशी संभरक) के साथ संविदा की है। संविदा की एक प्रति संलग्न है।

2. ऊपर के रपए की धनराशि में से भारतीय प्रैंट के कमीशन के रूप में धनराशि भारतीय मुद्रा में अदा की जानी है। विदेशी मुद्रा में सम्भरक को अदा की जाने वाली धनराशि प्रथमतः मुक्त विदेशी मुद्रा स्रोतों में से अर्थयुक्त की जाएगी जिसको बाद में धनराशि तक छच सामान्य प्रयोजन कैटिंग में से प्रति पूर्ति की जानी है।

II (3) Limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries in excess of the limit indicated in Section I (2) may also be considered for financing under the credit. For this, specific approval of the Government of Netherlands will be necessary.

Section II—Issue of Import Licence

II (1) The import licence will be issued on C. I. F. basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned within the validity period of the licence who shall consult the Department of Economic Affairs, (W. E. III Section) in the matter.

II (2) Firm order on CIF/C&F basis must be placed on the overseas suppliers in the Netherlands or the countries mentioned in Annex-I and sent to the Department of Economic Affairs, (W. E. III Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. If firm orders cannot be finalised within the time limit of 4 months the Licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period furnishing justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such request for extension in the ordering period will be considered on the merits of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (W. E. III Section), Ministry of Finance.

II (3) The licence will bear the superscription 'Dutch General Purpose Credit' and indicate the public notice number under which these licensing conditions are issued. The licence code for the first and second suffix will be "S"/"NN". This licence code will be mentioned in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Reserve Bank at the time of rupee deposit.

II (4) As soon as the importer receives the import licence, he should send a report to that effect to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W. E. III Section) along with the following information :

- (i) No. and Date of Import Licence ;
- (ii) Value ;
- (iii) Exchange rate, if any, indicated on Import Licence ;
- (iv) Date by which copies of contract are expected to be furnished to the Department of Economic Affairs.

Section III—Finalisation of Credit

III (1) The minimum value of contract eligible for financing under the credit is Dfl. 25,000.

III (2) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract will be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

III (3) The contract for the import of goods and services from the Netherlands and eligible source countries should be finalised keeping in view the Guidelines for Procurement of Goods and Services as detailed in Annex-I.

III (4) Goods and services should be procured through Formal Open International Bidding except in the following cases :

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ; or
- (b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million ; or
- (c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the Government of India on another more expedient procedure must be reached before the contract for the supplies could be finalised.

III (5) It would also not be necessary to resort to Formal Open International Bidding in the following type of cases :

- (a) where the purchaser has convincing reasons for maintaining reasonable standardisation of this equipment.
- (b) in cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.
- (c) where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only.

In such cases the procurement formula of paragraphs 31 to 39 of the Guidelines for Procurement of Goods and Services (Annex-I) may be followed.

III (6) The purchaser may purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorised distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer ;
- (iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source ;
- (iv) the importer is a manufacturers whose equipment and raw material formulae are designed for best utilisation with a specific type of raw material which can only be obtained from one source ;
- (v) the importer wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made ;
- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

III (7) Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, before invitations for preposals are sent out by the Indian firms to the consultant firms, a list of such prospective firms should be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W. E. III Section). The list in turn will be submitted to the Government of Netherlands who may approve the same or reject the choice of a consultant and may on the basis of their knowledge of the consultancy sector in Netherlands suggest that this list is extended.

III (8) Where the goods are proposed to be procured on the basis of Formal Open International Bidding, the importer should forward three copies of the tender notices as soon as these are advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin to the Embassy of the Netherlands in India, New Delhi under intimation to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W. E. III Section), New Delhi.

III (9) The term "Firm orders" referred to in Section II (2) means purchase order placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

III (10) The CIF/C&F value of the contract should be expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded with the Dutch suppliers and in the respective currency in case of contracts concluded with the suppliers in eligible source countries.

III (11) The contract must provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas suppliers.

III (12) The amount of Indian Agent's Commission included in the value of the contract should be specifically indicated. Any payment on this account should be made in Indian rupees to the Agent in India. No remittance of foreign exchange will be permitted for this purpose. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

III (13) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

III (14) The following provisions should be specifically incorporated in the contract :

(i) 'the contract is subject to the approval of Government of India (if the value of the contract is Dutch Guilders 50,000 or below) and subject to the approval of both the Government of India and the Government of Netherlands (if the value of the contract exceed Dutch Guilders 50,000);

(ii) This contract will be governed by the payment procedures laid down under the licensing conditions for the Dutch General Purpose Credit and will become effective after the Government of India's approval to this effect has been received.'

(iii) "The goods are of Dutch origin/manufacture" (in case of suppliers in Netherlands)

or

"The goods are of _____ origin/manufacture" (in case of suppliers in eligible source countries).

(iv) For the goods to be imported from Netherlands the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank, a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the supplier is established to the effect that the goods are of Netherlands origin. This certificate can be furnished along with the other shipping documents at the time of receiving payment. A specimen of the certificate is at Annex III.

In the case of supplier in eligible source countries the suppliers will have to produce to the N. I. O./proof of origin of goods in accordance with the Rules of Origin appended to the "Guidelines for Procurement of Goods and Services (Annex I).

III (15) For any customary performance guarantee, where required, the suppliers should be asked to furnish a bank guarantee/warranty.

Section IV—Approval of contract by Government of India/NIO.

IV (1) (a) Immediately after the contract is concluded, the importer should furnish 5 photostat or certified copies of the contract/supply orders accompanied by a photostat copy of the Import Licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE. III Section). In case of contracts concluded with suppliers in eligible source countries 8 copies of the same should be furnished. The importer is also required to furnish the information as per details in Annex II.

(b) In case of contracts concluded with Dutch Suppliers, the importer should furnish a bank guarantee from an approved scheduled bank, in the form prescribed (Annex IV) duly adjudicated by the Collector of Stamps. The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount of contract for which letter of Authority is sought plus interest and other charges. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and Banking as prevailing on the date of issue of import licence.

(2) When the supply contract is based on formal open International bidding or formal selective International bidding, the following information should also be furnished :

- (i) Name of the publication in which tender notice was advertised;
- (ii) Name of the parties who quoted against the tender enquiry;
- (iii) The reason for selecting a particular offer indicating whether it was the lowest technically suitable bid.

(3) If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation, the import licence and Bank Guarantee are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will forward copies of the contract to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague for approval.

(4) In respect of contracts valued at DG 50,000 or below approval of Dutch authorities is not required. The approval of the Government of India will be communicated to the Indian importers while forwarding the copies of their Contracts/supply orders to the Dutch Authorities. For Contracts of value exceeding DG 50,000, as soon as the approval of the Dutch authorities to the financing of the contract under Dutch Credit is received, the importer will be informed that their contract has become effective.

Section V—Payment to the Suppliers :

(A) Payment to the Suppliers in Netherlands.

V(1) A letter of Authority to the Netherlands Investment Bank for Developing Countries, The Hague (in the form at Annex V) authorising payment to the suppliers against shipping documents will be issued and forwarded along with the copies of contract etc. to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague.

V(2) : The validity of the letter of authority will be determined keeping in view the delivery schedule indicated in the contract. In no case will the letter of authority be made valid beyond the validity of the import licence.

V (3) : Since the payments to the suppliers under the credit are generally made by the Dutch Bank against the production of shipping documents the grace period facility will not be applicable to imports financed under this credit.

V(4) : In case the shipment/payments to the suppliers are not completed within the validity period of the Letter of Authority, the Importer should approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III section) for suitable extension of the Letter of Authority well before the expiry period of the Letter of Authority. Such a request should be accompanied with a photostat copy of the revaluated Import Licence, if the period of extension sought for is beyond the validity of the original Import Licence and a letter from the bank extending the validity of Bank Guarantee.

V(5) : If the request for extension in the period of validity of the Letter of Authority is not received within a period of six months from the validity date of the Letter of Authority, the un-utilised balance in the Letter of Authority will be deemed to have been surrendered and the Letter of Authority will stand lapsed automatically.

V(6) : The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the N.I.O. to the concerned importer's bank in India who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the importer has deposited :

- (i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Exports' Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17th January, 1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India;
- (ii) interest calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16th June, 1976 on the

amount required to be deposited vide item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N. V., The Hague, to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

V(7) : It shall be the responsibility of the Indian bank concerned, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

V(8) : The importers should make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC (PN)/68 dated the 30th August, 1968. The requisite 'S' Form will be sent by the concerned bank to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(9) : The moneys specified in Section V(6) should be deposited only with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi for credit to the Central Government Account under the head of account

"K—Deposits and advances—Deposit not bearing interest—843—Civil deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Purchases etc. under Dutch General Purpose Credit 1977-78".

V(10) : The advice of the rupee deposits referred to above, should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi by enclosing original receipted treasury challan in the proforma prescribed under Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974. No. 103-ITC(PN)/76 dt. 12-10-1976. The information in regard to Letter of Authority No. amount of foreign currency for which rupee deposit is made, date of payment to the Dutch supplier, amount of interest and period for which it is calculated should invariably be indicated in the challan form.

RE-IMBURSEMENT PROCEDURE

V(11) : In case of import licences where the value is below Rs. 1 lakh, the importer will have the option to adopt the Re-imbursement Procedure provided no payments are required to be withheld for performance etc. Under this system the importers will not be required to furnish the Bank Guarantee but their contract will have to indicate that the mode of payment will be by re-imbursement system. The importer will have to open a Letter of Credit on receipt of the approval of their contract by the Government of India. For this purpose a Letter of Authority (Annex VI) to the importer's Bank, as indicated by the importer, authorising opening a Letter of Credit on the suppliers' bank in Netherlands will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section). Payments against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence. Normally all shipments/payments to the suppliers should be completed within a period of 20 months from the date of issue of this said Letter of Authority. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of twenty months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section) at least a month before the expiry of this stipulated period for the extension of the time limit for completing the shipments/payments to the Suppliers. This request should be accompanied with a photostat copy of the revaluated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the un-utilized balances of their contract will be deemed as having been surrendered. The importer will furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Parliament Street, New Delhi-1, within 15 days of the shipment of goods a certificate from his Bank of payment made to the

supplier and also two copies of the invoice bearing a certificate from the Dutch supplier to the effect that "he received a sum of _____ Dutch Guilders amounting to 100 per cent of the invoice value or shipment of goods." He will also ensure that two copies of the certificate in regard to origin of Goods referred to in Section III(14) (iv) are furnished by the supplier to the Controller of Aid Accounts and Audit within the stipulated period of 15 days of the shipment of goods. Any omission on the part of the importers to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I&E. may be asked to suspend all import licences in the name of the importer. In case the importer persists in his default his case may be recommended to the C.C.I&E. for being blacklisted. The importer will in addition be liable to penalties/punishment under the law governing Import Control etc. In case the importer decides to adopt the reimbursement procedure, he should furnish 8 photostat/certified copies of the contract while seeking approval of his contract by Ministry of Finance.

(B) Payment to the suppliers in Eligible Source Countries.

V(12) : A Letter of Authority (in form at Annex VI) to the Importer's Bank, as indicated by the Importer in his application authorising opening of a Letter of Credit on the suppliers' bank in the eligible source country in favour of the supplier will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section). Copies of the contract along with a copy of the said Letter of Authority will be forwarded to the Dutch authorities also through the Embassy of India at the Hague.

V(13) : On receipt of the Letter of Authority mentioned in the preceding paragraphs, the Importer's Bank will open a Letter of Credit in favour of the supplier through his banker within a period of 30 days from the date of issue of the said Letter of Authority and against a valid import licence. An intimation to this effect shall be forwarded to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V(14) : After the payment to the supplier is made the supplier's bank shall forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by the latter.

V(15) : The supplier's bank will also obtain from supplier and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi a certificate or proof (in duplicate) in regard to the origin of the goods being in accordance with the Rules of origin appended to the Guidelines for Procurement of Goods and Services.

V(16) : The importer should forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate of remittance made by them to the supplier against the invoice/shipment of goods excluding bank charges, if any. This certificate should be obtained from the bank through which the Letter of Credit is opened. The importer should also ensure that one set of non-negotiable shipping documents, two copies of invoice with a certificate duly endorsed thereon in regard to receipt of payment by supplier and certificate of origin referred in Sections V(14) and V(15) are forwarded to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Controller of Aid Accounts & Audit within 15 days of the shipment of goods.

V(17) : Payment against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence.

V(18) : Normally all shipments/payments to the supplier should be completed within a period of 20 months from the date of issue of the Letter of Authority referred to above. In case the shipments/payments to the suppliers are not likely to be completed within the period of 20 months, the Importer

should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section) at least a month before expiry of this limit for completing the shipments/payments to the Suppliers. This request should be accompanied with a photostat copy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the unutilised balances of the contract will be deemed as having been surrendered.

V(19) : Any omission on the part of the importer to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences issued in the favour of the importer. In case the importer persists in his default, his case may be recommended to the C.C.I.&E. for being blacklisted. The importer will in addition be liable to penalties/punishments under the law governing Import Control etc.

V(20) : On receipt of the reimbursement documents, Controller of Aid Accounts and Audit, in the Ministry of Finance, will make a request to the Netherlands Investment Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier in the eligible source countries. The Netherlands Investment Bank will reimburse the equivalent amount in Netherlands guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands on the date of such reimbursement.

Section VI : Miscellaneous :

VI(1) : The importer should furnish a quarterly report, as in Annex VII, showing the utilisation status of the licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section).

(2) It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment could be effected to him must be clearly spelt out by the importer in Annex II. If necessary, a provision dealing with settlement of disputes may be included in the contract itself.

(3) The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to import licence and for meeting all obligations under Dutch General Purpose Credit.

(4) Any breach/violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEX I

Guidelines for Procurement of goods and services under Bilateral development loans by the Netherlands

A. General

1. These guidelines govern procurement of goods and services under bilateral loans which form part of the official Netherlands Development Aid Programme. These loans are untied in respect of developing countries. A list of eligible source countries is attached as Appendix A. The recipient country is included in this list. The Netherlands Government may agree, on an individual basis, to limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries, with transportation and insurance costs included.

2. The Netherlands Government must be satisfied that the proceeds from the loans are to be used with due care being given to economy, efficiency, fairness in international competition and non-discrimination among eligible source countries in accordance with procurement procedures set out in these guidelines.

3. Except in the cases mentioned in paragraphs 16 and 17, no practices shall be allowed, which could lead to, or result in a particular supplier or the suppliers of a particular country being favoured.

4. The rules of origin and control to be observed by the borrower in the procurement of goods and services, are attached to these guidelines as Appendix B.

5. Where the borrower does not effect direct procurement, he shall make such arrangements as are necessary to ensure that the purchaser complies with these guidelines.

6.(1) The borrower shall obtain goods and services through formal open international bidding except in the following cases :

(a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ;

(b) where the value of imports is less than Dfl. 1.25 million ; or

(c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the borrower on another more expedient procedure must be reached before suppliers are invited to submit their bids, such agreement to be reached on the basis of all relevant information to be supplied by the borrower through the Royal Netherlands Embassy.

6.(2) Where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only, the borrower shall have the option to confine bids to the Netherlands only or obtain bids from the Netherlands as well as the eligible source countries. In such cases article 30 of the Guidelines along with articles 31-33 or article 30 along with articles 34-38 are applicable.

7. These guidelines, together with the Rules of Origin and the list of eligible source countries, are subject to amendment by the Netherlands Government.

B. Procedures for Formal Open International Bidding

8. At the time invitations to bid are issued, the borrower (or the purchaser on the borrower's behalf) shall advertise the bidding in at least one of the following two publications :

Indian Trade Journal

Indian Export Service Bulletin

The importer shall send three copies of the tender notices as advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India.

9. In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited should, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is possible from a technical and administrative point of view to divide a project into contracts of a specialized nature and such division is likely to be advantageous to the borrower and/or to allow broader international competitive bidding the project should be divided. Single contracts for engineering, equipment and construction work (commonly known as "Turn-key contracts") may be desirable if they offer overall advantages to the borrower country within the technical and economic facilities available.

10. Formal prequalification may be desirable, in particular for civil works contracts. If prequalification is used, it should be based entirely upon ability to perform satisfactorily, taking into account (i) the firm's previous experience in similar types of work, (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial position and integrity. Advertisement of the prequalification procedure shall be carried out in accordance with the procedure described in paragraph 8. Condensed specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for prequalification. When prequalification is applied, all firms which fulfil the conditions for prequalification shall be permitted to bid.

11. Bidding documents shall be prepared in one of the languages customarily used in international transactions and shall unless prohibited by law specify that the text of the documents in that language is governing.

12. Specifications shall set forth as clearly and precisely as possible the work to be carried out, the goods and services to be supplied and the place of delivery of installation. Drawings shall be consistent with the text of the specifications; where they are not the text shall govern. The specifications shall state the principles of evaluations and comparison of bids, which will be taken into account when evaluations are made and bids are compared. The specifications shall be worded in such a way as to permit and encourage free and full international competition.

Any additional information, clarification or correction of errors and alterations of specifications and invitations to bid shall be communicated promptly to those who requested the original bidding documents.

13. If national standards are cited to which equipment or material must comply, the specifications shall state that goods meeting other internationally accepted standards, which demand an equal or better quality than the standards, mentioned, will also be accepted.

14. Specifications shall be based on performance and potential and should only prescribe registered brand names, catalogue numbers or products of a particular manufacturer if particular spare parts are required or if it has been decided that a certain amount of standardization is necessary to maintain certain essential quality factors. In the last case the specifications shall permit offers of alternative goods which have similar characteristics and whose performance and quality are of a level at least equal to those specified.

15. Invitations to bid shall list the eligible source countries and shall set out the rules of origin applicable.

16. Quotations shall be examined on the basis of strict equality of conditions among suppliers from eligible source countries (including the evaluation of quotations for material and equipment at prices free of customs tariffs and other duties and taxes of like effect). The borrower country, however, is authorised, in the evaluation and comparison of bids to supply goods and services, excluding transport costs, to extend a margin of preference to local goods and services and to products from other eligible source countries which are members of the same regional economic group, consistent with GATT, or which intend to establish such a group, over goods and services originating in other eligible source countries. This margin of preference shall not exceed 15 per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign bid or the existing level of customs duties of the bidder's country, whichever is the lowest.

17. In special cases, the borrower may, after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrowing country, extend a limited margin of preference to local and regional manufacturers, consistent with GATT, in addition to the margin of preference, mentioned in paragraph 16. In assessing the level of preference, due attention should be given to factors like the degree of national or regional ownership and management and the registration in the borrower country or the regional economic group of these manufacturing firms.

18. Bidding documents shall set out any preferences agreed upon and specify the manner in which they will be applied in the evaluation and comparison of bids.

19. Bidders shall be given inadequate time in which to submit their bids.

20. The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening shall be announced in the invitations to bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time shall be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted shall be read aloud and recorded.

21. No bidder shall be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but shall not ask any bidder to change the substance or price of his bid.

22. Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures on the side of either the borrower or the Netherlands Government before the announcement of the award of a contract to the successful bidder.

23. After the opening of the bids, the purchaser shall examine the bids in order to ascertain whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the requirements of the bidding documents, whether the required guarantees and sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it shall be rejected. A technical analysis together with a detailed assessment in monetary terms shall then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

24. Invitations to bid may state that the purchaser reserves the right to reject all bids when none are responsive to the intent of the specifications, when there is evidence of lack of competition, or when the low bids exceed the cost previously estimated by an amount sufficient to justify such action. If all bids are rejected, the borrower may, after consultation with the Netherlands Government, enter into negotiations with one or more of the lowest bidders to ascertain the causes for such events and the reasons for the difference between the low bid and the cost estimates. Negotiated contracts reflecting changes in the specifications, leading to economies in the estimated cost of the project, may be acceptable, provided the changes do not substantially alter the nature of the project. Where changes are substantial, rebidding may be appropriate. This shall at all times be approved by the Netherlands Government.

25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents and in any modifications thereto prior to the closing date for submission of bids. For the purpose of determining the lowest evaluated bid, commercial factors other than price, such as the time of completion of construction or other work, the efficiency and reliability of the equipment, the time of its delivery and the availability of service and spare parts, shall also be taken into consideration and shall, to the largest possible extent, be expressed in monetary terms. The currencies in which bid prices would have to be paid shall be valued, for bid comparison purposes only, on the basis of rates of exchange published by an official source and applicable to similar transactions at the closing date of the bidding.

26. The award of a contract shall be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid, taking into account the factors mentioned in the preceding paragraphs.

27. The Netherlands Government shall, upon request, be given adequate opportunity to present its comments and recommendations on all phases of procurement. After the award of contract, the Netherlands Government shall be provided with (copies of) all relevant documents and other information necessary for the evaluation of the use of the loan.

C. Procurement Procedures other than Formal Open International Bidding.

28. In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30, the procurement formulae of paragraphs 31—39 may be applied in accordance with paragraph 6.

29. Standardization,

Where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

30. Limited Number of Qualified Suppliers :

In cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.

Formal Selective International Bidding

31. Under formal selective international bidding the purchaser is authorized to invite bids from only a limited number of (pre) qualified suppliers known to be able to meet the special requirements of the procurement in question.

In such cases the borrower should ascertain that no potential qualified suppliers have been excluded. The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all necessary information as and when asked for by potential suppliers of eligible source countries to enable them to participate on an equitable basis.

32. The suppliers are to be selected exclusively on the basis of their qualifications and are, as far as possible, to be chosen from several eligible source countries including the Netherlands.

33. All provisions of formal international bidding, other than those of paragraph 8, are to be fully applied.

Informal International Competitive Procurement

34. If procurement is not through the formal competitive bidding procedures, it should be made in accordance with good commercial practice and without discrimination among eligible source countries.

35. The importer should give wide and timely publicity to the intended use of informal international competitive procurement. The Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all information necessary to permit suppliers of eligible source countries to participate on an equitable basis as and when such information is asked for.

36. The time allowed for the preparation of quotations and offers shall be governed by the nature of the contracts involved. Both lead time and delivery schedules shall be long enough to allow meaningful international competition.

37. The Netherlands Government may require the purchaser in particular cases to supply information on the purchases made, including full details concerning how quotations were obtained, the suppliers who are involved and the quotations received.

38. The guidelines for formal open international bidding should be applied to the fullest possible extent as appropriate.

Single Supplier

39. The purchaser is permitted to purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorised distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer;
- (iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source;
- (iv) the purchaser is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilization with a specific type of raw material which can only be obtained from one source;
- (v) the purchaser wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international

bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made;

- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

D. Guidelines for the Use of Consultants

40. Consultant firms employed should be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and bid documents prepared by them should be free of national, commercial or industrial bias, can be complied with on a competitive basis. In considering local consultant firms, due attention should be given to factors like the degree of national ownership, management and personnel and registration.

41. Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, in the process of selection, borrowers should consider a reasonable number of prospective firms, which can be expected to render competent and independent services from several eligible source countries. This list shall be bases on prequalification, taking into account.

- (i) the firm's previous experience in similar types of work;
- (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant; and
- (iii) its financial position and integrity.

It is desirable that, before invitations for proposals are sent out, the borrower submits the list of prospective firms to the Netherlands Government. The Netherlands Government reserves the right to reject the choice of a consultant, and may, furthermore, on the basis of her knowledge of the consultancy sector in the Netherlands, suggest that this list is extended.

E. Grievances

42. The borrower shall make provision for the hearing and investigation of complaints arising in connection with the invitations to bid, the submission of bids and the award of contracts.

43. In the case of purchases conducted under formal international bidding procedures complaints of any substance, regarding restrictive commodity specification or other restrictive terms of the invitation, made prior to the bid closing date, shall be resolved before the opening of bids. If necessary and only after consultation with the Netherlands Government, the bid closing date may be postponed for an appropriate period.

44. When a complaint has been made by one of the suppliers concerned, the documentation relating to the substance of the complaint and action taken thereon shall be available for examination by the Netherlands Government, as well as by the borrower.

Appendix—A

List of eligible source countries for united bilateral loans to developing countries.

A. Netherlands

B. Africa

North of Sahara

Algeria

Libyan Arab Rep.

Morocco

Tunisia

Egypt

South of Sahara

Botswana

Burundi	Colombia
Cameroon	Ecuador
Cape Verde Islands	Falkland Islands
Central African Rep.	Guyana
Chad	Guiana (Fr.)
Comoro Islands	Peraguay
Congo (People's Rep. of)	Peru
Zaire Rep.	Surinam
Dahomey	Uruguay
Ethiopia	Venezuela
Gabon	Asia
Gambia	Middle East
Ghana	Bahrein
Guinea	Iran
Guinea Bissau	Iraq
Ivory Coast	Israel
Kenya	Jordan
Lesotho	Kuwait
Liberia	Lebanon
Malagasy Republic	Oman
Malawi	Qatar
Mali	Saudi Arabia
Mauritania	Yemen (People's DR).
Mauritius	Syrian (Arab. Rep.)
Niger	Unit Arab Emirates
Negeria	Yemen (Arab. Rep.)
Reunion	South
Rwanda	Afghanistan
Senegal	Bangladesh
Scychedes	Bhutan
Sirerra Leone	Burma
Somalia	India
Terr. Afars and Issas	Maldives
St. Helena and dependencies	Nepal
Sudan	Pakistan
Swaziland	Sri Lanka
Tanzania	Far East
Togo	Brunei
Uganda	Khmer Rep.
Upper Volta	Hong Kong
Zambia	Indonesia
America	Korea (Rep. of)
North and Central	Korea (People's Dem. Rep. of)
Bahamas	Laos
Barbados	Macao
Bermuda	Malaysia
Costa Rica	Philippines
Cuba	Singapore
Dominican Republic	Thailand
El Salvador	Timor
Gaudeloupe	Vietnam (Rep. of)
Guatemala	Vietnam (Dem. Rep. of)
Haiti	Oceania
Honduras	Fiji
Honduras (Br.)	Gilbert & Ellice Islands
Jamaica	French Polynesia
Martinique	New Caledonia
Mexico	New Hebrides (Br. & Fr.)
Netherlands Antilles	Pacific Islands (US)
Nicaragua	Papua New Guinea
Panama	Solomon Islands
St. Pierre et Miquelon	Tonga
Trinidad et Tobago	Wallis and Futuna
West Indies (Br.)	Western Samoa
South	Europe
Argentina	Turkey
Bolivia	Portugal
Brazil	
Chile	

Appendix 'B'
Rules of Origin

1. The subject items of these rules of origin shall be goods and services produced in the eligible source countries.
2. In the case of goods, assessment of the Netherlands origin shall be subject to the legislation in this field which prevails in the European Community.
3. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 2 shall be furnished by means of a certificate of origin, issued by a Chamber of Commerce in the Netherlands.
4. In the case of goods, assessment of origin in developing countries shall be subject to the rules of origin which are established by the European Community in the framework of the General System of Preferences.
5. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 4 shall be furnished by means of a Certificate of Origin, Form A (as in use by the General System of Preferences), issued by an official authority in the developing country.
6. In the case of services (of paragraph 1 of the Guidelines), Origin shall be assessed, on an ad hoc basis, in mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

7. In cases where the Rules of Origin cause substantial problems of serious economic damage to the borrower country (e.g. an over-tight restriction of the number of potential suppliers), deviations from these rules may be permitted, but only after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

ANNEXURE II

- (a) Name and address of the Indian importer and/or Project authority where necessary.
- (b) Name and address of the supplier. In case of suppliers in Eligible Source Countries, the following information should also be furnished—
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by national of the eligible source countries.
- (c) (i) No. and date of Import Licence.
 - (ii) Value.
- (d) (i) Name and address of the Suppliers Bank in the Netherlands/Eligible Source Country.
 - (ii) The Importers Bank in India (Which will be the bank that has furnished the Bank Guarantee).
 - **(iii) The importers Bank in India which will be responsible to make rupee deposits in Government account before releasing shipping documents to the importer.
- (e) Value of the contract order in Dutch Guilders or the currency of the Eligible Source Country.
- (f) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or Formal Open International Bidding, or selective Formal International Bidding, in which case it should be indicated whether the contract has been entered into on the basis of the lowest technically suitable offer, with reason, if any.
- (g) Short description of goods to be imported.
- (h) Origin of Goods—percentage of imported components from non-eligible source countries, if any.
- (i) Expected date of completion of deliveries.
- (j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

*for Private Sector.

**for Public Sector.

68 GI/78—5

- (k) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc. which the Netherlands Investment Bank for Developing countries or the Suppliers Bank in Eligible Source Country should demand from the suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.
- (l) Indian Agents commission, if any, included in the contract (exact amount to be indicated), which will have to be deducted from the contract value while issuing a Letter of Authority. Such commission will be payable by the Importers direct to the Agents in rupees.
- (m) Value of which the Letter of Authority is requested.
- (n) Number, date and value of Bank Guarantee, indicating the period upto which it is valid.
- (o) Special instructions, if any.

ANNEXURE III
DUTCH CREDIT
CONTRACT CERTIFICATE
Particulars of contract

Indian Import Licence No.

1. Number and Date of the Contract

2. Description of goods or services to be supplied to the purchaser

(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate).

3. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) Df

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED.

4. Estimated % of the FOB value of the goods not originating in the Netherlands but purchased by the supplier direct from abroad, i.e. % of imported raw material or components used in manufacture.

(a) % FOB value

(b) Description of items and brief specification

5. IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED

6. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by

(a) Your firm (site engineers charges, etc.)

(b) Local supplier

7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 4 & 5 above

8. I hereby declare that I am employed in the Netherlands by the Supplier named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of Netherlands origin will be supplied by the supplier other than these specified in paragraphs 4 & 5 above.

Signed

Position hold

Name and address of supplier

Date

Certified

Netherlands Chamber of Commerce District.

ANNEXURE IV
GUARANTEE BOND

(To be furnished by Banks under the procedure for the import of goods under the Dutch General Purpose Credit)

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Dutch Guilders for the import of _____ by _____ (hereinafter called the Importer) against the import licence number _____ dated _____ issued under the terms and conditions of the Dutch General Purpose Credit and in pursuance of Import in favour of the Importer against the above mentioned agreement, we _____ (Bank) at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the Netherlands Investment bank for Developing Countries, The Hague nominated by the importer converted at the prevailing composite rate of exchange calculated as per Public Notices issued by the Government in the matter from time to time within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Head of Account as indicated by Government of India under the said Credit together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof (as prescribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-1976) reckoned from the date of payment to the Dutch supplier to the date of payment of rupee equivalent for Credit to the Government Account. The negotiable set of import document received from the Netherlands Investment bank for Developing Countries, The Hague will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We the _____ (Bank) also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sums not exceeding Rs. _____ or any part thereof for the time being due and payable by the Importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof (vide Public Notice ibid) reckoned from the date of payment to the Dutch Supplier to the date of actual deposit of the rupee equivalent into Government account. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us _____ (Bank), shall be final and binding on us _____ (Bank).

3. We _____ (Bank) further agree that in case of increase in the value of import or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place in proportion to this change.

4. We _____ (Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importer or the _____ (Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the _____ (Bank), shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the _____ (Bank) from its such liability.

6. We _____ (Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

7. We _____ (Bank), hereby undertake to make additional deposits in terms of Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 and such other Public Notices that may be issued time to time hereafter.

8. Our liability under this guarantee is restricted to Rs. _____ (plus interest and other charges, if any, not expected to exceed one per cent of the guarantee amount) and this guarantee shall remain in force till the _____ day* of _____ month, 19_____. Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto _____, all Government's rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the _____ day of _____

For _____ (Bank).

Accepted for and on behalf of
the President of India by

Shri _____

(Name & Designation)

Signature _____

*This date shall be arrived at the adding one month to the date by which all payments to the Suppliers are expected to be finalised.

Note:—The value of the Stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps act.

ANNEXURE V

No. F. 14()-WE.III/

Government of India (Bharat Sarkar)

Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)

Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

_____, The Hague, Netherlands.

To

Agreement for the loan of _____ million Netherlands Guilders—Request for direct payment.

Dear Sirs,

The Netherlands Investmentbank for Developing Coun-

LETTER OF AUTHORITY No.

With reference to our application of today's date as to the financing of the transaction between M/s. _____, India and M/s. _____, Holland, out of the loan made by your Bank to India, we hereby request and authorise you unconditionally and irrevocably to pay in accordance with the terms and conditions of the above mentioned contract to the supplier in Holland the amount of N. fl. _____ (_____ only). It is requested that the invoices, shipping and other documents presented by the Dutch supplier be despatched direct to the _____.

The suppliers will also be required to furnish to the Netherlands Investmentbank for Developing Countries a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Authority.

Kindly forward the debit advice to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,

Economic Aid (Accounts) Branch, Jeevan Deep, Parliament Street, New Delhi. This letter of Authority will remain valid upto _____

For the President of India,

Copy to _____
(Importer's Bank)

They should ensure that the rupees equivalent at the Composite rate of exchange to be calculated in the manner prescribed in Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 and such other Public Notices that may be issued from time to time together with the interest thereon at the rates prescribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976 from the date of payment to the suppliers to the date of deposit of the amount into Government Account is deposited before releasing the original documents to the Importer.

Annex VI

No. F. (14) -WE. III /

Government of India
(Bharat Saikar)

MINISTRY OF FINANCE

(Vitta Mantralya)

Department of Economic Affairs
(Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

Subject :—Contract entered under General Purpose Dutch Credit—Reimbursement.

Dear Sirs,

Messrs. _____

(Indian importer)

have entered into a contract with Messrs. _____

(Foreign supplier)

for the supply of _____

for the amount of _____

_____) C. I. F./C. & F. against
Licence No. _____ dated _____

issued under the Dutch General Purpose Credit for the value
of Rs. _____ (Rupees _____).

A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of _____
an amount of _____ is to be paid as Indian Agents' Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed initially out of the free foreign exchange resources, to be reimbursed later out of the Dutch General Purpose Credit, therefore, amounts to _____.

3. You are authorised to open a letter of credit in favour of Messrs. _____

_____) though their
bankers, viz. Messrs. _____

within a period of thirty days from date of this letter and against a valid Import Licence, under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

4. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of the expiry of the Letter of Credit is not later than forty-five (45) days after the final date for shipment as stated in the relative import licence.

5. The letter of credit will also provide that Messrs. _____

(foreign banker)

will forward directly to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the Dutch Supplier that the payment has been received by the latter.

They will also obtain from the suppliers and furnish to the Controller of Aid Accounts & Audit a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the exporter is established regarding the Netherlands origin of the goods covered under the Letter of Credit/* issued by the appropriate competent authority in regard to the origin of the goods covered under the Letter of Credit.

6. You are also required to forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi a certificate of remittance made by you to M/s. _____

against the invoice/shipment of goods, excluding Bank charges, if any.

7. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

*To be deleted if not applicable.

Copy with a copy of contract forwarded to :—

Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Bombay-1.

2. Copy also forwarded for information to :—

(i) _____

(Indian importer)

It may be ensured that M/s. _____

(foreign banker)

forward one set of shipping and other documents (non-negotiable) along with payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him, and two copies of certificate in regard to origin of goods to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(ii) M/s. _____

(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) along with payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him and two copies of certificate in regard to origin of goods may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(iii) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEX VII

STATEMENT SHOWING QUARTERLY REPORT ON
UTILISATION UNDER DUTCH (G.P.) CREDIT

1. Name of Importer.
2. No and date of Import Licence
3. Value of Import Licence.
4. Value of orders placed.
5. Letter of Authority No. and date
6. Amount of Letter of Authority
7. Date of Validity of Letter of Authority.
8. Amount utilised during the Quarter.
9. Total amount utilised.
10. Total Amount deposited into Government Account
11. Payment to be made during the subsequent quarters
12. Surrenders, if any.

D G
D.G
Rs

APPENDIX II

Conditions for Licensing Public Sector Imports under the Dutch General Purpose Credit

Section I—General

I(1) The Dutch General Purpose Credit for 1977-78 extended by the Nederlandse Investerings bank Voor Ontwikkelingslanden N.V. is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and commodities and services incidental thereto which are to be financed under the Credit can be imported from Netherlands and all countries enumerated in the list at Appendix A of the "Guidelines for Procurement of Goods and Services under Bilateral Development Loans by the Netherlands" (Annex 1) which will be the "eligible source countries" under the credit.

I(2) Components to the extent of 10 per cent in respect of chemicals and 20 per cent in respect of other imports from non-eligible source countries can, however, be considered for being financed under the Credit. Specific requests in this regard, if any, should be made to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE III Section) before finalising the contracts.

I(3) Limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries in excess of the limit indicated in Section I(2) may also be considered for financing under the credit. For this, specific approval of the Government of Netherlands will be necessary.

Section II—Issue of Import Licence

II(1) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned, within the validity period of the licence, who shall consult the Department of Economic Affairs, (WE III Section) in the matter.

II(2) Firm order on CIF/C&F basis must be placed on the overseas suppliers in the Netherlands or the countries mentioned in the Annex I and sent to the Department of Economic Affairs (WE III Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. If firm orders cannot be finalised within the time limit of 4 months, the Licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period, furnishing justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on

the merits of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs, (WE III Section), Ministry of Finance

The terminal date of disbursements in both the credit agreements viz Dfl. 120 million and Dfl 54 million would be 31-12-1980.

II(3) The licence will bear the superscription 'Dutch General Purpose Credit' and indicate the Public Notice number under which these licensing conditions are issued. The licence code for the first and second suffix will be "S"/"NN". This licence code will be mentioned in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Reserve Bank at the time of rupee deposit.

II(4) As soon as the importer receives the import licence, he should send a report to that effect to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE III Section) along with the following information :—

- (i) No. and Date of Import Licence ;
- (ii) Value.
- (iii) Exchange rate, if any, indicated on Import Licence.
- (iv) Date by which copies of contract are expected to be furnished to Department of Economic Affairs

Section III—Finalisation of Contract

III(1). The minimum value of contract eligible for financing under the credit is Dfl 25,000.

III(2). Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract will be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

III(3). The contract for the import of goods and services from the Netherlands and eligible source countries should be finalised keeping in view the Guidelines for Procurement of Goods and Services, as detailed in (Annexure I).

III(4) Goods and services should be procured through Formal Open International Bidding except in the following cases :

- (a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ; or
- (b) where the value of imports is less than Dfl. 125 million, or
- (c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the Government of India on another mere expedient procedure must be reached before the contract for the supplies could be finalised.

III(5) It would also not be necessary to resort to Formal Open International Bidding in the following types of cases :—

- (a) where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardisation of this equipment
- (b) in cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers
- (c) where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only.

In such cases the procurement formula of paragraphs 31 to 39 of the Guidelines for procurement of goods and services (Annex. I) may be followed.

III(6) The purchaser may purchase directly from a single supplier in one of the following cases :

- (i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer ;
- (ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer ;
- (iii) in order to assure interchange ability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source;
- (iv) the importer is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilisation with a specific type of raw material which can only be obtained from one source ;
- (v) the importer wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement, takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made;
- (vi) the value of a transaction is less than Dfl. 1.25 million.

III(7). Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, before invitations for proposals are sent out by the Indian firms to the consultant firms, a list of such prospective firms should be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E.III Section). The list in turn will be submitted to the Government of Netherlands who may approve the same or reject the choice of a consultant and may on the basis of their knowledge of the consultancy sector in Netherlands suggest that this list is extended.

III(8). Where the goods are proposed to be procured on the basis of Formal Open International Bidding, the importer should forward three copies of the tender notices as soon as these are advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India, New Delhi, under intimation to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E.III Section), New Delhi.

III(9). The term "Firm Orders" referred to in Section II(2) means purchase order placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

III(10). The CIF/C&F value of the contract should be expressed in Dutch Guilders in case of contracts concluded with the Dutch suppliers and in the respective currency in case of contracts concluded with the suppliers in eligible source countries.

III(11). The contract must provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian Importer from the overseas suppliers.

III(12). The amount of Indian Agent's Commission included in the value of the contract should be specifically

indicated. Any payment on this account, should be made in Indian rupees to the Agent in India. No remittance of foreign exchange will be permitted for the purpose. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

III(13). The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

III(14). The following provisions should be specifically incorporated in the contract :

- (i) "the contract is subject to the approval of Government of India (if the value of the contract is Dutch Guilders 50,000 or below) and subject to the approval of both the Government of India and the Government of Netherlands (if the value of the contract exceeds Dutch Guilders 50,000).
- (ii) This contract will be governed by the payment procedures laid down under the licensing condition for the Dutch General Purpose Credit and will become effective after the Government of India's contract exceeds Dutch Guilders 50,000).
- (iii) "The goods are of Dutch origin/manufacture" (in case of supplies in Netherlands)

or

- "The goods are of.....origin/manufacture" (in case of suppliers in eligible source countries)

- (iv) "For the goods to be imported from Netherlands, the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank, a certificate in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce of the district in which the supplier is established to the effect that the goods are of Netherlands origin. This certificate can be furnished along with the other shipping documents at the time of receiving, payment. A specimen of the certificate is at Annex. III.

In the case of supplier in eligible source countries the suppliers will have to produce to the Netherlands Investment Bank proof of origin of goods in accordance with the Rules of Origin appended to the "Guidelines for Procurement of Goods and Services (Annex. I)."

III(15). For any customary performance guarantee, where required, the suppliers should be asked to furnish a bank guarantee/warranty.

Section IV—Approval of contract by Government of India / Netherlands Investment Bank.

IV(1). Immediately after the contract is concluded, the importer should furnish 5 photostate or certified copy of the contract/supply orders accompanied by a photostate copy of the Import Licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section). In case of contracts concluded with supplies in eligible source countries, 8 copies of the same should be furnished. The importer is also required to furnish the information as per details in Annex. II.

IV(2) When the Supply contract is based on formal open international bidding or formal selective International bidding, the following information should also be furnished :—

- (i) Name of the publication in which tender notice was advertised ;
- (ii) Name of the parties who quoted against the tender enquiry ;
- (iii) The reason for selecting a particular offer indicating whether it was the lowest technically suitable bid.

IV(3). If the contract documents, the request for issue of letter of authorisation and the import licence are found to be in order, the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will forward copies of the contract to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague for approval.

IV (4) (a). In respect of contracts valued at DG 50,000 or below approval of Dutch authorities is not required. The approval of the Government of India will be communicated to the Indian importers while forwarding the copies of their contracts/supply orders to the Dutch Authorities.

(b) For contracts of value exceeding DG. 50,000, as soon as the approval of the Dutch authorities to the financing of the contract under Dutch Credit is received, the importer will be informed that their contract has become effective.

Section V—Payment to the Suppliers :

(A) Payment to the Suppliers in Netherlands

V(1). A letter of Authority to the Netherlands Investment Bank for Developing Countries, The Hague (in the form at Annex. IV) authorising payment to the suppliers against shipping documents will be issued and forwarded along with the copies of contract etc., to the Dutch authorities through the Embassy of India at The Hague.

V(2). The validity of the Letter of Authority will be determined keeping in view the delivery schedule indicated in the contract. In no case will the Letter of Authority be made valid beyond the validity of the import licence.

V(3). Since the payments to the suppliers under the credit are generally made by the Dutch Bank against the production of shipping documents, the grace period facility will not be applicable to imports financed under this credit.

V(4). In case the shipment/payments to the suppliers are not completed within the validity period of the Letter of Authority, the Importer should approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.F. III Section) for suitable extension of the Letter of Authority well before the expiry period of the Letter of Authority. Such a request should be accompanied with a photostat copy of the re-validated Import Licence, if the period of extension sought for is beyond the validity of the original Import Licence.

V(5). If the request for extension in the period of validity of the Letter of Authority is not received within a period of six months from the validity date of the Letter of Authority the un-utilised balance in the Letter of Authority will be deemed to have been surrendered and the Letter of Authority will stand lapsed automatically.

V(6). The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Netherlands Investment bank to the concerned importer's bank in India, which would be a branch of any of the nationalised banks who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the importer has deposited :

- (i) the rupee equivalent of the payments to the suppliers in Dutch Guilders at the prevailing composite rate of exchange to be calculated in the manner as prescribed in Chief Controller of Imports & Export's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 and as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the C.C.I&E. or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India,
- (ii) interest calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and at 15 per cent for the period in excess of 30 days in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976 on the amount required to be deposited vide item (i) above, reckoned from the date of actual payment to the supplier by the Netherlands Investment Bank for Developing Countries N. V. The Hague to the date of actual deposit of the rupee equivalent by the importer in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or Reserve Bank of India, New Delhi.

V(7). It shall be responsibility of the Indian Bank concerned, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

V(8). Public Sector importers (including Departments of the Central Government) should make the requisite rupee deposit only through Authorised Dealers in foreign exchange and also get the Exchange Control Copy of the Licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC (PN)/68 dated the 30th August, 1968. The requisite 'S' form will be sent by the concerned bank to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(9). The moneys specified in Section V(6) should be deposited only with the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or the Reserve Bank of India, New Delhi to the credit of the Central Government Account under the head of account.—

K—Deposits and advances—Deposit not bearing interest—843—Civil deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Purchases etc. under Dutch General Purpose Credit 1974-75.

V(10). The advice of rupee deposits referred to above, should be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi by enclosing original receipted treasury challan in the proforma prescribed under Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The information in regard to letter of Authority No., amount of foreign currency for which rupee deposit is made, date of payment to the Dutch supplier, amount of interest and period for which it is calculated should invariably be indicated in the challan form.

B. PAYMENT TO THE SUPPLIERS IN ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

V(11). A Letter of Authority (in form at Annex. V) to the Importer's Bank, as indicated by the Importer in his application authorising opening of a Letter of Credit on the suppliers' bank in the eligible source country in favour of the supplier will be issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.F. III Section). Copies of the contract along with a copy of the said Letter of Authority will be forwarded to the Dutch authorities also through the Embassy of India at The Hague.

V(12). On receipt of the Letter of Authority mentioned in the preceding paragraph, the Importer's Bank will open a letter of Credit in favour of the supplier through his banker within a period of 30 days from the date of issue of the said Letter of Authority and against a valid import licence. An intimation to this effect shall be forwarded to the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V(13). After the payment to the supplier is made the supplier's bank shall forward to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping documents and two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by the latter.

V(14). The supplier's bank will also obtain from supplier and furnish to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate or proof (in duplicate) in regard to the origin of the goods being in accordance with the Rules of origin appended to the "Guideline for Procurement of Goods and Services."

V(15). The importer should forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, a certificate of remittance made by them to the supplier against the invoice/shipment of goods excluding bank charges, if any. This certificate should be obtained from the bank through which the Letter of Credit is opened. The importer should also ensure that one set of non-negotiable shipping documents and two copies of invoice with a certificate duly endorsed thereon in regard to receipt of payment by supplier and certificate of origin, referred to in Section V(13) and V(14) are forwarded to Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Controller of Aid Accounts & Audit within 15 days of the shipment of goods.

V(16). Payment against the Letter of Credit will be made by the importer on the strength of the Exchange Control Copy of the Import Licence

V(17). Normally all shipments/payments to the Supplier should be completed within a period of 20 months from the date of issue of the Letter of Authority referred to above. In case the shipments/payments to the supplier are not likely to be completed within the period of 20 months, the Importer should invariably approach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section) at least a month before the expiry of this limit for completing the shipments/payments to the suppliers. This request should be accompanied with a photocopy of the revalidated Import Licence covering the period of extension sought for. If such a request is not received before the stipulated period, the unutilised balances of the contract will be deemed as having been surrendered.

V(18). Any omission on the part of the importer to send the reimbursement documents promptly to the Department of Economic Affairs will be viewed seriously and the C.C.I.&E. may be asked to suspend all import licences issued in the favour of the importer. In case the importer persists in his default his case may be recommended to the C.C.I. & E. for being blacklisted. The importer will, in addition, be liable to penalties/punishments under the law governing Import Control etc.

V(19). On receipt of the reimbursement documents, Controller of Aid Accounts and Audit in the Ministry of Finance, will make a request to the Netherlands Investment Bank for reimbursement of the amount paid to the supplier in the eligible source countries. The Netherlands Investment Bank will reimburse the equivalent amount in Netherlands guilders at the rate of exchange prevailing in the Netherlands on the date of such reimbursement.

Section VI : Miscellaneous :

VI(1). The importer should furnish a quarterly report, as in Annex. VI, showing utilisation status of the licence to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section).

VI(2). It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the supplier. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment could be effected to him must be clearly spelt out by the importer in Annex. II. If necessary, a provision dealing with settlement of disputes may be included in the contract itself.

VI(3). The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to import licence and for meeting all obligations under Dutch General Purpose Credit.

VI(4). Any breach of violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEX I

Guidelines for Procurement of goods and services under bilateral development loans by the Netherlands

A. General

1. These guidelines govern procurement of goods and services under bilateral loans which form part of the official Netherlands Development Aid Programme. These loans are untied in respect of developing countries. A list of eligible source countries is attached as Appendix A. The recipient country is included in this list. The Netherlands Government may agree, on an individual basis, to limited supplies of goods and services from non-eligible source countries to supplement the supplies from eligible source countries, with transportation and insurance costs included.

2. The Netherlands Government must be satisfied that the proceeds from the loans are to be used with due care being given to economy, efficiency, fairness in international competition and non-discrimination among eligible source countries, in accordance with the procurement procedures set out in these guidelines.

3. Except in the cases mentioned in paragraph 16 and 17, no practices shall be allowed, which could lead to, or result in a particular supplier or the suppliers of a particular country being favoured

4. The rules of origin and control to be observed by the borrower in the procurement of goods and services, are attached to these guidelines as Appendix B.

5. Where the borrower does not effect direct procurement, he shall make such arrangements as are necessary to ensure that the purchaser complies with these guidelines.

6. (1) The borrower shall obtain goods and services through formal open international bidding except in the following cases :

(a) where the Netherlands is the traditional or the only source for imports ;

(b) where the value of imports is less than DFL 1.25 million; or

(c) where such a procedure is inapplicable or inappropriate. In this case, agreement between the Netherlands Government and the borrower on another more expedient procedure must be reached before suppliers are invited to submit their bids, such agreement to be reached on the basis of all relevant information to be supplied by the borrower through the Royal Netherlands Embassy.

6. (2) Where in the light of the existing relationship subsisting between the Indian importers and the foreign suppliers and the scope of supplies available and identified in the Netherlands and/or the developing countries, the borrower considers that imports should be effected from the Netherlands only, the borrower shall have the option to confine bids to the Netherlands only or obtain bids from the Netherlands as well as the eligible source countries. In such cases article 30 of the Guidelines along with articles 31-33 or article 30 along with articles 34-38 are applicable.

7. These guidelines, together with the Rules of Origin and the list of eligible source countries, are subject to amendment by the Netherlands Government.

B. Procedures for Formal Open International Bidding

8. At the time invitations to bid are issued, the borrower (or the purchaser on the borrower's behalf) shall advertise the bidding in at least one of the following two publications :

Indian Trade Journal.

Indian Export Service Bulletin.

The importer shall send three copies of the tender notices as advertised in the Indian Trade Journal or the Indian Export Service Bulletin, to the Embassy of the Netherlands in India.

9. In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited should, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is possible from a technical and administrative point of view to divide a project into contracts of a specialized nature and such division is likely to be advantageous to the borrower and/or to allow broader international competitive bidding the project should be divided. Single contracts for engineering, equipment and construction work (commonly known as "Turn-key contracts") may be desirable if they offer overall advantages to the borrower country within the technical and economic facilities available.

10. Formal prequalification may be desirable, in particular for civil works contracts. If prequalification is used, it shall be based entirely upon ability to perform satisfactorily, taking into account (i) the firm's previous experience in similar types of work, (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial position and integrity. Advertisement of the prequalification procedure shall be carried out in accordance with the procedure described in paragraph 8. Condensed specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for prequalification. When prequalification is applied, all firms which fulfil the conditions for prequalification shall be permitted to bid.

11. Bidding documents shall be prepared in one of the languages customarily used in international transactions and shall unless prohibited by law specify that the text of the documents in that language is governing.

12. Specifications shall set forth as clearly and precisely as possible the work to be carried out, the goods and services to be supplied and the place of delivery of installation. Drawings shall be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications shall state the principles of evaluations and comparison of bids, which will be taken into account when evaluations are made and bids are compared. The specifications shall be worded in such a way as to permit and encourage free and full international competition.

Any additional information, clarification or correction of errors and alterations of specifications and invitations to bid shall be communicated promptly to those who requested the original bidding documents.

13. If national standards are cited to which equipment or material must comply, the specifications shall state that goods meeting other internationally accepted standards, which demand are equal or better quality than the standards mentioned, will also be accepted.

14. Specifications shall be based on performance and potential and should only prescribe registered brand names, catalogue numbers or products of a particular manufacturer if particular spare parts are required or if it has been decided that a certain amount of standardization is necessary to maintain certain essential quality factors. In the last case the specifications shall permit offers of alternative goods which have similar characteristics and whose performance and quality are of a level at least equal to those specified.

15. Invitations to bid shall list the eligible source countries and shall set out the rules of origin applicable.

16. Quotations shall be examined on the basis of strict equality of conditions among suppliers from eligible source countries (including the evaluation of quotations for material and equipment at prices free of customs tariffs and other duties and taxes of like effect). The borrower country, however, is authorised, in the evaluation and comparison of bids to supply goods and services, excluding transport costs, to extend a margin of preference to local goods and services and to products from other eligible source countries which are members of the same regional economic group, consistent with GATT, or which intend to establish such a group, over goods and services originating in other eligible source countries. This margin of preference shall not exceed 15 per cent on the CIF price of the lowest evaluated foreign bid or the existing level of customs duties of the bidder's country, whichever is the lowest.

17. In special cases, the borrower may, after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrowing country, extend a limited margin of preference to local and regional manufacturers, consistent with GATT, in addition to the margin of preference, mentioned in paragraph 16. In assessing the level of preference, due attention should be given to factors like the degree of national or regional ownership and management and the registration in the borrower country or the regional economic group of these manufacturing firms.

18. Bidding documents shall set out any preferences agreed upon and specify the manner in which they will be applied in the evaluation and comparison of bids.

19. Bidder shall be given adequate time in which to submit their bids.

20. The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening shall be announced in the invitations to bid and all bids shall be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time shall be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted shall be read aloud and recorded.

21. No bidder shall be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but shall not ask any bidder to change the substance or price of his bid.

22. Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards shall be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures on the side of either the borrower or the Netherlands Government before the announcement of the award of a contract to the successful bidder.

23. After the opening of the bids, the purchaser shall examine the bids in order to ascertain whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the requirements of the bidding documents, whether the required guarantees and sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it shall be rejected. A technical analysis together with a detailed assessment in monetary terms shall then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

24. Invitations to bid may state that the purchaser reserves the right to reject all bids when none are responsive to the intent of the specifications, when there is evidence of lack of competition, or when the low bids exceed the cost previously estimated by an amount sufficient to justify such action. If all bids are rejected, the borrower may, after consultation with the Netherlands Government, enter into negotiation with one or more of the lowest bidders to ascertain the causes for such events and the reasons for the difference between the low bid and the cost estimates. Negotiated contracts reflecting changes in the specifications, leading to economies in the estimated cost of the project, may be acceptable, provided the changes do not substantially alter the nature of the project. Where changes are substantial, re-bidding may be appropriate. This shall at all times be approved by the Netherlands Government.

25. Evaluations of bids shall be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents and in any modifications thereto prior to the closing date for submission of bids. For the purpose of determining the lowest evaluated bid, commercial factors other than price, such as the time of completion of construction or other work, the efficiency and reliability of the equipment, the time of its delivery and the availability of service and spare parts, shall also be taken into consideration and shall, to the largest possible extent, be expressed in monetary terms. The currencies in which bid prices would have to be paid shall be valued, for bid comparison purposes only, on the basis of rates of exchange published by an official source and applicable to similar transactions at the closing date of the bidding.

26. The award of a contract shall be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid, taking into account the factors mentioned in the preceding paragraphs.

27. The Netherlands Government shall, upon request, be given adequate opportunity to present its comments and recommendations on all phases of procurement. After the award of contract, the Netherlands Government shall be provided with (copies of) all relevant documents and other information necessary for the evaluation of the use of the loan.

C. Procurement Procedures other than Formal Open International Bidding.

28. In the cases mentioned in paragraphs 29 and 30, the procurement formulae of paragraphs 31—39 may be applied in accordance with paragraph 6.

29. Standardization where the purchaser has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

30. Limited Number of Qualified Suppliers : In cases where, because of the nature of the procurement in question, the number of qualified suppliers is limited and the market knowledge of the purchaser is such that he can be expected to know the qualified suppliers.

Formal Selective International Bidding

31 Under formal selective international bidding the purchaser is authorized to invite bids from only a limited number of (pre) qualified suppliers known to be able to meet the special requirements of the procurement in question

In such cases the borrower should ascertain that no potential qualified suppliers have been excluded. The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all necessary information as and when asked for by potential suppliers of eligible source countries to enable them to participate on an equitable basis

32 The suppliers are to be selected exclusively on the basis of their qualifications and are, as far as possible, to be chosen from several eligible source countries including the Netherlands

33 All provisions of formal international bidding, other than those of paragraph 8, are to be fully applied.

Informal International Competitive Procurement

34 If procurement is not through the formal competitive bidding procedures, it should be made in accordance with good commercial practice and without discrimination among eligible source countries

35 The importer should give wide and timely publicity to the intended use of informal international competitive procurement. The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India shall provide all information necessary to permit suppliers of eligible source countries to participate on an equitable basis as and when such information is asked for

36 The time allowed for the preparation of quotations and offers shall be governed by the nature of the contracts involved. Both lead time and delivery schedules shall be long enough to allow meaningful international competition

37 The Netherlands Government may require the purchaser in particular cases to supply information on the purchases made, including full details concerning how quotations were obtained, the suppliers who are involved and the quotations received

38 The guidelines for formal open international bidding should be applied to the fullest possible extent as appropriate

Single Supplier

39 The purchaser is permitted to purchase directly from a single supplier in one of the following cases

(i) procurement by a commercial importer involves a registered brand name commodity which is for resale by the importer, for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the sole distributor or manufacturer,

(ii) procurement by a commercial importer involves a commodity which is procured for manufacture, processing or assembly and resale of the end-product for which the importer is a regularly authorized distributor or dealer of the supplier and for which the supplier is the manufacturer,

(iii) in order to assure interchangeability of parts or because of special design or technical requirements the procurement can only be made from one source,

(iv) the purchaser is a manufacturer whose equipment and raw material formulae are designed for best utilization with a specific type of raw material which can only be obtained from one source,

(v) the purchaser wishes to extend or repeat a procurement originally made under formal international bidding provided that the complementary procurement is small in relation to the original procurement,

takes place on a few occasions only and while the construction work related to the original procurement is still under way or shortly after the original procurement is made;

(vi) the value of a transaction is less than Dfl. 125 million

D Guidelines for the Use Consultants

40 Consultant firms employed should be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and bid documents prepared by them should be free of national, commercial or industrial bias, and can be complied with on a competitive basis. In considering local consultant firms, due attention should be given to factors like the degree of national ownership, management and personnel and registration

41 Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consultant firms. However, in the process of selection, borrowers should consider a reasonable number of prospective firms, which can be expected to render competent and independent services from several eligible source countries. This list shall be based on prequalification, taking into account

- (i) the firm's previous experience in similar types of work,
- (ii) its potential with regard to personnel, equipment and plant, and
- (iii) its financial position and integrity

It is desirable that before invitations for proposals are sent out, the borrower submits the list of prospective firms to the Netherlands Government. The Netherlands Government reserves the right to reject the choice of a consultant, and may, furthermore on the basis of her knowledge of the consultancy sector in the Netherlands, suggest that this list is extended

F Grievances

42 The borrower shall make provision for the hearing and investigation of complaints arising in connection with the invitations to bid, the submission of bids and the award of contracts

43 In the case of purchases conducted under formal international bidding procedures complaints of any substance, regarding restrictive commodity specification or other restrictive terms of the invitation, made prior to the bid closing date, shall be resolved before the opening of bids. If necessary and only after consultation with the Netherlands Government, the bid closing date may be postponed for an appropriate period

44 When a complaint has been made by one of the suppliers concerned, the documentation relating to the substance of the complaint and action taken thereon shall be available for examination by the Netherlands Government, as well as by the borrower.

APPENDIX A

List of eligible source countries for untied bilateral loans to developing countries

A Netherlands

B Africa

North of Sahara

Algeria

Libyan Arab Rep.

Morocco

Tunisia

Egypt

South of Sahara

Botswana

Burundi	Brazil
Cameroon	Chile
Cape Verde Islands	Columbia
Central African Rep.	Ecuador
Chad	Falkland Islands
Comoro Islands	Guyana
Congo (People's Rep. of)	Guiana (Fr.)
Zaire Rep.	Paraguay
Dahomey	Peru
Ethiopia	Surinam
Gabon	Uruguay
Gambia	Venezuela
Ghana	Asia
Guinea	Middle East
Guinea Bissau	Bahrein
Ivory Coast	Iran
Kenya	Iraq
Lesotho	Israel
Liberia	Jordan
Malagasy Republic	Kuwait
Malawi	Lebanon
Mali	Oman
Mauritania	Qatar
Manuritius	Saudi Arabia
Niger	Yemen (People's DR)
Negerla	Syrian (Arab. Rep.)
Reunion	Unit. Arab Emirates
Rwanda	Yemen (Arab. Rep.)
Senegal	South
Seychelles	Afghanistan
Sierra Leone	Bangladesh
Somalia	Bhutan
Terr. Afars and Issas	Burma
St. Helena and dependencies	India
Sudan	Maldives
Swaziland	Nepal
Tanzania	Pakistan
Togo	Sri Lanka
Uganda	Far East
Upper Volta	Brunei
Zambia	Khmer Rep.
America	Hong Kong
North and Central	Indonesia
Bahamas	Korea (Rep. of)
Barbados	Korea (People's Dem. Rep. of)
Bermuda	Laos
Costa Rica	Macao
Cuba	Malaysia
Dominican Republic	Philippines
E1 Salvador	Singapore
Guadeloupe	Thailand
Guatemala	Timor
Haiti	Vietnam (Rep. of)
Honduras	Vietnam (Dem. Rep. of)
Honduras (Br.)	Oceania
Jamaica	Fiji
Martinique	Gilbert & Ellice Islands
Mexico	French Polynesia
Netherlands Antilles	New Caledonia
Nicaragua	New Hebrides (Br. & Fr.)
Panama	Pacific Islands (US)
St. Pierre et Miquelon	Papua New Guinea
Trinidad at Tobago	Solomon Islands
West Indies (Br.)	Tonga
South	Wallis and Futuna
Argentina	Western Samoa
Bolivia	Europe
	Turkey
	Portugal

APPENDIX 'B'

Rules of Origin

1. The subject items of these rules of origin shall be goods and services produced in the eligible source countries.

2. In the case of goods, assessment of the Netherlands origin shall be subject to the legislation in this field which prevails in the European Community.

3. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 2 shall be furnished by means of a certificate of origin, issued by a Chamber of Commerce in the Netherlands.

4. In the case of goods, assessment of origin in developing countries shall be subject to the rules of origin which are established by the European Community in the framework of the General System of Preferences.

5. Proof of origin of the goods mentioned in paragraph 4 shall be furnished by means of a Certificate of Origin, Form A (as in use by the General System of Preferences), issued by an official authority in the developing country.

6. In the case of services (cf. paragraph 1 of the Guidelines), origin shall be assessed, on an ad hoc basis, in mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

7. In cases where the Rules of Origin cause substantial problems or serious economic damage to the borrower country (e.g. an over-tight restriction of the number of potential suppliers), deviations from these rules may be permitted, but only after mutual consultation between the Netherlands Government and the borrower country.

ANNEXURE II

- (a) Name and address of the Indian importer and/or Project authority where necessary.
- (b) Name and address of the supplier. In case of suppliers in Eligible Source Countries, the following information should also be furnished—
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by national of the eligible source countries.
- (c) (i) No. and date of Import Licence.
 - (ii) Value.
- (d) (i) Name and address of the Supplier's Bank in the Netherlands/Eligible Source Country.
 - *(ii) The Importers' Bank in India (which will be the bank that has furnished the Bank Guarantee).
 - **(iii) The importers' Bank in India which will be responsible to make rupee deposits in Government account before releasing shipping documents to the importer.
- (e) Value of the contract order in Dutch Guilders or the currency of the Eligible Source Country.
- (f) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or Formal Open International Bidding or Selective Formal International Bidding, in which case it should be indicated whether the contract has been entered into on the basis of the lowest technically suitable offer, with reasons, if any.
- (g) Short description of goods to be imported.
- (h) Origin of Goods—percentage of imported components from non-eligible source countries, if any.

- (i) Expected date of completion of deliveries.
- (j) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (k) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, Certificate of Origin, etc., which the Netherlands Investment bank for Developing Countries or the Suppliers' Bank in Eligible Source Country should demand from the suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required.
- (l) Indian Agent's commission, if any, included in the contract (exact amount to be indicated), which will have to be deducted from the contract value while issuing a Letter of Authority. Such commission will be payable by the Importers direct to the Agents in rupees.
- (m) Value of which the Letter of Authority is requested.
- (n) Number, date and value of Bank Guarantee, indicating the period upto which it is valid.
- (o) Special instructions, if any.

*for Private Sector.

**for Public Sector.

ANNEXURE III
DUTCH CREDIT
CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of contract

Indian Import Licence No.

1. Number and Date of the Contract.....

2. Description of goods or services to be supplied to the purchaser

(If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate).

3. Total contract price payable by purchaser (State CIF, C&F or FOB) Dfl.....

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION MUST BE COMPLETED

- 4. Estimated per cent of the FOB value of the goods not originating in the Netherlands but purchased by the supplier direct from abroad, i.e. per cent of imported raw material or components used in manufacture.
 - (a) per cent FOB value.....
 - (b) Description of items and brief specification.....
- 5. If services are to be supplied the following section should also be completed.
- 6. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by
 - (a) Your firm (site engineers charges, etc.).....
 - (b) Local supplier
- 7. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 4 and 5 above.....
- 8. I hereby declare that I am employed in the Netherlands by the Supplier named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of Netherlands origin will be supplied by the supplier other than those specified in paragraphs 4 and 5 above.

Signed.....

Position held.....

Name and address of
Supplied.....

Date.....

Certified
Netherlands Chamber of Commerce..... District.

ANNEXURE IV

No. F. 14()-WE.III/

Government of India

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Netherlands Investment bank for developing Countries,
The Hague, Netherlands.Agreement for the loan of _____ million Netherlands
Guilder—Request for direct payment.

Dear Sirs,

LETTER OF AUTHORITY No.

With reference to our application of today's date as to
the financing of the transaction between M/s. _____, India andM/s. _____, Holland out
of the loan made by your Bank to India, we hereby request
and authorise you unconditionally and irrevocably to pay in
accordance with the terms and conditions of the above
mentioned contract to the supplier in Holland the amount of
N. fl. _____ (_____ only).It is requested that the invoices, shipping and other documents
presented by the Dutch suppliers be despatched direct
to the _____The suppliers will also be required to furnish to the
Netherlands Investment bank for Developing Countries a Certificate
in duplicate issued/certified by the Netherlands Chamber
of Commerce of the district in which the exporter is
established regarding the Netherlands origin of the goods
covered under the Letter of Authority.Kindly forward the debit advice to the Government of
India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,
Economic Aid (Accounts) Branch, Jeevan Deep, Parliament
Street, New Delhi. This Letter of Authority will remain
valid upto _____

For the President of India,

Copy to _____
(Importer's Bank)They should ensure that the rupees equivalent at the
Composite rate of exchange to be calculated in the manner
prescribed in Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976
and such other Public Notices that may be issued from time
to time together with the interest thereon at the rates pres-
cribed in Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976
from the date of payment to the suppliers to the date of
deposit of the amount into Government Account is deposited
before releasing the original documents to the Importer.

ANNEXURE V

No. F. 14()-WE.III/

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

SUBJECT :—Contract entered under General Purpose Dutch
Credit Reimbursement.

Dear Sirs,

Messrs. _____

(Indian importer)
have entered into a contract with Messrs. _____

(Foreign supplier)

for the supply of _____

for the amount of _____ (_____)

_____) C.I.F./C&F, against Licence
No. _____ dated _____
issued under the Dutch General Purpose Credit for the value
of Rs. _____ (Rupees _____).
_____.)

A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of _____ an
amount of _____ is to be paid as Indian
Agents' Commission in Indian currency. The sum to be
paid to the supplier in foreign currency which will be financed
initially out of the free foreign exchange resources, to be
reimbursed later out of the Dutch General Purpose Credit,
therefore, amounts to _____3. You are authorised to open a letter of credit in favour of
Messrs. __________, though their
bankers, viz. Messrs. _____within a period of thirty days from date of this letter and
against a valid Import Licence, under intimation to the
Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building,
Parliament Street, New Delhi.4. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control
Manual, you are required to ensure that the date of the expiry
of the Letter of Credit is not later than forty-five (45) days
after the final date for shipment as stated in the relative
import licence.5. The letter of credit will also provide that Messrs. _____
(foreign banker)will forward directly to the Controller of Aid Accounts &
Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi, one set of
non-negotiable shipping documents and two copies of the
invoice with a certificate duly endorsed thereon by the Dutch
Supplier that the payment has been received by the latter.They will also obtain from the suppliers and furnish to the
Controller of Aid Accounts & Audit a certificate in duplicate
issued/certified by the Netherlands Chamber of Commerce
of the district in which the exporter is established regarding
the Netherlands origin of the goods covered under the Letter
of credit/*issued by the appropriate competent authority in
regard to the origin of the goods covered under the Letter
of Credit.6. You are also required to forward to the Controller of
Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department
of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street,
New Delhi a certificate of remittance made by you to
M/s. _____against the invoice/shipment of goods, excluding Bank
charges, if any.

7. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

*To be deleted if not applicable.

Copy with a copy of the contract forwarded to :—

Reserve Bank of India, Exchange Control Department, Bombay-1.

2. Copy also forwarded for information to :—

(i) _____
(Indian importer)

It may be ensured that M/s. _____
(foreign banker)

forward one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him, and two copies of certificate in regard to origin of goods to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(ii) M/s. _____
(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice, two copies of the invoice with a certificate duly endorsed thereon by the supplier that the payment has been received by him and two copies of certificate in regard to origin of goods may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of

Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

(iii) Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEXURE VI

Statement Showing Quarterly Report on Utilisation under Dutch (G.P.) Credit

1. Name of Importer.	
2. No. and date of Import Licence.	
3. Value of Import Licence.	
4. Value of orders placed.	
5. Letter of Authority No. and date.	
6. Amount of Letter of Authority.	
7. Date of Validity of Letter of Authority.	
8. Amount utilised during the Quarter	D.G.
9. Total amount utilised	D.G.
10. Total Amount deposited into Government Account.	Rs.
11. Payment yet to be made during the subsequent quarters.	
12. Surrenders, if any.	

